(1100/RPS/NKL)

1100 hours

(Hon. Speaker *in the Chair*)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, I have given a notice of Adjournment Motion....(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 101, श्री दिलीप साईकिया जी।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): अध्यक्ष जी, शिड्यूल्ड कास्ट्स- शिड्यूल्ड ट्राइब्स के रिजर्वेशन पर हाथ लगाया जा रहा है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : गलत बात मत बोलिए, सरकार नहीं है इसमें।

...(व्यवधान)

(प्रश्न 101)

श्री दिलीप साईकिया (मंगलदाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला पूरक प्रश्न यह है कि बच्चों पर बढ़ते पढ़ाई के दबाव और अभिभावकों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए …(व्यवधान) शिक्षकों पर दबाव की समस्या को कम करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से सरकार ने कौन-कौन से कदम उठाए हैं, क्योंकि आज देश भर में ऐसे कई विद्यालय हैं, जहां पर केवल एक ही शिक्षक ही मौजूद है? …(व्यवधान)

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक: श्रीमन्, पूरे देश भर में…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): मुझे एक मिनट बोलने दीजिए। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, कोई गलत वक्तव्य मत दीजिए। ऐसे नहीं होता है। गलत बात मत कीजिए।

…(व्यवधान)

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक: श्रीमन्, सर्व शिक्षा अभियान के तहत, समग्र शिक्षा अभियान के तहत, पहले जो सर्व शिक्षा अभियान था, माध्यमिक शिक्षा अभियान और अध्यापक शिक्षा – इन तीनों का मिलाकर, समीक्षा के बाद समग्र शिक्षा अभियान बनाया गया।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, मुझे बोलने दीजिए।…(व्यवधान)

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक: श्रीमन्, इसके तहत स्कूलों का उन्नयन, रिहायशी विद्यालयों की स्थापना, परिवहन की सुविधाएं दिलाना, मुफ्त वर्दी, मुफ्त पुस्तकें, सामुदायिक प्रबन्धन समिति का प्रशिक्षण, पुस्तकालय, समग्र विद्यालय अनुदान, प्री-नर्सरी को सहायता देना, लड़कियों को आत्म रक्षा सिखाना, खेल आदि हर क्षेत्र में राज्य सरकारों को मदद दी जा रही है। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपकी कोई बात अंकित नहीं हो रही है।

…(व्यवधान)

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक: श्रीमन्, जहां तक स्कूल में शिक्षकों की भर्ती का प्रश्न है, यह राज्य सरकारों से संबंधित विषय है। उनको बार-बार कहा गया है कि जो भी पद उनके यहां रिक्त हैं, उनको शीर्ष प्राथमिकता पर भरा जाए। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मेरी बात सुनिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अगर आप बोलना चाहते हैं तो मेरी बात सुनिए। आप प्रश्न काल को चलने दीजिए। शून्य काल में आपका विषय लेंगे और सरकार की तरफ से माननीय रक्षा मंत्री जी जवाब देंगे।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नहीं, प्रश्न काल में नहीं। गलत परम्परा मत बनाइए। कभी ऐसे चर्चा नहीं हुई। मैं आपको शून्य काल में मौका दूंगा।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह गलत बात है।

…(व्यवधान)

श्री दिलीप साईकिया (मंगलदाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा है, सर्व शिक्षा अभियान को अभी सर्व स्पर्शी बनाने की दिशा में कम्प्यूटर शिक्षा को छठीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक देने का प्रावधान रखा गया है। क्या टीचर और टेक्नोलॉजी का एकीकरण करके, सभी स्तरों पर गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए कम्प्यूटर शिक्षा को प्राथमिक स्तर पर शुरू करने का सरकार का कोई विचार है? असम में हजारों टीचर्स हैं, जिनकी सर्विस अभी तक रेगुलराइज नहीं हुई है। उनको रेगुलराइज करने, या जब तक उनको रेगुलराइज नहीं किया जाता है, तब तक उनकी सर्विस खत्म नहीं की जाएगी, क्या मंत्री जी की ओर से ऐसा कोई प्रावधान रखा गया है?

(1105/IND/KSP)

…(व्यवधान)

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक: श्रीमन्, पहले कम्प्यूटर एडेड लर्निंग कार्यक्रम था, जिसके लिए प्रत्येक जिले को 50 लाख रुपये उपलब्ध कराए जाते थे। इस समय उसे और व्यापक बनाने के लिए और हर बच्चा कम्प्यूटर शिक्षा से जुड़ सके, ई-लर्निंग के तहत अब प्रत्येक स्कूल को 6 लाख 40 हजार रुपये कम्प्यूटर लैब की स्थापना के लिए स्वीकृत किए जा रहे हैं, जबकि 2 लाख 40 हजार रुपये पांच वर्ष तक के लिए रेगुलर स्वीकृत हो रहा है।…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): अध्यक्ष जी, यह सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति के खिलाफ अन्याय कर रही है। यह संविधान के खिलाफ है और मौलिक अधिकारों का हनन है।…(व्यवधान)

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक: श्रीमन्, ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड के तहत भी अभी तक हजारों स्कूल में स्मार्ट क्लासेस शुरू की जा रही हैं तथा स्वयं एवं स्वयंप्रभा के तहत और दीक्षा के तहत इसको किया जा रहा है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय रक्षा मंत्री जी, क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं?

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : रक्षा मंत्री जी बोलना चाहते हैं।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, मेरी बात रिकॉर्ड नहीं हो रही है, मुझे भी बोलने दीजिए।

रक्षा मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): अध्यक्ष महोदय, इस देश की सर्वोच्च न्यायपालिका – सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 'रिजर्वेशन इन प्रमोशन' के मुद्दे पर एक जजमेंट दिया है। यह मामला बहुत ही संवेदनशील है। मैं सभी सम्मानित सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस संबंध में हमारे सामाजिक न्याय मंत्री जी यहां पर आकर स्टेटमेंट देने वाले हैं, तब तक सदन की कार्यवाही को ठीक तरीके से चलने दें। सामाजिक न्याय मंत्री यहां पर आएंगे और स्टेटमेंट देंगे। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: ठीक है। आपने अपनी बात कह दी, उन्होंने अपनी बात कह दी है।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, मेरी बात रिकॉर्ड नहीं हुई है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपकी बात रिकॉर्ड हो गई।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): रिकॉर्ड नहीं हुई है। …(व्यवधान) सर, मेरी बात रिकॉर्ड नहीं हुई है।…(व्यवधान) मुझे दो मिनट का समय दीजिए।

माननीय अध्यक्ष : श्री रमेश चन्द्र कौशिक जी।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, मेरी बात रिकॉर्ड नहीं हुई है।…(व्यवधान) मुझे दो मिनट का समय दीजिए। …(व्यवधान) एक दफा मेरी बात भी रिकॉर्ड हो जानी चाहिए। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजें। आप एक मिनट मेरी बात सुनिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सदन के अंदर मैंने कभी भी आपको किसी विषय पर बोलने से नहीं रोका, लेकिन आप सभी माननीय सदस्यों ने तय किया था कि हम प्रश्न काल के बाद शून्य काल में इस विषय को उठाएंगे। शून्य काल में आप विषय उठाएं, मैं आपको विषय पर बोलने दूंगा और सरकार की तरफ से सामाजिक न्याय मंत्री जी अपना वक्तव्य देंगे, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। उसके बाद भी अगर आपको चर्चा करनी हो तो आप नियम-प्रक्रिया के तहत नोटिस दीजिए, यही संसद की प्रक्रिया है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट रुकिए, सुरेश जी।

आप सभी वरिष्ठ सदस्य हैं, क्यों इस संसद की गरिमा को खत्म करना चाहते हैं?

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: संविधान खतरे में नहीं है, लेकिन इस तरीके से आप सदन की मर्यादा को खतरे में डाल रहे हैं। यह बात गलत है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सुरेश जी, शून्य काल में इस विषय पर बोलें। एडजर्नमेंट मोशन तो प्रश्न काल के बाद आएगा।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऐसा क्यों करते हैं? मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा। आप अपना विषय रखना। सरकार की तरफ से मंत्री जी वक्तव्य देंगे, सदन चलेगा।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। राजनाथ सिंह जी बोल रहे हैं, मुझे भी दो मिनट के लिए बोलने दीजिए।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय राजनाथ सिंह जी ने केवल कहा है कि ऐसा वक्तव्य देंगे, उन्होंने जवाब नहीं दिया। जवाब देने से पहले मैं आपको बुलाऊंगा, उसके बाद सरकार जवाब देगी। पहले आपका

सवाल होगा, उसके बाद सरकार जवाब देगी। सिस्टम यही है कि पहले आपका सवाल होगा, उसके बाद सरकार जवाब देगी। आपको शून्यकाल में बोलने का अवसर देंगे।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपकी बात को रिकार्ड में लाएंगे। माननीय सदस्य, आपको शून्य काल में बोलने का मौका देंगे। शून्य काल में आपको इस सब्जेक्ट पर बोलने का मौका दिया जाएगा।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप मेरी बात सुनिए। माननीय रक्षा मंत्री जी ने कोई वक्तव्य नहीं दिया है। सदन शांति से चले, इसलिए उन्होंने केवल उठकर यह कहा है कि सरकार आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए इस पर वक्तव्य देना चाहती है।

(1110/ASA/KKD)

अगर उन्होंने कोई वक्तव्य देना होता तो मैं पहले आपको बुलाता, उसके बाद सरकार वक्तव्य देती। यह सिस्टम है।

…(व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, he knows the subject matter. He is the most responsible Minister …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : वह इस सदन के उप नेता हैं। सदन के उप नेता कभी भी किसी भी विषय पर वक्तव्य दे सकते हैं। आप नियम प्रक्रिया की किताब में देखिए। आप वरिष्ठ नेता हैं।

…(व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): That is why we are raising it. He knows the subject matter …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको भी विषय पर बोलने दूंगा। बालू जी, आपका विषय आज लेना है न। बैठे-बैठे मत बोलिए।

…(व्यवधान)

(इति)

(प्रश्न 102)

डॉ. रामशंकर कठेरिया (इटावा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने विस्तार से प्रश्न का उत्तर दिया है। देश भर में श्रमिकों की जो कई तरह की बड़ी-बड़ी समस्याएं थीं, उन समस्याओं के समाधान की दिशा में पिछले 6 साल से सरकार का जो एक सकारात्मक प्रयास रहा है, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी समस्याएं, आज भी श्रमिकों के साथ …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप सभी जिम्मेदार माननीय सदस्य हैं। मैं किसी माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी को रोकना नहीं चाहता। लेकिन सदन के अंदर प्रश्न काल सबसे महत्वपूर्ण काल है। सभी माननीय सदस्यों ने यह व्यवस्था दी है कि प्रश्नकाल के बाद जो भी विषय होगा, हम प्रश्न काल के बाद अपने विषयों को उठाएंगे। सभी माननीय सदस्यों का मानना है कि प्रश्न काल सबसे महत्वपूर्ण काल है, इसलिए आप अपना प्रश्न संक्षेप में पूछें। मुझे पूरी लिस्ट रोज पूरी करने का प्रयास करना है।

डॉ. रामशंकर कठेरिया (इटावा): माननीय अध्यक्ष महोदय, बाहरी स्रोत से ली जाने वाली जो सेवाएं हैं, उन सेवाओं के द्वारा जो लोग लगाए जाते हैं और राज्य का जो श्रम विभाग है, उनके अनुसार दैनिक रेट से जो भुगतान किया जाता है, जैसे दिल्ली में सफाई कर्मचारियों को महीने में लगभग 14842 रुपये का भुगतान बनता है और उसमें से 1781 रुपये ईपीएफ के लिए और 111 रुपये ईएसआई के लिए कटते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली इन तीनों बातों में कठिनाइयां आती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसमें प्रॉपर पैसा उसको मिले और उसका जो पैसा कटता है, वह भी उसके खाते में जाए। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसमें कहीं-कहीं जो शिकायतें आती हैं, उन शिकायतों के समाधान की दिशा में माननीय मंत्री जी की तरफ से क्या कोशिशें हो रही हैं?

श्री संतोष कुमार गंगवार: माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, उनकी वह बात दुरुस्त है। इसीलिए हमारी सरकार ने इस दिशा में विशेष कदम उठाए हैं। आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने वर्ष 2014 के बाद श्रम कानूनों में जो परिवर्तन की बात की थी, उसी का परिणाम यह है कि हम 44 कानूनों को चार कोड्स में बदल रहे हैं। पहला कानून कोड ऑन वेजेज अभी पिछले सत्र में ही सदन ने पास किया है। इससे इन सारी समस्याओं को हम हल करने का काम करेंगे और हमारा मानना है कि जो शिकायतें आप बता रहे हैं, उनका एक सही समाधान भी होगा। मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो भी शिकायतें हमारे पास आ रही हैं, चाहे वे जिस स्तर की आ रही हैं, हम केवल संगठित मजदूर जो 8 करोड़ हैं, उनकी हम चिंता नहीं कर रहे हैं, 50 करोड़ मजदूरों की चिंता हमारी सरकार कर रही है और उनकी हर समस्या का समाधान हम टाइम-बाउंड तरीके से करने का काम कर रहे हैं कि कैसे कम से कम समय में समस्या का समाधान हो। अगर किसी की कोई स्पेसिफिक समस्या हो तो माननीय सदस्य अगर हमें बताएंगे तो हम उसका समाधान करने का काम करेंगे।

डॉ. रामशंकर कठेरिया (इटावा): माननीय अध्यक्ष जी, जो आउटसोर्सिंग है, हम देख रहे हैं कि धीरे-धीरे बहुत बड़ी संख्या में, सभी क्षेत्रों में, चाहे सरकारी हो या गैर-सरकारी हो, हम धीरे-धीरे आउटसोर्सिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन उनमें उसी तरह की समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं।

(1115/RAJ/RP)

मैंने कई जगह ऐसा देखा है कि कभी-कभी किसी बड़ी फैक्ट्री जो गेट पास में दिए जाते हैं, वे गेट पास उनको एक महीना के बाद तब दिए जाते हैं जब उसमें कटौती हो जाती है। इसे रोकने के लिए माननीय मंत्री जी की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं?

आउटसोर्सिंग में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्या माननीय मंत्री जी की तरफ से, सरकार की तरफ से इसमें रिजर्वेशन की व्यवस्था पर कोई विचार किया जा रहा है?

श्री संतोष कुमार गंगवार: सर, माननीय सदस्य ने आउटसोर्सिंग की बात कही है। हमारी सरकार ने इस ओर चिंता की है और एक टाइम बाउंड कार्य की बात की है। इसलिए एक साल, दो साल या तीन साल, जितने समय के लिए नौकरी होगी, वह निश्चित होगी और उसमें सारी समस्याओं का समाधान होगा। जहां तक इसमें आरक्षण का प्रश्न है, तो मैं अभी उसके उपर टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, संबंधित मंत्री महोदय से बात करके बताऊंगा।

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): सर, धन्यवाद। यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। In 2016, a number of complaints had been registered during 2016-19 under EPFiGMS, that is a Grievance Management System. The number was 2,36,005. In the year 2019, it has come to 9 lakh. That means, several lakhs of petitions have been registered. The matter is regarding the PF and the pension. The rate of disposal, according to your answer, is around 90 per cent plus.

You are imposing online submission of application. As far as the poor cashew workers and the traditional workers are concerned, they are illiterate. They are not able to submit their applications online. It is very difficult for them. Now, it is becoming mandatory. Therefore, the poor people are not able to submit their applications through online portals in cities.

I would like to know from the hon. Minister whether this will be reviewed so that the poor people can submit their applications offline. The hon. Minister has assured in this august House that after realisation of the entire commuted pension, the original pension will be restored. The Government and the EPF trustees have decided this. But, unfortunately, so far, no order has been issued in this regard by the EPF Commissioner. It has not been issued after months. I would like to know whether the EPF Commissioner or the Chief Provident Fund Commissioner is the highest authority or the Government and the Minister is the highest authority. The poor worker whose pension has been deducted since

long has not been restored. It means, it is an anti-labour approach on the part of the Central Provident Fund Commissioner.

I would like to know from the hon. Minister when the order will be issued in this regard so that the poor workers will be satisfied. These are two parts of my supplementary.

श्री संतोष कुमार गंगवार : सर, यह कम्पलसरी नहीं है कि ऑनलाइन शिकायत करें, जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं, अगर वे हार्ड कॉपी पर या हमारे मोबाइल पर भी शिकायत कर देंगे तो उसकी सुनवाई होगी, उसका निस्तारण होगा। हमारा यह मानना है कि उनकी समस्याओं का निस्तारण विदइन टाइम हो और टाइम लिमिट कम से कम हो। इसलिए इसमें कोई वजह नहीं है कि ऑनलाइन ही शिकायत करें। It is not necessary. He can make his complaint by any way which he likes.

जहां तक पेंशन का सवाल है तो माननीय सदस्य इसके अच्छे जानकार हैं, मैं इनके साथ अलग से बात करके इसका समाधान करूंगा और इसको दुरुस्त करने की दिशा में जल्दी कदम उठाऊंगा।

SHRI FEROZE VARUN GANDHI (PILIBHIT): Sir, the domestic workers have traditionally been one of the most exploited communities in our country. My question relates to breach of the National Wage Guidelines by domestic employers. Through you, I would like to ask the hon. Minister whether workers have any grievance redressal mechanism towards their protection in this regard.

श्री संतोष कुमार गंगवार : सर, डोमेस्टिक वर्कर्स की समस्या होती है, हमारी जानकारी में है। अब इसीलिए सरकार ने, आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने आठ करोड़ नहीं, बल्कि 50 करोड़ वर्कर्स की चिंता की बात की है। हमारी सदन ने कोड ऑन वेजेज पास किया है। ऐसी कोई भी समस्या होगी, शिकायत होगी, उसका तुरंत समाधान किया जाएगा। अगर माननीय सदस्य की जानकारी में कोई स्पेसिफिक समस्या है, वह उसके बारे में बताएंगे तो हम तुरंत उसका निस्तारण करने का काम करेंगे।

श्री विनायक भाउराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): अध्यक्ष महोदय, भारत के मजदूरों के बारे में देखा जाए तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। खासकर, प्रोविडेंट फंड के कंट्रीब्यूशन और ईएसआईसी की समस्या है।

(1120/VB/RCP)

महोदय, सबसे बड़ी समस्या यह है कि जहाँ कांट्रैक्चुअल वर्कर्स रहते हैं, वहाँ बहुत-से ठेकेदार वर्कर्स का कंट्रीब्यूशन इकट्ठा करते हैं और उसे प्रोविडेंट फण्ड में जमा करते हैं, लेकिन मालिक का जो शेयर होता है, वह डिडक्ट करके जमा नहीं किया जाता है।

कांट्रैक्चुअल सिस्टम में एक ठेकेदार का मुद्दत खत्म होने के बाद जब दूसरा ठेकेदार आता है, तो उनकी जो कंटिन्यूटी होनी चाहिए, वह भी बहुत-सी जगहों पर नहीं हो रही है, खासकर के मुम्बई, दिल्ली के एयरपोर्ट्स पर, जहाँ बहुत-से कांट्रैक्चुअल वर्कर्स काम करते हैं।

मेरी आपके माध्यम से मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि कांट्रैक्चुअल वर्कर्स को भी ईपीएफ और ईएसआइसी की सहायता मिलनी चाहिए। हालाँकि, आपने उसके लिए डाटा-बेस पोर्टल तैयार की है, लेकिन उसके ऊपर सही तरीके से ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार इसके लिए गम्भीर है, ऐसा आपने बताया है, फिर भी इसमें और सुधार करने के लिए आपने क्या प्रावधान किए हैं?

श्री संतोष कुमार गंगवार : माननीय अध्यक्ष जी, इसमें जो भी सुधार हो सकता है, उसका समाधान भी किया जाएगा। सरकार की चिन्ता है कि यह ब्रेक न हो, अगर ठेकेदार बदलता है, तो मजदूर को नुकसान न हो, यह हमारी चिन्ता का विषय है। अगर मजदूर हमें सीधे रूप से लिखकर देता है, तो हम उसका समाधान भी करेंगे और अगर आपके संज्ञान में किसी क्षेत्र विशेष की कोई स्पेसिफिक शिकायत है, उसके बारे में आप हमें बताएंगे, तो हम पूरी तरह से आपको संतुष्ट करने का काम करेंगे।

(इति)

(प्रश्न 103)

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस्पात मंत्रालय के पीएसयू सेल से यह जानना चाहा था कि सेल के पास कितने कैश रिज़र्व्स, सरप्लस और बैंक फण्ड्स हैं।

माननीय अध्यक्ष: आपने प्रश्न पूछ लिया है, आप आगे पूछें।

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): सर, मैं वही पूछ रहा हूँ।

मुझे जो उत्तर दिया गया है, उसमें केवल कैश सरप्लस की ही जानकारी दी गई है। यह कहा गया है कि वर्ष 2011-12 में कैश सरप्लस 13 हजार करोड़ रुपये थे, परन्तु सेल का कहना है कि वर्ष 2015 के बाद सेल के पास कोई कैश सरप्लस फण्ड है ही नहीं।

मेरा प्रश्न यह है कि सेल के कैश सरप्लस फण्ड का क्या हुआ और क्या सेल के पास कोई फण्ड है ही नहीं?

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : माननीय अध्यक्ष जी, स्थिति ऐसी ही है। यह विषय स्टील के बाजार भाव से जुड़ा हुआ है। वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 तक स्टील सेक्टर की अपवर्ड जर्नी के कारण उस समय सेल के पास थोड़ी बचत हुई थी। वह कैसे किया गया है, इस संबंध में आपके माध्यम से उत्तर सभा-पटल पर रखा गया है। फिलहाल आज सेल के पास कोई कैश सरप्लस नहीं है।

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): महोदय, मैंने आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहा था और सेल ने बताया है कि इनवेस्टमेंट्स उन बैंक्स में रखे गए हैं, जहाँ उसको सबसे ज्यादा इंट्रेस्ट रेट मिलते हैं। परन्तु, सेल ने यह नहीं बताया कि इन बैंक्स में सेल के द्वारा जो इनवेस्टमेंट्स किए गए हैं, उन पर उसको कितना इंट्रेस्ट रेट मिलता है? केवल राशि बता दी गई है, लेकिन रेट ऑफ इंट्रेस्ट नहीं बताया गया है। मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: हम माननीय सदस्य को वह भी बता देंगे।

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के जवाब से पूर्णत: संतुष्ट हूँ।

माननीय अध्यक्ष: ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): सर, यह मेरे क्षेत्र का प्रश्न है।

कुमारबाग स्टील प्लांट के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर के सामने मंत्री जी ने कहा था कि अगर वहाँ पर रेक पॉइंट बन जाए, तो हम कुमारबाग यूनिट को पूर्ण रूप से चालू करेंगे और वहाँ के एम्प्लॉइज को परमानेंट करेंगे। कुमारबाग में माननीय रेल मंत्री जी के द्वारा रेक पॉइंट का निर्माण हो गया है। उन्होंने कहा था कि तीन हजार रुपये प्रति टन एक्स्ट्रा खर्च है, वह भी बच गया है, इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि कुमारबाग प्लांट को 100 परसेंट कब तक चालू करेंगे और वहाँ के एम्प्लॉइज को कब तक एडजस्ट करेंगे?

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक अलग प्रश्न है, मैं माननीय सदस्य से इस विषय के बारे में चर्चा करूँगा।

SHRI M. K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): Sir, there is a Joint Venture company of SAIL, namely SAIL-SCL Kerala Limited (SSKL) in my constituency, Kozhikode. For the revival of this company, a meeting was held by the Ministry of Steel on 30.06.2017. Various measures including provision of material and financial assistance was discussed. Unfortunately, however, no effective measure to revive this company has been forthcoming so far.

I would like to know from the hon. Minister the steps being taken to revive this company which will give employment opportunity to over 200 persons both directly and indirectly.

(1125/PC/SMN)

SHRI DHARMENDRA PRADHAN: Sir, this is a separate question but with your permission, I would like to answer this specific query. It is not a fact that the Government has not taken any step to revive that plant. Recently, the Chairman of Steel Authority of India, at the invitation of the hon. Chief Minister of Kerala, has visited Kerala. They had a very detailed discussion.

Today, the raw-material is little bit costly. The landing cost is higher in Kerala. The private sector is more competitive to supply to the Kerala market. We have asked some assurance from the Kerala Government for the off-take guarantee. In that way, the Government of India is keen to run that plant and the Government of Kerala is in consultation on that issue.

I hope if that competitiveness will come, we can run that plant.

(ends)

(प्रश्न 104)

श्री अजय निषाद (मुजफ्फरपुर): माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने विस्तार से अच्छा उत्तर दिया है, मंत्री जी का आभार।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इंजीनियरिंग शिक्षा को और उन्नत बनाने हेतु बी. आर. मोहन रेड्डी समिति की मुख्य संस्तुतियां क्या थीं?

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक: श्रीमन, जो समिति गठित की गई थी, उस बी. आर. मोहन रेड्डी समिति ने दिनांक 27 दिसंबर, 2018 को जो मुख्य संस्तुतियां दी थीं, उनमें था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कोर्स सुनिश्चित किया जाए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को सुनिश्चित किया जाए, क्वॉन्टम कम्प्यूटिंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी सहित जो दस-बारह प्रमुख संस्तुतियां थीं, उनमें दूसरी महत्पवपूर्ण संस्तुति थी कि पारंपरिक विषयों में सीट कम कर के मौजूदा सीटों को इन पाठ्यक्रमों में परिवर्तित कर के अनुशासन पाठ्यक्रमों पर अधिक ध्यान देना, एआईसीटीई इनको अन्य पाठ्यक्रमों के आधार पर सुनिश्चित करे, यह प्रमुख रूप से उनकी संस्तुतियां थीं।

श्री अजय निषाद (मुजफ्फरपुर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि दिव्यांग छात्रों और जम्मू-कश्मीर के छात्रों को तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने के लिए क्या सरकार कोई छात्रवृत्ति दे रही है?

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक: श्रीमन, मुझे आपके माध्यम से सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की शिक्षा पर सरकार ने विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया है।

कुछ दिन पूर्व 45 नई योजनाओं को वहां शुरू किया गया है। जम्मू-कश्मीर के छात्रों को विशेषकर प्रधान मंत्री विशेष पैकेज के तहत छात्रवृत्ति दी जाती है। मेडिकल के छात्र को चार लाख रुपये तक और इंजीनियरिंग के छात्र को तीन लाख रुपये तक की छात्रवृत्ति दी जाती है।

माननीय सदस्य ने दिव्यांगों के बारे में जो चर्चा की है, दिव्यांगों के लिए भी विशेष रूप से सुविधाएं दी जाती हैं और उनको छात्रवृत्ति के साथ-साथ अलग से तमाम प्रकार की सुविधाएं देने का प्रावधान है।

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Hon. Speaker, as we know today unemployment is a serious crisis facing our technical sector. Sixty-four per cent of our fresh graduates of age 20 to 24 have no work. This is a major crisis facing the country and engineering is particularly bad because you are looking at a situation where even among those who get jobs, 65 per cent end up in jobs that do not require an engineering degree. So, the question is this. When the AICTE was first setup, it had a mandate of promoting technical education with a view to the development of the country.

When we look at the latest World Bank Report, technology is reshaping the skills needed for work in the technical space. There is a demand for

advanced cognitive skills, socio-behavioural skills, skill combination associated with greater adaptability, and of course, you already mentioned Mr. Minister about innovation, automation, internet of things, cyber-studies, and so on.

The question is what is the AICTE doing to amend its very strict regulatory approach asking how many classrooms, how many teachers, what syllabus, and moving into a situation where we can instill the skills that will help our technical graduates to actually get employment in today's difficult market?

(1130/SPS/MMN)

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक: श्रीमन्, मैं यह समझता हूं कि बीते पांच सालों में हमारी गवर्नमेंट ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। ए.आई.सी.टी.ई. के माध्यम से जो छात्र वहां तक पहुंचा है, उसको पूरी ताकत के साथ एक योद्धा के रूप में वर्तमान परिस्थितियों से मुकाबला करने के लिए कैसे तैयार किया जाए और उसको किस तरीके से रोजगारपरक बनाया जाए, इसके लिए हमने नए मॉडल तैयार किए हैं। इसमें परिणाम आधारित मॉडल पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। इस पाठ्यक्रम को उद्योगों के साथ जोड़कर ताकत के साथ लागू करेंगे। छात्रों के लिए अनिवार्य इंटर्नशिप कर दी गई है। इसमें छात्र छ: महीने तक अनिवार्य रूप से उद्योगों के साथ जुड़कर काम करेंगे। हमने छात्रों को प्रेरित करने और छात्रों की कांउसलिंग के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम शुरू किए हैं। परीक्षा में क्या-क्या सुधार हो सकता है, उस पर भी पूरा ध्यान केन्द्रित किया गया है। तकनीकी शिक्षा के लिए अलग परिप्रेक्ष्य में जो उद्योग हैं, पाठ्यक्रम हैं और छात्र के बीच भी समन्वय रहे, ताकि वह जो भी शिक्षा प्राप्त करता है, उससे वह वहां तक पहुंचे जहां उसकी योग्यता है।

श्रीमन्, इसके लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण बहुत जरूरी है, इसलिए शिक्षकों का प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। जब भी नए प्रवक्ता आते हैं, तो उनके लिए चार सप्ताह की अनिवार्य ट्रेनिंग सुनिश्चित की गई है। जो अध्यापक वहां पढ़ा रहे हैं, उनको अत्याधुनिक तकनीकी के साथ नया प्रशिक्षण रेगुलर दिया जाए, ताकि वह बच्चे को पूरी ताकत के साथ तैयार कर सकें। हमने स्टार्ट अप प्रोग्राम शुरू किए हैं और उनके बहुत अच्छे परिणाम भी निकले हैं।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): सर, मंत्री जी अद्भुत उत्तर देते हैं। मैं आज प्रत्यक्ष रूप से इनके उत्तर पोर्टल पर देख रहा था। वहां अभी तक प्रश्नों का उत्तर मिलता था, लेकिन आज इनके पोर्टल पर सभी सप्लीमेंट्रीज, जो इनके विभाग ने तैयार करके दिए थे, वे भी उपलब्ध थे। इससे हम सब लोगों का ज्ञान बढ़ता है और हमें ज्यादा कठिन सवाल पूछने के लिए रास्ता दिखेगा।

माननीय अध्यक्ष: आप पोर्टल पर सवाल पूछ लेना।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): महोदय, पूरे भारतवर्ष में चिंता का विषय है कि पूरे भारत में 15 लाख इंजीनियरिंग की सीट्स हैं। महादेय, फिर से आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से कहना चाहता हूं, क्योंकि आप कोटा से हैं और कोटा शिक्षा के क्षेत्र में विश्व में जाना जाने वाला स्थान है, जहां से बच्चे पढ़कर सभी आई.आई.टीज. में जाते हैं। इन 15 लाख सीट्स में से 7.5 लाख सीट्स खाली हैं। यह इतना बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर है, जो पूरे भारतवर्ष में बना है। यह प्रत्यक्ष रूप से मंत्री जी के उत्तर में भी है

कि 7.5 लाख सीट्स खाली हैं। पिछले वर्ष जो 7 लाख 90 हजार के आस-पास बच्चे आए हैं, उनमें से मात्र 3 लाख 60 हजार बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पूरे भारतवर्ष में जो ए.आई.सी.टी.ई. के कॉलेजेज खाली पड़े हैं, वे अरबों-खरबों रुपये का निवेश करने के बाद भी खाली पड़े हैं। उस संरचना का उपयोग करने के लिए क्या किसी और रूप से स्किल कोर्सेज के लिए अनुमति देने के प्रावधान के साथ-साथ, जो पिछली बार ए.आई.सी.टी.ई. ने 1 लाख 60 हजार सीटें गुणवत्ता के आधार पर अपने आप कम की हैं, उनके लिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या ए.आई.सी.टी.ई. के कॉलेजेज बंद होने के कारण जो स्पेयर इन्फ्रास्ट्रक्चर इस देश में उपलब्ध हुआ है, उसके उपयोग के लिए सरकार के विवेक में कोई ऐसा निर्णय है और क्या इसकी क्वालिटी बढ़ाकर इसमें अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सकता है? क्या निचले स्तर के स्किल से जोड़कर 10वीं, 12वीं, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग की कोई ऐसी व्यवस्था है कि वे 8वीं में स्किल प्राप्त करें, 10वीं में स्किल प्राप्त करें, डिप्लोमा भी प्राप्त करें और आई.एस.सी. करने के बाद डिप्लोमा करें, फिर डिप्लोमा के पश्चात इंजीनियरिंग में जाए? अगर इस प्रकार की व्यवस्था भारतवर्ष में कायम हो सकती है तो शायद इतनी बढ़ी संख्या में भवन और इन्फ्रास्ट्रक्चर खाली नहीं रहेंगे। क्या ए.आई.सी.टी.ई. स्किल मंत्रालय के साथ मिलकर कोई इंटीग्रेशन का प्रस्ताव लाएगी, ताकि यह पूरी व्यवस्था जिसमें 7.5 लाख सीटें खाली हैं, जिसमें व्यवस्था और इन्फ्रास्टक्चर उपलब्ध है, उसका उपयोग हो सके? मैं माननीय मंत्री जी से नीतिगत तौर पर इस सवाल का उत्तर जानना चाहूंगा।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक: श्रीमन्, माननीय सदस्य ने जो 8वीं, 10वीं,12वीं के साथ नवाचार की शिक्षा नई प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ने के लिए कहा है, उसके लिए नई शिक्षा नीति का जो नया मसौदा ला रहे हैं, उसमें हम इसको समाहित कर रहे हैं।

(1135/MM/VR)

लेकिन जहां तक आपने कहा है, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए भी हमने यह सुनिश्चित किया है कि कोई न कोई इंजीनियरिंग कॉलेज किसी एक विषय को लेकर उसके शिखर तक पहुंचे और जिनका स्तर अच्छा नहीं है, स्वाभाविक है कि वे प्रतिस्पर्द्धा में नहीं आ पाएंगे, इसलिए वही इंजीनियरिंग कॉलेज अब जिंदा रहेंगे जो उद्योगों के साथ मिलकर नये पाठयक्रम, नवाचार के साथ, नई प्रोद्योगिकी के साथ मिलकर उस छात्र को रोजगार की दिशा में खड़ा करने के लिए सक्षम होंगे और इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है।

श्री जयंत सिन्हा (हज़ारीबाग): बहुत-बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से संक्षेप में एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं खुद एक इंजीनियर हूं। आईआईटी की एजुकेशन में और हमारे जो सब इंजीनियरिंग इंस्टीटयूट्स हैं, उनमें एआईसीटीई का योगदान काफी रहा है। लेकिन इम्प्लॉयबिलिटी का जो क्राइसिस है, जिसका माननीय शशि थरूर जी और माननीय रूडी जी ने जिक्र किया है कि उनमें सॉफ्ट स्किल्स और लीडरशिप स्किल्स भी अत्यंत जरूरी हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि एआईसीटीई का जो क्यूरिकुलम है, उसकी डेवलपमेंट के लिए सॉफ्ट स्किल्स पर क्या आपने ध्यान दिया है?

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : श्रीमन, निश्चित रूप में ध्यान दिया है। जैसा मैं पहले भी अवगत करा चुका हूं कि उद्योगों के साथ मिलकर, अभी क्या था कि छात्र कुछ पढ़ रहा है और आवश्यकता कुछ और है। आवश्यकता और उसके अध्ययन के बीच का जो सेतु था, उसको मिलाने की कोशिश हमने की है। इसीलिए उद्योगों के साथ मिलकर पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। जो भी छात्र पढ़ेगा, उसमें वह 50 प्रतिशत उद्योगों के साथ काम करेगा, 50 प्रतिशत प्रेक्टिकल होगा और 50 प्रतिशत थ्योरिटिकल होगा। इससे निश्चित रूप से उद्योगों का आधार भी बढ़ेगा और उसकी लाइन भी तय होगी।

(इति)

(Q.105)

SHRIMATI VANGA GEETHA VISWANATH (KAKINADA): Thank you, Sir. I am very happy and not only me but all of us are very happy by the answer given by the hon. Minister that between 2015-16 and 2018-19 there has been a gradual decrease in the number of drop-out students. It is a happy news.

But I would like to know from the hon. Minister what the major reasons are for drop-out of students from IIT and IIM colleges and what steps the Government is taking to prevent this.

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : श्रीमन, विशेषकर आईआईएम और आईआईटी में जो छात्र बीच में छोड़कर जाते हैं, एक तो वे तनाव में होते हैं और तनाव के कारण जब पाठ्यक्रम का बोझ पड़ता है तो उसके कारण वे छोड़ देते हैं। दूसरा, उच्च शिक्षा में जाने के लिए उनको तमाम प्रकार के अवसर मिलते हैं तो वे वहां भी चले जाते हैं। इसलिए सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि इसके लिए शैक्षणिक प्रगति और सहकर्मी सहायता प्राप्त प्रशिक्षक हों, जो हर संस्थान में परामर्शी होंगे। वे छात्रों के साथ लगातार सम्पर्क रखेंगे और उनका जो तनाव है, जो दबाव है, उसको कम करेंगे। छात्रों के तनाव को कम करने के लिए काउंसलर हर संस्थान में सुनिश्चित किए गए हैं। जब छात्र बी.टेक करने के बाद एम.टेक में जाएगा तो उसके लिए छात्रवृत्ति की तमाम ऐसी सुविधाएं हैं, ताकि वह बीच में छोड़े नहीं। इसकी वजह से बहुत अच्छे रिजल्ट भी आए हैं।

SHRIMATI VANGA GEETHA VISWANATH (KAKINADA): It is not only the responsibility of the HRD Ministry but also of the head of the institution. What role is being played by the head of the institution in this issue?

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : श्रीमन, हम लोगों ने एक लीप प्रोग्राम भी सुनिश्चित किया है। किसी भी आईआईटी, एनआईटी, आईआईएसईआर या आईआईएम के जो निदेशक हैं, उनको उन समस्याओं के समाधान की दिशा में क्या-क्या प्रशासनिक और व्यावहारिक कठिनाइयां आती हैं, इसके लिए एक लीप प्रोग्राम नेतृत्व विकास की क्षमता के लिए अलग से लाया गया है, ताकि छात्रों के बीच बेहतर तरीके से उस संस्थान का जो शीर्ष वाला है, श्रीमन, इसलिए मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि पहले की अपेक्षा बीच में छोड़कर जाने वाले छात्र जो वर्ष 2015-16 में 7.49 प्रतिशत थे, अब गिरकर के 2.82 प्रतिशत रह गए हैं। इस वर्ष तो इसमें और भी कमी आएगी।

(1140/SJN/SAN)

श्री अच्युतानंद सामंत (कंधामल) : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि whether the Government has approved any proposal which will allow the students studying in IITs to opt for B.Sc. (Engineering) in case they are unable to keep pace with the required academic standards.

जो बच्चे आईआईटी में पढ़ते हैं, वह प्रैशर में चले जाते हैं, लेकिन वे बाद में आईआईटी के स्टैंडर्ड में कोप-अप नहीं कर पाते हैं, ऐसे बच्चे ड्राप आउट हो जाते हैं। ऐसे बच्चे ड्राप आउट न हो सकें, उसके लिए पहले आईआईटी में यह रूल था कि बच्चे की काउंसलिंग करके उसको किसी दूसरे कोर्स या बीएससी (इंजीनियरिंग) में पढ़ने के लिए कहा जाता था। लेकिन अभी आईआईटी में वह प्रथा समाप्त हो गई है। क्या मंत्रालय की ऐसी कोई योजना है कि वह उस प्रथा को दोबारा से लागू करे, जिसकी वजह से बच्चे का भविष्य सुरक्षित होगा और ड्राप आउट भी कम हो जाएगा?

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : श्रीमान्, इस साल से यह शुरू कर दिया गया है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, वह बिल्कुल सही है। इसलिए, हम लोगों ने दो प्रकार से किया है। यदि उसको यह लगता है कि वह विभिन्न कोर्सों में या वह जिसके भी अनुरूप फिट बैठ सकता है, एक तो यह किया है। दूसरा यह है कि कैसे उसको सक्षम किया जा सकता है। इसलिए, कैसे उसको अतिरिक्त क्लासेज़ देकर तैयार किया जाए, तो उसको और मदद के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है।

DR. T. SUMATHY (a) THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Hon. Speaker, Sir, the answer given by the hon. Minister regarding the statistics of drop-outs seem to be very convincing, but I would like to ask the hon. Minister, through you, whether he is aware of the suicides committed by the students in the IITs. Recently also, we have had a case in the Chennai IIT. Is the hon. Minister aware of such cases because that also can be considered as drop-outs? I would like to ask the hon. Minister, through you, what steps are taken in such cases. Those cases are testimonial evidence of students being subjected to psychological tensions, either by the academic professor or by the peers. So, I would like to know from the hon. Minister, through you, what his take on these cases is.

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक: श्रीमान्, हालांकि यह इससे जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं है, लेकिन एक ही कारण नहीं है। ऐसी कुछ दुखद घटनाएं घटती हैं, तो उनके अलग-अलग कारण हैं। इसीलिए, मैंने अपने उत्तर में यह कहा है कि जो तनाव है, उसको कम करना है। चाहे किसी भी कारण से उस पर दबाव है, तनाव है, उसको कम करने के लिए जहां हम युद्ध स्तर पर लीव प्रोग्राम कर रहे हैं, वहीं अतिरिक्त शिक्षण का भी कार्यक्रम कर रहे हैं। माननीय सदस्य ने जो कहा है कि यदि उसको दबाव महसूस हो रहा है, तो हम उसको अतिरिक्त पाठ्यक्रमों में भी हिस्सा दे रहे हैं। यह एक अच्छा प्रयोग है।

SHRI GAURAV GOGOI (KALIABOR): Hon. Speaker, Sir, the hon. Minister referred that stress is a very major factor in institutes of higher education. One of the reasons for high level of stress is the cases of sexual harassment and bullying. My question to the hon. Minister is what instructions the Ministry has given to institutions of higher education with respect to monitoring, supervision

and resolution of cases of sexual harassment and bullying. Specifically, we have seen in the recent case in Gargi College how a festival of girl students became a painful episode because so many males entered and harassed the girl students over there. What steps will the Ministry take so that the girls of Gargi College feel safe and reassured?

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक: श्रीमान्, माननीय सदस्य जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं, जैसा कि संज्ञान में आया है कि वे छात्र नहीं थे, कुछ बाहर के लोग वहां घुसे थे, वह भी ठीक नहीं है। इसलिए, उस कालेज के प्रशासन से यह पूछा गया है कि उस पर ध्यान दें।

जहां तक जो बच्चे का तनाव और उसकी समस्याओं का विषय है, हम लोगों ने एक 'दीक्षारंभ' नामक कार्यक्रम शुरू किया है। चाहे वह उच्च शिक्षा में हो, या चाहे तकनीकी शिक्षा में हो, जब भी बच्चा उस परिवेश में जाएगा, तो सबसे पहले पुरातन छात्र उसका परिचय कराएंगे। पुरातन छात्र फिर अध्यापकगण के साथ मिलकर उनको पूरे परिसर के वातावरण से परिचित कराएंगे और उनको जानकारी देंगे। उस छात्र को शुरू से ही यह लगना चाहिए कि हां, मैं जिस संस्थान में आया हूं, वह मेरा है। जो पुराने छात्र हैं, जो उसके सहयोगी हैं और जो अध्यापक हैं, वे उसके मार्गदर्शक हैं। इस साल से हमने 'दीक्षारंभ' नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है। उसमें अद्भुत् प्रकार के परिणाम सामने आए हैं। यदि कोई भी घटना घटती है, तो उसके लिए कड़े से कड़े प्रावधान किए गए हैं और इस समय हमने उनको लागू भी किया है।

(इति)

(प्रश्न 106)

(1145/GG/RBN)

श्री अब्दुल खालेक (बारपेटा): अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने सदन के पटल पर जो जवाब रखा है, वह कनफ्यूज़िंग है। सरकार दावा कर रही है कि जीडीपी में कोई गिरावट नहीं हुई है। लेकिन आईएमएफ द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट 2020 बोल रहा है कि जीडीपी डाउन हुआ है, जो कि 4.8 पर्सेंटेज है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आईएमएफ द्वारा प्रकाशित जो इनफॉर्मेशन है, क्या यह गलत थी या सरकार के दावे गलत हैं?...(व्यवधान)

सर, हम लोग सुन रहे हैं कि ऑटोमोबाइल सैक्टर में स्लाइडिंग ग्रोथ हुई है। लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में क्या हो रहा है, वह भी हम जानना चाहते हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर): माननीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि इस पूरे विषय को बड़े ग्लोबल इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में भी देखना चाहिए। जहां पर वर्ल्ड आउटपुट ग्रोथ, वर्ष 2018 में 3.6 पर्सेंट थी, जो कम हो कर 2.9 पर्सेंट रह गई। एडवांस इकॉनोमीज़ जो बढ़ रही थीं, वर्ष 2018 में 2.2 पर्सेंट से, वह कम हो कर 1.7 पर्सेंट रह गई। जो इमर्जिंग मार्केट्स और डेवल्पिंग इकॉनोमीज़ थीं, वे 4.5 पर्सेंट से कम हो कर वर्ष 2019 में 3.7 पर्सेंट रह गईं। वहीं पर हम भारत में अगर देखें तो आईएमएफ ने कहा था कि 4.8 प्रतिशत की ग्रोथ इस वर्ष रहेगी, जो लगभग अभी पांच प्रतिशत के लगभग अनुमानित है। अगले वर्ष के लिए भी जो कॉन्फिडेंस दिखाया है, आईएमएफ ने भी, वह लगभग छह प्रतिशत का है। हमारे आरबीआई ने भी उसको छह पर्सेंट और इकॉनोमिक सर्वेयरिस्ट ने उसको छह से साढ़े पर्सेंट की ग्रोथ कही है। उसके पीछे बड़ा कारण है, जो भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं, चाहे वह इन्सॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड की बात हो, जीएसटी की बात हो या बाकी एनबीएफसीज़ के लिए कदम उठाए गए हों या बैंकों के मर्जर्स की बात हो, ये सारे कदम उस दिशा में हैं, जहां पर हमारी विकास दर बढ़ सके। मुझे कहते हुए प्रसन्नता भी हो रही है, अगर आप ग्रीन शूट्स की ओर देखेंगें तो इंडस्ट्रीज़ के आठ में से पांच कोर सैक्टर्स जो हैं, उनमें पॉज़िटिव ग्रोथ है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। दिसंबर, 2019 में कोल लगभग 6.1 पर्सेंट, सीमेंट 5.5 पर्सेंट, स्टील 1.9 पर्सेंट, फर्टिलाइजर 10.2 पर्सेंट, रिफाइनरी 3.0 पर्सेंट है।

अध्यक्ष जी, यही नहीं इसके अलावा भी जो आंकड़े दिखाते हैं, उनमें भारत में एफडीआई भी लगातार बढ़ी है। अप्रैल से नवंबर, 2018 में नैट एफडीआई 21.2 बिलियन यूएस डॉलर्स थी। जो अप्रैल से नवंबर, 2019-20 वाले वित्तीय वर्ष में 24.4 बिलियन यूएसस डॉलर्स हुई। नैट एफडीआई भी 2018 में 8.7 बिलियन यूएस डालर्स थी, जो 2019-20 अप्रैल से नवंबर में 12.6 बिलियन डॉलर्स हुई। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार के सब कदम भी उस दिशा में हैं कि विकास दर में बढ़ावा हो और इंडीकेटर्स भी बड़े पॉजिटिव आ रहे हैं। निश्चित तौर पर हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे।

SHRI ABDUL KHALEQUE (BAARPETA): The present Government came out with a promise of providing two crores of new jobs a year. How far has that promise been affected by the growth slide in the economy? Is it true that the job generation in the country is at an all-time low in the last four decades?

Moreover, one of the reasons behind the stagflation of the economy is the crisis faced by the banking sector and the financial institutions like the IL&FS. Despite the enforcement agencies going after the defaulters in the public space, why do such scams involving banks and financial institutions get noticed by the enforcement agencies? Or is it the policy of the Government to go after the public figures and their tax issues but allow the FIIs and the banks to commit financial crimes affecting thousands of people?

SHRI ANURAG SINGH THAKUR: As far as the banking sector is concerned, the Government has taken many steps, from mergers to the recapitalisation of banks. If you look at the previous tenure, like 2009-14, the way the loans were given and post that, when we came into power, there is a vast difference. In 2015 we had the Asset Quality Review for the banking sector.

Apart from that there was a four 'R' approach, that is Reforms, Resolution, Recapitalisation, and Recognition. Due to that there is a huge improvement. If you look at the banks today, the Government has infused more than Rs. 3.5 lakh crore for recapitalisation of banks. The banks are doing well. They are into profits. Out of 18, I think 12 are making profits.

(1150/SM/KN)

In the NBFC sector also, the Partial Credit Guarantee Scheme was for one lakh crore rupees. That has also given advantage to the NBFC sector.

Sir, if you look at the NBFC sector as against the regulatory requirement of 15 per cent of CRAR, the NBFC sector remained at 19.5 per cent at the end of September, 2019. So, I can assure the Member that as far as the banking sector is concerned, due to recapitalisation and other steps taken by the Government and the RBI, the banks have started doing well.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I have seldom seen that a reply which is given is as much bad as catchy on the very crucial question regarding India's economy.

You read with me the question. It asks about the sectors which have taken the hit of the sliding growth rate. In the whole reply, no mention of any sector, whether auto or others, has been made.

Again, part '(e)' of the question says about the manner in which the Government proposes to steer the economy on a growth path. Instead of saying some 'bla, bla' as to what the Budget has done, specific measures needed to steer the economy towards the growth path, in this very critical situation when the GDP growth rate has slumped to 11 year low and when unemployment rate has slumped to 45 year low, …(*Interruptions*) have not been mentioned.

I would like to ask the Minister directly in this very dire situation, very critical situation, whether the Government is thinking of giving any fiscal stimulus to the economy which was badly hit by demonetisation and marred implementation …(*Interruptions*) of GST at this stage when there is no money in the hands of the consumers. They are not able to buy….(*Interruptions*) I want to know whether the Government is going to give any fiscal stimulus.

माननीय अध्यक्ष : दादा, पूरी बात बजट में कर लेना। माननीय मंत्री जी।

SHRI ANURAG SINGH THAKUR: Sir, I am grateful for the question the hon. Member has asked. Let me, Sir, come again to the global economic situation today …(*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): What are the sectors which have been hit?

SHRI ANURAG SINGH THAKUR: I will come to that also. I think that is also part of your Supplementary Question.

Sir, if you look at the global growth today, it has come down to 2.9 per cent. If you compare with that, India will grow at five per cent and in the next year, the expected growth will be from six to six-and-a-half per cent according to the various agencies, from IMF and World Economic Outlook to the RBI's statement recently and also as per *The Economic Survey*.

Sir, what are the step the Government has taken? As I earlier said, from the Insolvency and Bankruptcy Code, the recovery was more than four lakh rupees. Apart from that, the GST was one of the other reforms.

Sir, if you look at the macro economic indicators, it clearly shows that stability remained secured; the GDP was 5 per cent this year; inflation which used to be in double digits in the previous regime, was 4.1 per cent average in

the last five years; if you look at the current account deficit, it was 1.5 per cent; If you look at the numbers regarding fiscal deficit, it is 3.8 per cent. As per the FRMB Act, we just reached at 3.8 per cent. हमने 0.5 परसेंट इस साल उसको किया है। Sir, look at the other indicators also. I can give you a long list.

माननीय अध्यक्ष : आप सारे आँकड़े बजट में बता देना।

…(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : सर, उनका प्रश्न इतना लम्बा है कि सारे आँकड़े बताने ही पड़ेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि इतना समय नहीं है, तो सारी डिटेल्स मैं इनको दे दूँगा। इसके अलावा एफडीआई भी देखिए। मैंने पहले एफपीआईज़ के बारे में सब कुछ कह दिया है। इन्होंने कहा कि कौन से तीन सेक्टर्स की वजह से हो पाया, जो आपके मूल प्रश्न में भी था और आपकी सप्लीमेंट्री में भी। सर, अगर इसमें तीन सेक्टर्स को देखा जाए, उसका सारे सेक्टर्स पर ही इफेक्ट होगा। अगर ग्लोबली ग्रोथ कम हुई है, उसका भारत की अर्थव्यवस्था पर भी फर्क पड़ेगा और सब सेक्टर्स पर पड़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ और सर्विसेज़, इस पर उसका ज्यादा प्रभाव पड़ा है और मॉडरेशन थोड़ा सा इसका मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर पर भी है।

(1155/CS/SPR)

महोदय, लेकिन कुल मिलाकर भारत सरकार ने जो कदम उठाए हैं, जो कारपोरेट टैक्स रेट कट किया है, वह ऐतिहासिक है, सबसे आकर्षक है, जिसके कारण और निवेश भारत में आएगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो 103 लाख करोड़ रुपये के नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की बात की गई है, उससे एफडीआई में भी बढ़ावा होगा।…(व्यवधान)

महोदय, मैं यहाँ पर एफपीआईज के नम्बर भी देना चाहता हूँ।…(व्यवधान) जो मैंने पहले भी दिए हैं।…(व्यवधान) इनकी एप्रोच केवल एक स्टिम्युलस की बात करती है, लेकिन हमने हर सेक्टर के लिए जो कदम उठाए हैं, उससे भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और एक-एक इंडिकेटर बताता है कि भारत अच्छा कर रहा है।…(व्यवधान) जो कदम भारत सरकार ने उठाए हैं, वे प्रशंसनीय हैं और उससे भी दुनिया का भारत में विश्वास बढ़ा है कि भारत आगे अच्छा करने वाला है।…(व्यवधान)

(इति)

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नम्बर - 107, श्री खगेन मुर्मु जी।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न पूछने वाले सभी माननीय सदस्य अपनी सीट से प्रश्न पूछा करें।

…(व्यवधान)

(प्रश्न 107)

श्री खगेन मुर्मु (माल्दहा उत्तर): महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट रुकिए।

माननीय सदस्य, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आप सीट पर बैठे-बैठे टिप्पणियाँ करना बंद कर दें, नहीं तो मुझे मजबूर होकर कार्रवाई करनी पड़ेगी। That's all.

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, यह गलत है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

सुश्री महुआ मोइत्रा (कृष्णानगर): हमने कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन आप फेयरनेस कीजिए।...(व्यवधान)

श्री खगेन मुर्मु (माल्दहा उत्तर): महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप एक मिनट रुकिए।

...(व्यवधान)

विधि और न्याय मंत्री; संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): महोदय, एक मिनट।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : रवि शंकर जी, आप एक मिनट बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट, पहले आप बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सदन में पार्टी के नेता हैं। मैं आपसे फिर आग्रह कर रहा हूँ कि आप माननीय सदस्य को कहें कि एक तो वे अपनी सीट से बोलें।

दूसरा, सदन के अंदर माननीय सदस्य सीट पर बैठे-बैठे बार-बार टिप्पणियाँ करती रहती हैं। आप उन्हें समझाएं।

आप मुझे यह न कहें कि न्यायपूर्ण करें, मैं न्यायपूर्ण हूँ, नहीं हूँ, यह सदन तय कर दे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हर कोई अपनी सीट से बोले।

माननीय अध्यक्ष : हाँ।

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, I would tell her to follow your direction. She is a first time MP. She is a very promising and very

(page 24-30)

jovial MP. She is also a very good speaker. I would tell her to follow the rules, procedures, and directions of the Chair. It will also be good for her also. You also give her your blessings.

श्री खगेन मुर्मु (माल्दहा उत्तर): महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत ही विस्तार से उत्तर सभा पटल पर रखा है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या संस्कृति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्मारकों के विकास के अतिरिक्त और कोई योजना पश्चिम बंगाल के लिए है? यदि हाँ तो वे कौन-कौन सी योजनाएं हैं?

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल : महोदय, माननीय सदस्य को हमने विस्तार से इस बात की जानकारी दी थी कि पश्चिम बंगाल में 135 हमारे संरक्षित स्मारक हैं और सिक्किम के सब-सर्किल को जोड़ देंगे तो इनकी संख्या 138 होती है। जिन योजनाओं की उन्होंने बात की है, मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि उनके प्रश्न के अलावा, संग्रहालयों की जो योजना है, वह पश्चिम बंगाल में चल रही है। मैं उनकी जानकारी और सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि अभी 11 जनवरी को माननीय प्रधान मंत्री जी ने ओल्ड करेंसी बिल्डिंग में एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है और वहाँ तीन स्थानों को फिर से पुनर्स्थापित करने का काम किया है। ओल्ड करेंसी बिल्डिंग, मेटकॉफ हॉल और बेलवेडियर भवन, इन तीनों जगहों पर 18 से 20वीं सदी के पश्चिम बंगाल के जितने भी आर्टिस्ट हैं, उन सबकी चित्रकला को, वहाँ के इतिहास को, उन सबको वहाँ पर संग्रहीत करके दिखाने की कोशिश की गई। इस समय जो बजट में म्यूजियम के डेवलपमेंट की बात आई है, उसमें इंडियन म्यूजियम को प्राथमिकता के साथ रखा गया है कि उस म्यूजियम का काम होगा। ऐसी अनेक योजनाएं, अगर उसके अलावा भी माननीय सदस्य जानना चाहते हैं तो मैं उन्हें सूचना दूँगा।

(1200/RV/UB)

श्री खगेन मुर्मु (माल्दहा उत्तर): सर, आपके माध्यम से मेरा लास्ट सप्लीमेंटरी क्वैश्चन है कि क्या संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्वाधीनता आंदोलन में पश्चिम बंगाल के योगदानकर्ताओं के लिए कोई स्मारक बनाने की योजना है?

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल: अध्यक्ष जी, मैंने अभी प्रश्न के उत्तर में आपके सामने कहा है कि अभी जो शुरुआत में है, उसमें एक स्थान पर तमाम स्वतंत्रता-संग्राम सेनानियों के तमाम इतिहास को, उनकी गतिविधियों को, उनके चित्रों को, पूरे पश्चिम बंगाल के इतिहास को सिरे से, प्रारंभ से लेकर अन्त तक संजोने की व्यवस्था है।

(इति)

प्रश्न काल समाप्त

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

1201 बजे

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्लीज, बैठिए। पूरी बात सुनिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैंने कहा है कि मैंने किसी भी स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। लेकिन, जब माननीय सदस्य ने इस विषय को प्रश्न काल में उठाया था तो मैंने कहा था कि आपको शून्य काल में बोलने की इजाजत दी जाएगी।

…(व्यवधान)

श्री सौमित्र खान (बिशनुपुर): सर, मुझे बोलने दीजिए।

माननीय अध्यक्ष: नहीं।

माननीय सदस्य, प्लीज आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): सर, वहां की…(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) कैसे खत्म होगी?

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, नहीं। आपको वकील बनने की जिम्मेदारी नहीं दी है। आप बैठिए।

…(व्यवधान)

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): सर, बंगाल का बुरा हाल है।

माननीय अध्यक्ष: आप बैठिए। आपको वकील नहीं बनाया गया है।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आप माननीय सदस्यों को बता दीजिएगा कि इस तरीके से बीच में न उठा करें।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1202 बजे

माननीय अध्यक्ष: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे। श्री श्रीपाद येसो नाईक जी।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): Sir, on behalf of Shri Raj Nath Singh, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(1) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Defence for the year 2020-2021.

(2) Defence Services Estimates for the year 2020-2021.

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री नरेन्द्र सिंह तोमर की ओर से, वर्ष 2020-2021 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (DR. SUBRAHMANYAM JAISHANKAR): Sir, I beg to lay on the Table a copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of External Affairs for the year 2020-2021.

मानव संसाधन विकास मंत्री (डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक): श्रीमन्, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं: -

(1) वर्ष 2020-2021 के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(2) वर्ष 2020-2021 के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की निर्गत परिणामी रूपरेखा।

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका सिंह सरुता): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री अर्जुन मुण्डा जी की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं: -

(1) वर्ष 2020-2021 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
(2) वर्ष 2020-2021 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की निर्गत परिणामी रूपरेखा।

THE MINISTER OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT AND MINISTER OF TEXTILES (SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Cotton Textiles Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.
(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Cotton Textiles Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2018-2019.
(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Synthetic and Rayon Textiles Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.
(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Synthetic and Rayon Textiles Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2018-2019.
(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Carpet Export Promotion Council, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.
(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Carpet Export Promotion Council, New Delhi, for the year 2018-2019.
(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Carpet Technology, Bhadohi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Carpet Technology, Bhadohi, for the year 2018-2019.

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Apparel Export Promotion Council, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Apparel Export Promotion Council, New Delhi, for the year 2018-2019.

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Fashion Technology, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Fashion Technology, New Delhi, for the year 2018-2019.

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sardar Vallabhbhai Patel International School of Textiles and Management, Coimbatore, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sardar Vallabhbhai Patel International School of Textiles and Management, Coimbatore, for the year 2018-2019.

(8) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Handloom Export Promotion Council, Chennai, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Handloom Export Promotion Council, Chennai, for the year 2018-2019.

(9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Synthetic and Art Silk Mills' Research Association, Mumbai, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Synthetic and Art Silk Mills' Research Association, Mumbai, for the year 2018-2019.

(10) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Northern India Textile Research Association, Ghaziabad, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Northern India Textile Research Association, Ghaziabad, for the year 2018-2019.

(11) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Man-Made Textiles Research Association, Surat, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Man-Made Textiles Research Association, Surat, for the year 2018-2019.

(12) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Bombay Textile Research Association, Mumbai, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Bombay Textile Research Association, Mumbai, for the year 2018-2019.

(13) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the South India Textile Research Association, Coimbatore, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the South India Textile Research Association, Coimbatore, for the year 2018-2019.

(14) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 13 of the Central Silk Board Act, 1948:-

(i) S.O.3785(E) published in Gazette of India dated 22nd October, 2019 nominating Shri Sudhakar Xalxo, Director, Directorate or Rural Industries (Sericulture Sector) to serve as Member of the Central Silk Board for a period of three years from the date of this notification.

(ii) S.O.2802(E) published in Gazette of India dated 5th August, 2019 nominating members, mentioned therein, to serve as Member of the Central Silk Board for a period of three years from the date of this notification.

(iii) S.O.2859(E) published in Gazette of India dated 7th August, 2019 ceasing the membership of Shri Neeraj Shekhar, consequent upon resignation from the Member of Parliament in Rajya Sabha w.e.f. 15.07.2019 as member of the Central Silk Board.

(15) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(i) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Textiles for the year 2020-2021.

(ii) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Women and Child Development for the year 2020-2021.

(iii) Output Outcome Framework of the Ministry of Women and Child Development for the year 2020-2021.

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE, MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF EARTH SCIENCES (DR. HARSH VARDHAN): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Technology Development Board, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Technology Development Board, New Delhi, for the year 2018-2019.

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Aryabhatta Research Institute for Observational Sciences, Nainital, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Aryabhatta Research Institute for Observational Sciences, Nainital, for the year 2018-2019.

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Birbal Sahni Institute of Palaeosciences, Lucknow, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Birbal Sahni Institute of Palaeosciences, Lucknow, for the year 2018-2019.

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Astrophysics, Bengaluru, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Astrophysics, Bengaluru, for the year 2018-2019.

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials, Hyderabad, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials, Hyderabad, for the year 2018-2019.

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Satyendra Nath Bose National Centre for Basic Sciences, Kolkata, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Satyendra Nath Bose National Centre for Basic Sciences, Kolkata, for the year 2018-2019.

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions of the Indian National Science Academy, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian National Science Academy, New Delhi, for the year 2018-2019.

(8) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Science Congress Association, Kolkata, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Science Congress Association, Kolkata, for the year 2018-2019.

(9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Academy of Sciences, India, Prayagraj, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Academy of Sciences, India, Prayagraj, for the year 2018-2019.

(10) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Wadia Institute of Himalayan Geology, Dehradun, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Wadia Institute of Himalayan Geology, Dehradun, for the year 2018-2019.

(11) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Technology Information, Forecasting and Assessment Council, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Technology Information, Forecasting and Assessment Council, New Delhi, for the year 2018-2019.

(12) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Bose Institute, Kolkata, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Bose Institute, Kolkata, for the year 2018-2019.

(13) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Innovation Foundation-India, Gandhinagar, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Innovation Foundation-India, Gandhinagar, for the year 2018-2019.

(14) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Institute of Nano Science and Technology, Mohali, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Institute of Nano Science and Technology, Mohali, for the year 2018-2019.

(15) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Association for the Cultivation of Science, Kolkata, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Association for the Cultivation of Science, Kolkata, for the year 2018-2019.

(16) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Bengaluru, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Bengaluru, for the year 2018-2019.

(17) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Academy of Sciences, Bengaluru, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Academy of Sciences, Bengaluru, for the year 2018-2019.

(18) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Regional Centre for Biotechnology, Faridabad, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Regional Centre for Biotechnology, Faridabad, for the year 2018-2019.

(19) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(i) Memorandum of Understanding between the Bharat Immunologicals and Biologicals Corporation Limited and the Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology, for the year 2019-2020.

(ii) Memorandum of Understanding between the Biotechnology Industry Research Assistance Council and the Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology, for the year 2019-2020.

(20) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the Central Electronics Limited, New Delhi, for the year 2018-2019.

(ii) Annual Report of the Central Electronics Limited, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(b) (i) Review by the Government of the working of the National Research Development Corporation, New Delhi, for the year 2018-2019.

(ii) Annual Report of the National Research Development Corporation, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(21) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (20) above.

(22) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Consultancy Development Centre, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Consultancy Development Centre, New Delhi, for the year 2018-2019.

(23) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (22) above.

(24) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(iv) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Science and Technology for the year 2020-2021.

(v) Output Outcome Framework of the Ministry of Science and Technology for the year 2020-2021.

(vi) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Health and Family Welfare for the year 2020-2021.

(vii) Output Outcome Monitoring Framework of the Ministry of Health and Family Welfare for the year 2020-2021.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (SHRI BABUL SUPRIYO): Sir, on behalf of Shri Prakash Javadekar, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Prasar Bharati (Audience Research Posts) Recruitment Rules, 2019 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.866(E) in Gazette of India dated 21st November, 2019 under Section 34 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990.

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Mass Communication, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Mass Communication, New Delhi, for the year 2018-2019.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

(4) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(i) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Information and Broadcasting for the year 2020-2021.

(ii) Output Outcome Monitoring Framework of the Ministry of Information and Broadcasting for the year 2020-2021.

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): मान्यवर, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं: -

(1) (एक) दत्तोपंत थेंगड़ी राष्ट्रीय कामगार शिक्षा और विकास बोर्ड (पूर्ववर्ती-केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड), नागपुर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दत्तोपंत थेंगड़ी राष्ट्रीय कामगार शिक्षा और विकास बोर्ड (पूर्ववर्ती-केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड), नागपुर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) वर्ष 2020-2021 के लिए श्रम मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री राव इंद्रजीत सिंह की ओर से, वर्ष 2020-2021 के लिए योजना मंत्रालय की निर्गत परिणामी रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 36 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970:-

(i) The Establishment of New Medical College, Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity by a Medical College Regulations, 2019 published in

Notification No. F. No. 3-16/2018-Regulation (13A) in Gazette of India dated 18th July, 2019.

(ii) The Indian Medicine Central Council (Post Graduate Ayurveda Education) Amendment Regulations, 2019 published in Notification No. F. No. 4-90/2018-P.G.Regulation (Ayurved) in Gazette of India dated 29th July, 2019.

(2) A copy of the Statement (Hindi and English versions) explaining reasons for not laying the Annual Reports and Audited Accounts of the following institutions within the stipulated period of nine months after the close of the accounting year 2018-2019:-

(i) Central Council for Research in Ayurvedic Sciences, New Delhi
(ii) National Institute of Ayurveda, Jaipur
(iii) Post Graduate Teaching & Research in Ayurveda, Jamnagar
(iv) National Academy of Ayurveda, New Delhi
(v) National Institute of Homoeopathy, Kolkata
(vi) Indian Medicines Pharmaceutical Corporation Ltd., Mohan(Alomora)
(vii) Pharmacopoiea commission of Indian medicine & Homoeopathy gaziabad
(viii) North Eastern Institute of Folk Medicine, Pasighat
(ix) North Eastern Institute of Ayurveda and Homoeopathy, Shillong (NEIAH)
(x) All India Institute of Ayurveda, New Delhi

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Council for Research in Yoga and Naturopathy, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Council for Research in Yoga and Naturopathy, New Delhi, for the year 2018-2019.

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Morarji Desai National Institute of Yoga, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Morarji Desai National Institute of Yoga, New Delhi, for the year 2018-2019.

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the North Eastern Institute of Ayurveda and Homoeopathy, Shillong, for the years 2016-2017 and 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the North Eastern Institute of Ayurveda and Homoeopathy, Shillong, for the years 2016-2017 and 2017-2018.

(6) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Council of Homoeopathy, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Council of Homoeopathy, New Delhi, for the year 2018-2019.

(8) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Siddha, Chennai, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Siddha, Chennai, for the year 2018-2019.

(9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Council for Research in Unani Medicine, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Council for Research in Unani Medicine, New Delhi, for the year 2018-2019.

(10) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (9) above.

(11) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Council of Indian Medicine, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Council of Indian Medicine, New Delhi, for the year 2018-2019.

(12) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (11) above.

(13) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Council for Research in Homoeopathy, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Council for Research in Homoeopathy, New Delhi, for the year 2018-2019.

(14) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (13) above.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): Sir, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(1) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Minority Affairs for the year 2020-2021.

(2) Output Outcome Framework of the Ministry of Minority Affairs for the year 2020-2021.

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रह्लाद सिंह पटेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं: -

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण): -

(एक) वर्ष 2020-2021 के लिए पर्यटन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2020-2021 के लिए पर्यटन मंत्रालय की निर्गत परिणामी रूपरेखा।

(2) (एक) वृंदावन अनुसंधान संस्थान, वृंदावन के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वृंदावन अनुसंधान संस्थान, वृंदावन के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) कलाक्षेत्र फाउंडेशन, चेन्नई के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे। (दो) कलाक्षेत्र फाउंडेशन, चेन्नई के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI HARDEEP SINGH PURI): Sir, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(1) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Housing and Urban Affairs for the year 2020-2021.

(2) Output Outcome Framework of the Ministry of Housing and Urban Affairs for the year 2020-2021.

(1205//KMR/MY)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष महोदय, मैं लोक 1उद्यम सर्वेक्षण 2018-2019 (खण्ड एक और दो) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (SHRI BABUL SUPRIYO): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Pollution Control Board, Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Pollution Control Board, Delhi, for the year 2018-2019.

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 25 of the Environment (Protection) Act, 1986:-

(i) S.O.2522(E) published in Gazette of India dated 15th July, 2019 making certain amendments in Notification No. S.O.5120(E) dated 3rd October, 2018.

(ii) S.O.3023(E) published in Gazette of India dated 22nd August, 2019 relating to certifying instruments and equipments for monitoring air quality.

(iii) S.O.2502(E) published in Gazette of India dated 12th July, 2019 regarding Blue Flag Certification of twelve beaches.

(iv) S.O.3248(E) published in Gazette of India dated 11th September, 2019 regarding reconstitution of Gujarat Coastal Zone Management Authority.

(v) S.O.3903(E) published in Gazette of India dated 30th October, 2019 regarding reconstitution of Kerala Coastal Zone Management Authority.

(vi) S.O.5768(E) published in Gazette of India dated 16th November, 2018 regarding extension/renewal of the tenure to the private environmental laboratories.

(vii) S.O.3744(E) published in Gazette of India dated 16th November, 2018 regarding extension/renewal of the tenure to the private environmental laboratories.

(3) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(i) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for the year 2020-2021.

(ii) Output Outcome Monitoring Framework of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for the year 2020-2021.

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Salim Ali Centre for Ornithology and Natural History, Coimbatore, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Salim Ali Centre for Ornithology and Natural History, Coimbatore, for the year 2017-2018.

(5) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (4) above.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI SANJAY DHOTRE): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, Tirupati, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, Tirupati, for the year 2018-2019.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology Patna, Patna, for the year 2017-2018.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology Patna, Patna, for the year 2017-2018, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Technology Patna, Patna, for the year 2017-2018.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology Kharagpur, Kharagpur, for the year 2018-2019.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology Kharagpur, Kharagpur, for the year 2018-2019, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Technology Kharagpur, Kharagpur, for the year 2018-2019.

(6) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology Madras, Chennai, for the year 2018-2019.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology Madras, Chennai, for the year 2018-2019, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Technology Madras, Chennai, for the year 2018-2019.

(8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

(9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology Hyderabad, Hyderabad, for the year 2018-2019.

(ii) A copy of the Annual Accounts of the Indian Institute of Technology Hyderabad, Hyderabad, for the year 2018-2019, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the Indian Institute of Technology Hyderabad, Hyderabad, for the year 2018-2019.

(10) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (9) above.

(11) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology Jodhpur, Jodhpur, for the year 2018-2019.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology Jodhpur, Jodhpur, for the year 2018-2019, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Technology Jodhpur, Jodhpur, for the year 2018-2019.

(12) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (11) above.

(13) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology Gandhinagar, Gandhinagar, for the year 2018-2019.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology Gandhinagar, Gandhinagar, for the year 2018-2019, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Technology Gandhinagar, Gandhinagar, for the year 2018-2019.

(14) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (13) above.

(15) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology Kurukshetra, Kurukshetra, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technology Kurukshetra, Kurukshetra, for the year 2018-2019.

(16) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (15) above.

(17) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Jamia Millia Islamia, New Delhi, for the year 2018-2019.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Jamia Millia Islamia, New Delhi, for the year 2018-2019, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Jamia Millia Islamia, New Delhi, for the year 2018-2019.

(18) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (17) above.

(19) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology Delhi, New Delhi, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technology Delhi, New Delhi, for the year 2017-2018.

(20) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (19) above.

(21) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology Arunachal Pradesh, Yupia, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technology Arunachal Pradesh, Yupia, for the year 2017-2018.

(22) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (21) above.

(23) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology Patna, Patna, for the year 2016-2017.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology Patna, Patna, for the year 2016-2017, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technology Patna, Patna, for the year 2016-2017.

(24) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (23) above.

(25) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology Sikkim, Ravangla, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technology Sikkim, Ravangla, for the year 2017-2018.

(26) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (25) above.

(27) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Samagra Shikshana Karnataka, Bengaluru, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Samagra Shikshana Karnataka, Bengaluru, for the year 2018-2019.

(28) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (27) above.

(29) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Council for Teacher Education, New Delhi, for the year 2017-2018.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Council for Teacher Education, New Delhi, for the year 2017-2018, together with Audit Report thereon.

(iii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Council for Teacher Education, New Delhi, for the year 2017-2018.

(30) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (29) above.

(31) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sant Longowal Institute of Engineering and Technology, Longowal, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sant Longowal Institute of Engineering and Technology, Longowal, for the year 2018-2019.

(32) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (31) above.

(33) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Atal Bihari Vajpayee Indian Institute of Information Technology and Management, Gwalior, for the year 2017-2018.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Atal Bihari Vajpayee Indian Institute of Information Technology and Management, Gwalior, for the year 2017-2018.

(34) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (33) above.

(35) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing, Kurnool, for the year 2017-2018.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing, Kurnool, for the year 2017-2018, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Institute of Information Technology, Design and Manufacturing, Kurnool, for the year 2017-2018.

(36) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (35) above.

(37) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Ghani Khan Choudhury Institute of Engineering and Technology, Malda, for the year 2012-2013, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Ghani Khan Choudhury Institute of Engineering and Technology, Malda, for the year 2012-2013.

(38) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (37) above.

(39) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Board of Apprenticeship Training (Southern Region), Chennai, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Board of Apprenticeship Training (Southern Region), Chennai, for the year 2018-2019.

(40) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (39) above.

(41) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Board of Practical Training (Eastern Region), Kolkata, for the year 2018-2019, alongwith Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Board of Practical Training (Eastern Region), Kolkata, for the year 2018-2019.

(42) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (41) above.

(43) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Board of Apprenticeship Training (Northern Region), Kanpur, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Board of Apprenticeship Training (Northern Region), Kanpur, for the year 2018-2019.

(44) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (43) above.

(45) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Board of Apprenticeship Training (Western Region), Mumbai, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Board of Apprenticeship Training (Western Region), Mumbai, for the year 2018-2019.

(46) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (45) above.

(47) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing, Kancheepuram, for the year 2017-2018.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing, Kancheepuram, for the year 2017-2018, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing, Kancheepuram, for the year 2017-2018.

(48) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (47) above.

(49) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rajasthan Council of Elementary Education, Jaipur, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rajasthan Council of Elementary Education, Jaipur, for the year 2017-2018.

(50) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (49) above.

(51) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rajasthan Council of Secondary Education, Jaipur, for the years 2014-2015 and 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rajasthan Council of Secondary Education, Jaipur, for the years 2014-2015 and 2015-2016.

(52) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (51) above.

(53) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 48 of the Indian Institute of Information Technology (Public-Private Partnership) Act, 2017:-

(i) S.O.3810(E) published in Gazette of India dated 23rd October, 2019 regarding ordinances framed for the Indian Institute of Information Technology (Public-Private Partnership), Lucknow.

(ii) S.O.3811(E) published in Gazette of India dated 23rd October, 2019 regarding ordinances framed for the Indian Institute of Information Technology (Public-Private Partnership), Ranchi.

(iii) S.O.3812(E) published in Gazette of India dated 23rd October, 2019 regarding ordinances framed for the Indian Institute of Information Technology (Public-Private Partnership), Pune.

(iv) S.O.3813(E) published in Gazette of India dated 23rd October, 2019 regarding ordinances framed for the Indian Institute of Information Technology (Public-Private Partnership), Tiruchirappalli.

(v) S.O.3814(E) published in Gazette of India dated 23rd October, 2019 regarding ordinances framed for the Indian Institute of Information Technology (Public-Private Partnership), Kalyani.

(vi) S.O.3815(E) published in Gazette of India dated 23rd October, 2019 regarding ordinances framed for the Indian Institute of Information Technology (Public-Private Partnership), Una.

(vii) S.O.3816(E) published in Gazette of India dated 23rd October, 2019 regarding ordinances framed for the Indian Institute of Information Technology (Public-Private Partnership), Sonepat.

(viii) S.O.3817(E) published in Gazette of India dated 23rd October, 2019 regarding ordinances framed for the Indian Institute of Information Technology (Public-Private Partnership), Dharwad.

(ix) S.O.3818(E) published in Gazette of India dated 23rd October, 2019 regarding ordinances framed for the Indian Institute of Information Technology (Public-Private Partnership), Kottayam.

(x) S.O.3819(E) published in Gazette of India dated 23rd October, 2019 regarding ordinances framed for the Indian Institute of Information Technology (Public-Private Partnership), Sricity Chittoor.

(xi) S.O.3820(E) published in Gazette of India dated 23rd October, 2019 regarding ordinances framed for the Indian Institute of Information Technology (Public-Private Partnership), Nagpur.

(xii) S.O.3821(E) published in Gazette of India dated 23rd October, 2019 regarding ordinances framed for the Indian Institute of Information Technology (Public-Private Partnership), Guwahati.

(xiii) S.O.3822(E) published in Gazette of India dated 23rd October, 2019 regarding ordinances framed for the Indian Institute of Information Technology (Public-Private Partnership), Vododara.

(xiv) S.O.3823(E) published in Gazette of India dated 23rd October, 2019 regarding ordinances framed for the Indian Institute of Information Technology (Public-Private Partnership), Kota.

(xv) S.O.3824(E) published in Gazette of India dated 23rd October, 2019 regarding ordinances framed for the Indian Institute of Information Technology (Public-Private Partnership), Senapati.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आसन को इधर-उधर करके बात नहीं किया कीजिए।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI ANURAG SINGH THAKUR): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(i) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Corporate Affairs for the year 2020-2021.

(ii) Output Outcome Framework of the Ministry of Corporate Affairs for the year 2020-2021.

(iii) Detailed Demands for Grants of the Parliament, Secretariats of the President and Vice-President for the year 2020-2021.

(iv) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Finance for the year 2020-2021.

(v) Output Outcome Monitoring Framework of the Ministry of Finance for the year 2020-2021.

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Pension Fund Regulatory and Development Authority, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Pension Fund Regulatory and Development Authority, New Delhi, for the year 2018-2019.

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Public Finance and Policy, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Public Finance and Policy, New Delhi, for the year 2018-2019.

(4) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Insurance Regulatory and Development Authority of India, Hyderabad, for the year 2018-2019, together with Audit Report thereon.

(5) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Nagaland Rural Bank, Kohima, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(6) A copy of the Consolidated Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Regional Rural Banks for the year 2018-2019.

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Financial Management, Faridabad, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Financial Management, Faridabad, for the year 2018-2019.

(8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

(9) A copy of the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Adviser) (Fifth Amendment) Regulations, 2019 published in Notification No. PFRDA/12/RGL/139/10 in Gazette of India dated 3rd December,

2019 under Section 53 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013.

(10) A copy of the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) (Amendment) Regulations, 2019 (Hindi and English versions) published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/25 in Gazette of India dated 29th July, 2019 under Section 31 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992.

(11) A copy of the Notification No. S.O.4644(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 27th December, 2019 to explicitly explain the provisions of the aforesaid Notification No. S.O.870(E) dated 27.03.2015 under sub-section (3) of Section 114 of the Insurance Act, 1938.

(12) A copy of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Third Party Administrators-Health Services) (Amendment) Regulations, 2019 (Hindi and English versions) published in Notification No. F. No. IRDAI/Reg/15/166/2019 in Gazette of India dated 4th December, 2019 under Section 114A of the Insurance Act, 1938 and Section 27 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999.

(13) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 25 of the Coinage Act, 2011:-

(i) The Coinage of Two Hundred and Fifty Rupees to commemorate the occasion of 250th Session of Rajya Sabha Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.829(E) in Gazette of India dated 8th November, 2019.

(ii) The Coinage (Issue of Commemorative Coin on the occasion of the 550th Prakash Utsav of Shri Guru Nanak Dev Ji) Amendment Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.791(E) in Gazette of India dated 16th October, 2019.

(iii) The Coinage of One Hundred Fifty Rupees Coin to commemorate the occasion of 150th Birth Anniversary of Mahatma Gandhi Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.592(E) in Gazette of India dated 22nd August, 2019.

(14) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 3A of the Government Savings Promotion Act, 1873:-

(i) G.S.R.913(E) published in Gazette of India dated 12th December, 2019, rescinding Notification No. G.S.R.1136(E) dated 15th June, 1968.

(ii) The Sukanya Samriddhi Account Scheme, 2019 (Amendment Rules), 2018 published in Notification No. G.S.R.914(E) in Gazette of India dated 12th December, 2019.

(iii) The Public Provident Fund Scheme, 2019 (Amendment Rules), 2018 published in Notification No. G.S.R.915(E) in Gazette of India dated 12th December, 2019.

(iv) The Senior Citizen's Savings Scheme, 2019 (Amendment Rules), 2018 published in Notification No. G.S.R.916(E) in Gazette of India dated 12th December, 2019.

(v) The National Savings (Monthly Income Account) Scheme, 2019 (Amendment Rules), 2018 published in Notification No. G.S.R.917(E) in Gazette of India dated 12th December, 2019.

(vi) The National Savings Recurring Deposit Scheme, 2019 (Amendment Rules), 2018 published in Notification No. G.S.R.918(E) in Gazette of India dated 12th December, 2019.

(vii) The National Savings Certificates (VIII Issue) Scheme, 2019 (Amendment Rules), 2018 published in Notification No. G.S.R.919(E) in Gazette of India dated 12th December, 2019.

(viii) The Kisan Vikas Patra Scheme, 2019 (Amendment Rules), 2018 published in Notification No. G.S.R.920(E) in Gazette of India dated 12th December, 2019.

(ix) The Post Office Savings Account Scheme, 2019 (Amendment Rules), 2018 published in Notification No. G.S.R.921(E) in Gazette of India dated 12th December, 2019.

(x) The National Savings Time Deposit Scheme, 2019 (Amendment Rules), 2018 published in Notification No. G.S.R.922(E) in Gazette of India dated 12th December, 2019.

(15) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 296 of the Income Tax Act, 1961:-

(i) The Income-tax (8th Amendment) Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.662(E) in Gazette of India dated 17th September, 2019, together with an explanatory memorandum.

(ii) The Income-tax (13th Amendment) Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.836(E) in Gazette of India dated 11th November, 2019, together with an explanatory memorandum.

(16) A copy of the Prohibition of Benami Property Transactions (1st Amendment) Rules, 2019 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.885(E) in Gazette of India dated 29th November, 2019 under Section 69 of the Benami Transactions (Prohibition) Amendment Act, 2006, together with an explanatory memorandum.

(17) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2A) of Section 76 of the Indian Stamp Act, 1899:-

(i) The Indian Stamp (Collection of Stamp-Duty through Stock Exchanges, Clearing Corporations and Depositories) Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.901(E) in Gazette of India dated 10th December, 2019.

(ii) The Indian Stamp (Collection of Stamp-Duty through Stock Exchanges, Clearing Corporations and Depositories) (Amendment) Rules, 2020 published in Notification No. G.S.R.19(E) in Gazette of India dated 8th January, 2020.

(18) A copy of the Notification No. G.S.R.28(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 13th January, 2020, together with an explanatory memorandum seeking to appoint Revisional Authority under CGST Act, 2017 under Section 166 of the Central Goods and Service Tax Act, 2017.

(19) A copy of the Notification No. G.S.R.948(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 24th December, 2019, together with an explanatory memorandum making certain amendments in Notification No. 14/2018-Union Territory Tax, dated 8th October, 2018 under Section 166 of the Central Goods and Service Tax Act, 2017 and Section 24 of the Union Territory Goods and Service Tax Act, 2017.

(20) A copy of the Notification No. 1-CA(5)/70A/2019 (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 29th November, 2019, containing

corrigendum to the Notification No. 1-CA(5)/70/2019 dated 30th September, 2019 under Section 30B of the Chartered Accountants Act, 1949.

(21) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) to Section 23A of the Regional Rural Banks Act, 1976:-

(i) S.O.4106(E) published in Gazette of India dated 14th November, 2019, regarding dissolution of Madhya Bihar Gramin Bank and Bihar Gramin Bank by reason of amalgamation.

(ii) S.O.4107(E) published in Gazette of India dated 14th November, 2019, regarding dissolution of Narmada Jhabua Gramin Bank and Central Madhya Pradesh Gramin Bank by reason of amalgamation.

(iii) S.O.4108(E) published in Gazette of India dated 14th November, 2019, regarding dissolution of Sarva UP Gramin Bank and Prathama Bank by reason of amalgamation.

(iv) S.O.4109(E) published in Gazette of India dated 14th November, 2019, regarding dissolution of Gramin Bank of Aryavart and Allahabad UP Gramin Bank by reason of amalgamation.

(v) S.O.4110(E) published in Gazette of India dated 14th November, 2019, regarding dissolution of Pragathi Krishna Gramin Bank and Kaveri Grameena Bank by reason of amalgamation.

(vi) S.O.4111(E) published in Gazette of India dated 14th November, 2019, regarding dissolution of Vananchal Gramin Bank and Jharkhand Gramin Bank by reason of amalgamation.

(vii) S.O.4112(E) published in Gazette of India dated 14th November, 2019, regarding dissolution of Pallavan Grama Gramin Bank and Pandyan Grama Bank by reason of amalgamation.

(viii) S.O.4113(E) published in Gazette of India dated 14th November, 2019, regarding dissolution of Baroda Gujarat Gramin Bank and Dena Gujarat Gramin Bank by reason of amalgamation.

(ix) S.O.4114(E) published in Gazette of India dated 14th November, 2019, regarding dissolution of Punjab Gramin Bank, Malwa Gramin Bank and Sutlej Gramin Bank by reason of amalgamation.

(x) S.O.4115(E) published in Gazette of India dated 14th November, 2019, regarding dissolution of Assam Gramin Vikash Bank and Langpi Dehangi Rural Bank by reason of amalgamation.

(22) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 159 of the Customs Act, 1962:-

(i) G.S.R.61(E) published in Gazette of India dated 2nd February, 2020, together with an explanatory memorandum seeking to amend notification No.50/2017-Customs dated 30th June, 2017.

(ii) G.S.R.62(E) published in Gazette of India dated 2nd February, 2020, together with an explanatory memorandum seeking to amend notification No. 57/2017-Customs, dated the 30th June, 2017.

(iii) G.S.R.63(E) published in Gazette of India dated 2nd February, 2020, together with an explanatory memorandum seeking to amend notification No. 19/2019-Customs, dated the 06th July, 2019.

(iv) G.S.R.64(E) published in Gazette of India dated 2nd February, 2020, together with an explanatory memorandum seeking to amend notification No. 148/1994-Customs, dated the 13th July, 1994.

(v) G.S.R.65(E) published in Gazette of India dated 2nd February, 2020, together with an explanatory memorandum seeking amend notification No. 25/1999-Customs, dated the 28th February, 1999.

(vi) G.S.R.66(E) published in Gazette of India dated 2nd February, 2020, together with an explanatory memorandum seeking to amend notification No. 24/2005-Customs, dated the 01st March, 2005.

(vii) G.S.R.67(E) published in Gazette of India dated 2nd February, 2020, together with an explanatory memorandum seeking to amend notification No. 25/2005-Customs, dated the 1st March, 2005.

(viii) G.S.R.68(E) published in Gazette of India dated 2nd February, 2020, together with an explanatory memorandum seeking exempt specified goods from Health Cess imposed on the medical devices falling under heading 9018 to 9022 in terms of clause 139 of the Finance Bill, 2020.

(ix) G.S.R.69(E) published in Gazette of India dated 2nd February, 2020, together with an explanatory memorandum seeking to amend notification No. 11/2018-Customs, dated the 2nd February, 2018 in order to revise the levy of Social Welfare Surcharge on specified goods.

(x) G.S.R.70(E) published in Gazette of India dated 2nd February, 2020, together with an explanatory memorandum seeking to amend notifications mentioned in the Column (2) of the Table of the notification No. 10/2020-Customs, dated the 2nd February, 2020.

(xi) G.S.R.71(E) published in Gazette of India dated 2nd February, 2020, together with an explanatory memorandum seeking to amend notification No. 82/2017-Customs dated the 27th October, 2017.

(xii) G.S.R.72(E) published in Gazette of India dated 2nd February, 2020, together with an explanatory memorandum seeking rescind certain customs notifications which have become redundant or entries in these notifications are being merged with other similar notifications granting exemptions.

(xiii) The Transhipment of Cargo to Nepal under Electronic Cargo Tracking System Regulations, 2019 published in Notification No. G.S.R.704(E) published in Gazette of India dated 30th September, 2019, together with an explanatory memorandum.

(xiv) The Manufacture and other Operations in Warehouse (No. 2) Regulations, 2019 published in Notification No. G.S.R.754(E) published in Gazette of India dated 1st October, 2019, together with an explanatory memorandum.

(xv) The Warehouse (Custody and Handling of Goods) Amendment Regulations, 2019 published in Notification No. G.S.R.755(E) published in Gazette of India dated 1st October, 2019, together with an explanatory memorandum.

(xvi) The Warehouse Goods (Removal) Amendment Regulations, 2019 published in Notification No. G.S.R.756(E) published in Gazette of India dated 1st October, 2019, together with an explanatory memorandum.

(23) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 10 of the Customs Tariff Act, 1975:-

(i) The Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Amendment Rules, 2020 published in Notification No.

G.S.R.73(E) published in Gazette of India dated 2nd February, 2020, together with an explanatory memorandum.

(ii) The Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidised Articles and for Determination of Injury) Amendment Rules, 2020 published in Notification No. G.S.R.74(E) published in Gazette of India dated 2nd February, 2020, together with an explanatory memorandum.

(24) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (7) of Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975:-

(i) G.S.R.75(E) published in Gazette of India dated 2nd February, 2020, together with an explanatory memorandum seeking to amend notification No. 1/2018-Customs (SG), dated the 30th July, 2018.

(iii) G.S.R.76(E) published in Gazette of India dated 2nd February, 2020, together with an explanatory memorandum seeking to revoke the Anti-dumping duty imposed on Purified Terephthalic Acid and for this purpose, rescinds the notifications No. 28/2016-Customs (ADD), dated the 5th July, 2016 and No. 28/2019-Customs (ADD), dated the 24th July, 2019.

(25) A copy of the Order (Hindi and English versions) issued by the Central Board of Direct Taxes, Department of Revenue, Ministry of Finance under Section 119(2)(c) of the Income-tax Act, 1961.

(26) A copy of the Notification No. G.S.R.912(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 12th December, 2019, rescinding notifications, mentioned therein under sub-section (3) of Section 15 of the Government Savings Promotion Act, 1873.

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया): अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2020-2021 के लिए पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SUSHRI DEBASREE CHAUDHURI): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Commission for Protection of Child Rights, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Commission for Protection of Child Rights, New Delhi, for the year 2018-2019.

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Adoption Resource Authority, New Delhi, for the year 2018-2019, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Adoption Resource Authority, New Delhi, for the year 2018-2019.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Public Cooperation and Child Development, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Public Cooperation and Child Development, New Delhi, for the year 2018-2019.

(5) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (4) above.

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Childline India Foundation, Mumbai, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Childline India Foundation, Mumbai, for the year 2018-2019.

(7) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (6) above.

(8) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Social Welfare Board, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Social Welfare Board, New Delhi, for the year 2018-2019.

(9) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (8) above.

(10) A copy of the following papers (Hindi and English versions) under Section 14 of the National Commission for Women Act, 1990:-

(i) Annual Report of the National Commission for Women, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Commission for Women, New Delhi, for the year 2018-2019.

(11) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (10) above.

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY GENERAL: Hon'ble Speaker, Sir, I have to report the following message received from the Secretary-General of Rajya Sabha:-

"I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on Wednesday, the 4th December, 2019 adopted the following Motion in regard to the Committee on Public Accounts:-

> "That this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do agree to nominate one Member from Rajya Sabha *vice* Shri Bhubaneswar Kalita, who resigned from the membership of Rajya Sabha *w.ef* 5.8.2019, to associate with the Committee on Public Accounts of the Lok Sabha for the unexpired portion of the term of the Committee and do proceed to elect, in such manner as the Chairman may direct, one Member from among the Members of this House to serve on the said Committee."

2. I am further to inform the Lok Sabha that in pursuance of the above Motion, Shri P. Bhattacharya, Member, Rajya Sabha has been duly elected to the said Committee.'

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

13th Report

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): I beg to present the Thirteenth Report of the Business Advisory Committee.

चीन में नोवल कोरोनावायरस के प्रकोप के संबंध में भारत सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में वक्तव्य

1208 बजे

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री; विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (डॉ. हर्ष वर्धन): अध्यक्ष महोदय, मैं चीन तथा कुछ अन्य देशों में नोवल कोरोना वायरस रोग के प्रकोप के फैलने तथा इस बारे में भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के संबंध में माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा।

कोरोना वायरस वायरसों के वो बड़े समूह हैं जिनके कारण इंसानों तथा जानवरों में बीमारी फैलती है। पशु कोरोना वायरस कभी-कभार विकसित होकर लोगों को संक्रमित करते हैं तथा उसके पश्चात वे लोगों में फैलने लगते हैं, जैसा कि वर्ष 2003 में सिवियर एक्युट रेसिपिरेटरी सिंड्रोम (सार्स) में तथा वर्ष 2014 में मीडिल ईस्ट रेसिपिरेटरी सिंड्रोम (मर्स) में देखा जा चुका है।

नोवल कोरोना वायरस के इस प्रकोप के संबंध में चीन से 31 दिसम्बर, 2019 को सूचना मिली थी। प्रारंभ में इस प्रकोप को चीन के हुबेई प्रान्त के वुहान शहर में सीफूड बाजार में दिसम्बर 2019 के शुरू में नोटिस किया गया था तथा बहुत ही कम समय में यह चीन के सभी प्रान्तों में फैल गया।

दिनांक 09 फरवरी की स्थिति के अनुसार चीन में पुष्ट मामलों की कुल संख्या 37,198 है तथा 811 मौतों की सूचना है। चीन के अलावा 27 देश, जिसमें हांगकांग, मकाओ तथा ताईवान भी शामिल हैं, में कुल 354 पुष्ट मामलों की सूचना है। चीन से सूचित मामलों और मौतों की संख्या में वृद्धि हो रही है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 30 जनवरी, 2020 को इस महामारी को 'पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न' (पीएचआईईसी) घोषित किया।

इस महामारी के कई महामारी विज्ञान संबंधी मानक जैसे कि रोगोद्भवन अवधि, संचरण का माध्यम, उपनैदानिक संक्रमण, वायरस खत्म होने की अवधि इत्यादि अज्ञात है। किसी भी व्यक्ति के संक्रमित होने के बाद बीमारी विकसित होने में लगभग 2 सप्ताह लग सकते हैं। नोवल कोरोना वायरस के मुख्य लक्षण में बुखार, खांसी और सांस लेने में दिक्कत है। रेडियोलॉजिकल साक्ष्य निमोनिया जैसे होंगे। 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत मामलों में रोग इतना गंभीर हो सकता है कि वेनटिलेटरी सहायता की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे मामलों में मृत्यु-दर लगभग 2 प्रतिशत है।

(1210/CP/SNT)

1210 बजे (श्री राजेन्द्र अग्रवाल पीठासीन हुए)

मनुष्य से मनुष्य में संप्रेषण के मामले नोवल कोरोना वायरस में देखे गए हैं तथा ये संक्रमित व्यक्ति के सन्निकट रहने वाले लोगों में ड्रापलेट्स/एयरोसोल के माध्यम से फैलता है। संक्रमित रोगियों के फीकल नमूनों में इस वायरस के पाए जाने की रिपोर्टों के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों संबंधी अध्ययन किए जा रहे हैं। नोवल कोरोना वायरस को और फैलने से रोकने के लिए इस

रोग के सभी संदिग्ध एवं संभावित मामलों को बैरियर नर्सिंग एवं सम्पूर्ण सावधानियों के साथ अलग से उपचार किया जाना चाहिए।

हमारे देश में, केरल से अब तक तीन पॉजिटिव मामलों की रिपोर्ट आई है। इन सभी मामलों का वुहान, चीन से यात्रा का इतिहास है। इन्हें अलग रखा गया है और इन्हें नैदानिक रूप से स्थिर बताया गया है।

इस महामारी की बढ़ती हुई घटना को देखते हुए न केवल स्वास्थ्य क्षेत्र द्वारा बल्कि सभी सरकारी क्षेत्रों द्वारा ठोस प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इस रोग को फैलने से रोकने और सीमित रखने हेतु भारत सरकार ने अनेक कार्य प्रारंभ किए हैं। मैं स्थिति की प्रतिदिन समीक्षा कर रहा हूं। स्थिति पर निगरानी रखने के लिए मेरी अध्यक्षता में एक मंत्री समूह का गठन किया गया है, जिसमें विदेश मंत्री, नागर विमानन मंत्री एवं गृह राज्य मंत्री, नौवहन राज्य मंत्री और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण राज्य मंत्री शामिल हैं। मंत्रिमंडल सचिव ने स्वास्थ्य, रक्षा, विदेश, नागर विमानन, गृह, वस्त्र, फार्मा, वाणिज्य आदि सभी संबंधित मंत्रालयों और राज्य मुख्य सचिवों सहित अन्य अधिकारियों के साथ दैनिक समीक्षा की है। मेरा अपना मंत्रालय ताजा स्थितियों की निरंतर समीक्षा कर रहा है। राज्यों के साथ हर दूसरे दिन वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है।

भारत सरकार ने भारत में नोवल कोरोना वायरस संक्रमण के फैलने के खतरे के नियंत्रण के लिए कई अन्य उपाय भी किए हैं। यात्रा संबंधी प्रथम परामर्शिका दिनांक 17 जनवरी, 2020 को जारी की गई थी और जैसे ही स्थिति बढ़ती है, वैसे ही यात्रा परामर्शिका को संशोधित किया जा रहा है। वर्तमान में :-

क) चीन से आने वाले किसी भी विदेशी नागरिक का वर्तमान वीज़ा (जिसमें पूर्व में जारी ई-वीज़ा सम्मिलित है) को अमान्य किया गया है।

ख) भारत में दौरे के लिए विवश लोगों को बीजिंग में भारतीय दूतावास अथवा शंघाई या गुआंग़जौ में दूतावास से संपर्क करने को कहा गया है।

ग) भारतीय नागरिकों को चीन से यात्रा करने से बचने की सलाह दी गई है। अब से लोगों को चीन से यात्रा कर लौटने पर क्वारंटाइन किया जाएगा।

दिनांक 18 जनवरी, 2020 से यात्रियों की जांच की शरुआत की गई थी। प्रारम्भ में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोची हवाई अड्डे को कवर किया गया और तत्पश्चात् कुल 21 हवाई अड्डों हेतु इसका विस्तार किया गया। हांगकांग और चीन के अलावा सिंगापुर व थाईलैंड से सभी फ्लाइटों के लिए यूनिवर्सल थर्मल स्क्रीनिंग को अनिवार्य किया गया है और इन फ्लाइट्स की जांच को सुलभ बनाने के लिए निर्धारित एरो-ब्रिज में पार्क किया जाएगा। हवाई अड्डों और पत्तनों में मुख्य स्थानों पर संकेत बोर्ड प्रदर्शित किए गए हैं, हवाई जहाज में घोषणाएं की जा रही हैं और सभी यात्रियों द्वारा स्व-घोषणा प्रपत्र भरे जा रहे हैं। आज तक कुल 1,97,192 यात्रियों वाली कुल 1,818 उड़ानों की जांच की गई है। विशेषज्ञ डॉक्टरों के दल को सभी विमान पत्तनों पर प्रभावी जांच और संबद्ध अस्पतालों में एकाकी में रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भेजा गया है।

चीन से आने वाले यात्रियों और कार्मिक दल की पहचान करने और उनमें लक्षण पाए जाने के मामले में उन्हें पृथक करने के लिए देश के 12 प्रमुख समुद्री पत्तनों और सभी छोटे पत्तनों पर भी यात्रियों की जांच शुरू की गई है।

1214 बजे (माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

नेपाल में पुष्ट मामलों के आलोक में सरकार ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार तथा सीमा सशस्त्र बल तथा लैंड पोर्ट आथोर्टी के समन्वयन में नेपाल से लगे सभी चैक पोस्टों पर जांच शुरु की है। नेपाल से लगे सीमावर्ती गांवों में पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया है, ताकि लोगों में इस रोग के प्रति जागरुकता पैदा की जा सके और सावधानी बरती जा सके।

(1215/NK/GM)

चीन के हयूवे प्रांत में निरंतर बंद को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने वुहान तथा हयूवे प्रांत के नजदीकी शहरों में कार्यरत भारतीय छात्रों तथा अन्य पेशेवरों को निकालने का निर्णय लिया है। नागर विमानन मंत्रालय, एयर इंडिया, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ समन्वित ऑपरेशन में दिनांक 31 जनवरी और 1 फरवरी, 2020 दिल्ली और वुहान के बीच दो विशेष एयर इंडिया की उड़ानों का परिचालन किया गया, जिनसे कुल 654 यात्रियों को वापस लाया गया जिनमें 647 भारतीय नागरिक (खाली कराने वाले ऑपरेशन हेतु वुहान से भारतीय दूतावास के दो कार्मिकों सहित) तथा 7 मालदीव देश के नागरिक शामिल हैं। मैं एयर इंडिया, इसके कार्मिक दल और अपने चिकित्सकों तथा परा-चिकित्सा स्टॉफ को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने इस चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन को अंजाम दिया और उनके इस सराहनीय कार्य को इस सदन के सौजन्य से रिकार्ड पर लेना चाहूंगा।

खाली कराने के पश्चात् वर्तमान में लोगों की मानेसर में भारतीय सेना तथा छावला कैंप में भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) द्वारा विशेष रूप से निर्मित केन्द्रों में क्यूरेन्टाइन प्रक्रिया चल रही है। खाली कराए गए लोगों में से लक्षण युक्त 10 लोगों को एकाकी स्थल पर शिफ्ट किया गया है। उनमें से सभी जांच में रोग मुक्त पाए गए और उनकी स्थिति स्थिर है, अन्य सभी विस्थापित व्यक्तियों की प्रतिदिन चिकित्सीय जांच की जा रही है और वे स्वस्थ हैं।

भारतीय दूतावास और कांसुलेट्स सभी चीन के अन्य भागों में भारतीय समुदाय के साथ नियमित रूप से संपर्क बनाए हुए हैं और उनके स्वास्थ्य की निरंतर जानकारी रख रहे हैं।

देश भर में चीन से आने वाले सभी मामलों तथा ऐसे व्यक्तियों से संपर्क रखने वाले लोगों और जिन्हें ज्वर, खांसी अथवा श्वसनहीनता है उनकी नियमित निगरानी शुरू की जा चुकी है। एकीकृत रोग निगरानी नेटवर्क के माध्यम से ऐसे सभी व्यक्तियों का पता लगाया जाता है और इस समय 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 9452 यात्रियों पर नजर रखी जा रही है। राज्य निगरानी अधिकारियों, जिला निगरानी अधिकारियों और स्वास्थ्य पेशेवरों की रेपिड रिस्पोंस टीमों द्वारा राज्य स्वास्थ्य सचिवों के नेतृत्वों में दैनिक आधार पर ऐसे लोगों की निगरानी की जा रही है। देश भर में किसी प्रकार के प्रकोप प्रबंधन के लिए तृतीयक स्वास्थ्य केन्द्रों में पर्याप्त संख्या में अलग एकाकी बिस्तर उपलब्ध

करवाए गए हैं। लक्षणग्रस्त 369 यात्रियों को एकाकी केन्द्रों में रेफर किया गया है और उन पर निगरानी रखी जा रही है।

मंत्रालय ने स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्रों में राज्यों को निगरानी और संपर्क ट्रेसिंग, प्रवेश स्थलों पर निगरानी, प्रयोगशाला सैंपल संग्रहण, पैकेजिंग और परिवहन, क्लीनिकल प्रबंधन प्रोटोकॉल तथा संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण में सहायता प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) और एन95 मास्क जैसे महत्पवूर्ण मदों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इनके निर्यात को विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों और एन95 मास्क का बफर स्टॉक राज्यों के साथ-साथ केन्द्र सरकार द्वारा रखा जाता है।

राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, पुणे नोडल प्रयोगशाला है। आईसीएमआर की उत्पन्न/पुन: उत्पन्न होने वाले संक्रामक रोगों के प्रति तैयारी के भाग के रूप में एनआईवी, पुणे ने एनसीओवी के मॉलिक्यूलर निदान हेतु क्षमता स्थापित की है। नेक्स्ट जनरेशन सिकेंव्निसंग कार्य की भी व्यवस्था की गई है। नैदानिक नमूनों की जांच 11 और प्रयोगशालाओं में भी शुरू की जा चुकी है। इस समय 1510 नमूनों की जांच की जा चुकी है और उनमें से 1507 नमूने ठीक पाए गए और 3 नमूने रोग वाहक पाए गए तथा 27 नमूनों की जांच चल रही है।

(1220/SK/RK)

जोखिम संप्रेषण सामग्री तैयार की जा चुकी है और राज्यों के माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसार किया जा रहा है। समुदाय में विशेषज्ञों द्वारा रेडियो और टीवी के माध्यम से तकनीकी ब्रीफिंग के जरिए अपेक्षित जागरुकता सुनिश्चित की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रोज प्रेस ब्रीफिंग की जा रही है और सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना साझा की जा रही है। 24x7 नियंत्रण कक्ष कार्य कर रहा है, जिसका नंबर है - 011-23978046.

भारत सरकार विश्व स्वास्थ्य संगठन मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय और देश में स्थित कार्यालय के साथ नियमित सम्पर्क बनाए हुए है ताकि उत्पन्न परिदृश्य की अद्यतन जानकारी प्राप्त हो सके।

भारत सरकार ने नोवल कोरोना वायरस रोग से उत्पन्न चुनौती का सामना करने के लिए अन्य देशों को भी सहायता उपलब्ध कराई है। आईसीएमआर ने दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रीय सहयोग के सदस्य देशों के समक्ष नमूनों की जांच का प्रस्ताव रखा है। मालदीव से प्राप्त नमूनों की जांच भी भारत में शुरू की जा चुकी है। अफगानिस्तान से नमूनों की जांच संबंधी अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है। हम इस संक्रामक रोग के उपचार और यात्रियों की जांच हेतु भूटान को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए भी सहमत हो गए हैं।

भारत सरकार स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है तथा नोवल कोरोना वायरस के संचरण से बचने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रही है।

माननीय अध्यक्ष: मद संख्या 26।

…(व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, this matter requires a detailed discussion, for which I have given a notice under Rule 193. Also, a Calling Attention Notice has already been issued. I know that as per Rule 372, seeking clarification is not permitted.…(*Interruptions*) The matter is very serious and is of urgent importance as the State of Kerala has been affected. Three patients have already been identified. I would like to know from the hon. Minister, whether the Ministry of Health and Family Welfare will send a team …(*Interruptions*) I know it.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप नोटिस दें, आसन इस पर निर्देश दे देगा।

…(व्यवधान)

श्री विनायक भाउराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): माननीय अध्यक्ष जी, चाइना से जो वैसल आया है, उसमें 22 चीनी कर्मचारी हैं,…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपका विषय गंभीर है, आप नोटिस दे दें, मैं इस पर बात करूंगा, आप सबसे चर्चा करूंगा।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मद संख्या 27, श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी।

STATEMENT RE: CORRECTING ANSWER GIVEN TO UNSTARRED QUESTION NO. 2261 DATED 2nd DECEMBER, 2019 - LAID

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI ANURAG SINGH THAKUR): Sir, I beg to lay a Statement correcting the Hindi reply to Unstarred Question No. 2261 given on 2nd December, 2019 asked by Shri Deepak Baij and Shri Subbarayan K., MPs regarding 'Demonetisation'.

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 106TH AND 112TH, 107TH AND 113TH REPORTS OF STANDING COMMITTEE ON HEALTH AND FAMILY WELFARE - LAID

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE, MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF EARTH SCIENCES (DR. HARSH VARDHAN): Sir, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 106th and 112th & 107th and 113th Reports of the Standing Committee on Health and Family Welfare on Demands for Grants 2018-19 pertaining to the Department of Health and Family Welfare and Department of Health Research respectively, Ministry of Health and Family Welfare.

_____

INSTITUTE OF TEACHING AND RESEARCH IN AYURVEDA BILL

1224 hours

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the establishment of an Institute of Teaching and Research in Ayurveda and to declare it as an Institution of national importance for the promotion of quality and excellence in education, research and training in Ayurveda and allied disciplines and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान की स्थापना और उसे आयुर्वेद और सहबद्ध शाखाओं शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण की क्वालिटी तथा उत्कृष्टता के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषित करने तथा उससे सम्बन्धित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापति करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, I have given a notice to oppose the introduction.

माननीय अध्यक्ष: श्री सौगत राय जी।

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, under Rule 72(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I oppose the introduction of the Institute of Teaching and Research in Ayurveda Bill, 2020.

My objection is related to setting up of the institute at Jamnagar in Gujarat. I had protested earlier also when the GIFT City was established at Ahmedabad. (1225/MK/PS)

So, in this country, whatever new will be set-up, will be established in Gujarat. …(*Interruptions*) Why only Gujarat? …(*Interruptions*) Sir, listen to me. Kerala and Bengal have a glorious ayurvedic traditions. So, why do they not set-up the same Institute in Kolkata instead of Gujarat? …(*Interruptions*) Sir, will you allow this? …(*Interruptions*) Is this related to the present topic? …(*Interruptions*) Whatever they are saying, is it related to the present matter?

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, प्लीज बैठ जाइए।

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष: यह गलत परम्परा है। प्लीज बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्लीज बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): That is why, I am saying that this Institute should not be set-up at a far-away place in Jamnagar, Gujarat. Instead, it should be placed either at the centre of the country, that is, in New Delhi, or at places which have got glorious traditions in Ayurvedic research and teaching, that is, in Varanasi, Kerala or West Bengal.

That is why, I oppose the introduction of this Bill to set-up an Institute at Jamnagar. I also object to the way some hon. Members from the Ruling Party stood up and showed some posters while I was speaking. In your dispensation, such things should not be allowed. …(*Interruptions*) Such things should not be allowed. …(*Interruptions*) आप व्यवस्था दीजिए कि ऐसा न किया जाए। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: एक मिनट, प्लीज बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आज सदन के अंदर सभी माननीय सदस्य हैं। आज इस बात पर चर्चा हो जाए कि क्या पोस्टर लाना जरूरी है? नहीं है न? माननीय अधीर रंजन जी क्या आपकी सहमति है?

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): पहले मुझे अपनी बात तो कहने दीजिए।

माननीय अध्यक्ष: आप बोलिए। आप सहमति देंगे तो मैं सभी सदस्यों से कहूंगा कि पोस्टर बाहर जाए और जो सदन में पोस्टर लाएंगे, तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। आप बताएं, क्या आप इससे सहमत हैं?

…(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): सरकार की तरफ से हम पूरे सहमत हैं कि सदन के अंदर पोस्टर, बैनर वगैरह नहीं लाना चाहिए। आपने जो सुझाव दिया है। हम पूरे उसके पक्ष में हैं।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: दादा तो ऐसे ही सहमत हैं।

…(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम): हम लोग समर्थन करते हैं। …(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): हमारे लीडर बाहर कुछ कहते हैं तो यहां आकर खुद मंत्री जी सदन के अंदर उनका अपमान करते हैं। यह भी बंद होना चाहिए।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं पोस्टर की बात कर रहा हूं।

…(व्यवधान)

श्री प्रहलाद जोशी: अगर यह विषय उठाना है तो उन लोगों के वक्तव्य के बारे में भी हम बोलना चाहते हैं।...(व्यवधान)

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): I have given a notice for opposing the introduction of the Bill on three following grounds:

Firstly, the Bill seeks to conglomerate three institutes under the Gujarat Ayurved University at Jamnagar, as one institution and confers it with the status of an Institute of National Importance. This selective conferment of the status of the Institute of National Importance leads to an unreasonable classification because it treats identically-recognised ayurvedic institutes in India, unequally.

The second reason is that the Bill fails to define the term or the criteria for an institution to become an Institution of National Importance, thereby giving rise to arbitrariness in the exercise of conferring this status.

The third reason is that the Bill fails to meet the larger objective of the promotion of quality and excellence in education, research and training in Ayurveda as mentioned in the Title of the Bill. By according the status of Institute of National Importance only to one institution while overlooking the Government Ayurveda College in Thiruvananthapuram -- which despite being established much before the Gujarat Ayurveda University in 1889 has not even been upgraded let alone being considered for the status of Institute of National Importance -- has resulted in the failure to establish a nexus between the classification made and the objects sought to be achieved by the Bill. For these three reasons, hon. Speaker, Sir, the Fundamental Right to Equality under Article 14 of the Constitution stands violated.

I, therefore, wish to oppose the proposed Bill and I request your permission, hon. Speaker, Sir, to elaborate upon these submissions before the House in a full discussion, as permitted by the proviso to Rule 72(1) so that the Motion of introduction is not allowed without a full discussion. Thank you, hon. Speaker.

श्री श्रीपाद येसो नाईक: अध्यक्ष महोदय, इस इंस्ट्रियूशन के बारे में जैसे दादा जी ने कहा कि यह तो एक कोने में है। मेरे ख्याल से बंगाल, केरल और गुजरात तो और सेंट्रलाइज है।

(1230/YSH/RC)

माननीय अध्यक्ष : दादा नहीं, माननीय सदस्य कहिए।

श्री श्रीपाद येसो नाईक: माननीय सदस्य माफ कीजिए। सर, इस इंस्टिट्यूशन के बारे में आप जानते हैं कि आप लोगों के सहयोग से आज आयुर्वेद इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन हर दिन बढ़ती जा

रही है। This Institution was started in 1952 as a Central Institute of Research in Indigenous System of Medicine. In 1956, a Post Graduate Centre was started by the Central Government. In 1962, both these Institutions were merged and one Institution was started called Ayurveda Studies and Research. In 1967, the Post Graduate Centre became an integral part of the University. It has a WHO collaborating centre. This Centre has UG, PG pharmacy in Ayurveda. It is also running a Yoga Institution in collaboration with Meharshi Patanjali Institute of Yoga and Naturopathy. This Institution has published a number of publications in Ayurveda. A maximum number of publications have been issued by this Institution. These have been published in highly reputed journals. यह इनका इतिहास है। मैं माननीय सदस्य को मना करता हूं। यह आपके सहयोग से तो अभी शुरू हो रहा है। आप आज जो भी कह रहे हैं, उस पर निश्चित ही विचार भी करेंगे।...(व्यवधान) आपकी ओर से तो प्रपोजल आने दीजिए। उसके बाद हम निश्चित रूप से इस पर विचार करेंगे। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप चेयर को संबोधित करके बात कीजिए।

...(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

> " कि आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान की स्थापना और उसे आयुर्वेद और सहबद्ध शाखाओं शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण की क्वालिटी तथा उत्कृष्टता के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषित करने तथा उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित किए जाने की अनुमति प्रदान की जाए। "

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

SHRI SHRIPAD YESSO NAIK : Sir, I introduce the Bill.

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, I had asked for a full discussion. You have not ruled it out.

माननीय अध्यक्ष : आप चर्चा के समय अपनी बात को स्पष्ट कर देना।

प्रमोशन में रिज़र्वेशन विषय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में

1234 बजे

माननीय अध्यक्ष : श्री अधीर रंजन चौधरी।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, मैं एक गंभीर मुद्दा उठाना चाहता हूं। मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। सर, बात यह है कि उत्तराखण्ड सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह तर्क दिया गया था कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षण है, उसको हटा दिया जाना चाहिए। सर, मुकेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ उत्तराखण्ड का विषय सुप्रीम कोर्ट के अधीन था और इसमें बहस के दौरान प्रमुखता से दो चीजें सामने आई थीं। पहली यह कि अनुसूचित जाति एवं अनूसूचित जनजाति के व्यक्तियों का सरकारी पदों की भर्ती पर उनका कोई मौलिक अधिकार नहीं है। दूसरा यह कि सरकार का कोई संवैधानिक कर्त्तव्य नहीं है कि वह अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की सरकारी पदों पर नियुक्ति के लिए आरक्षण की व्यवस्था करे।

सर, आप जानते ही है कि सदियों से हमारे देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ भेदभाव चलता आ रहा है। आजादी के बाद हमारे संविधान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की संख्या, जो पूरी आबादी की एक तिहाई है, हमने इन सभी को संरक्षण देने के साथ ही इनके अधिकारों को निश्चित करने का काम किया है। सर, हमारे जमाने में शिड्यूल कास्ट सबप्लान, शिड्यूल ट्राइब सबप्लान और स्वर्गीय राजीव गांधी जी तो जो शिड्यूल कास्ट पर एट्रोसिटी होती थी, उस पर एक्ट भी लेकर आए थे। आज इस सरकार को क्या हो गया है? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए जो 15 और 7.5 प्रतिशत आरक्षण है, उस आरक्षण के अधिकार को सरकार छीनने की कोशिश क्यों कर रही है?...(व्यवधान) सर, मैं पढ़ देता हूं।...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): सर, इसमें सरकार का कोई लेना-देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है। माननीय सोशल वेलफेयर मिनिस्टर सवा दो बजे एक स्टेटमेंट देंगे, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इसका सरकार से कोई लेना-देना नहीं है। ...(व्यवधान) सर, उत्तराखण्ड में वर्ष 2012 में किसकी सरकार थी, इसका उत्तर देना पड़ेगा। वर्ष 2012 में कांग्रेस की सरकार थी। इसलिए मैं बता रहा हूं कि इसमें भारत सरकार का कोई लेना देना नहीं है फिर भी माननीय सोशल वेलफेयर मिनिस्टर सवा दो बजे एक स्टेटमेंट देंगे।...(व्यवधान)

(1235/RPS/SNB)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, यह सरकार जो राष्ट्रवाद की बात करती है, *... (Not recorded)*...(व्यवधान)

श्री प्रहलाद जोशी: सर, इस बात को एक्सपंज करना चाहिए। अधीर रंजन चौधरी जी सरकार के खिलाफ जो कुछ बोल रहे हैं, यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसमें सरकार का नाम लेना बिल्कुल ठीक नहीं है।...(व्यवधान) 2012 में किसकी सरकार थी उत्तराखण्ड में? ...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, क्या यह विपक्ष के साथ सही वार्ता हो रही है? …(व्यवधान) आप बताइए। यह सरकार की तरफ से क्या रखा गया है? The Uttarakhand Government contended that there is no Fundamental Right to claim reservation in appointments or promotions in public posts. …(*Interruptions*) There is no constitutional duty on the part of the State Government to provide reservation. What does this mean? Who are these people? …(*Interruptions*) उत्तराखण्ड की तरफ से कौन सुप्रीम कोर्ट में गया? …(व्यवधान) कौन सा वकील वहां गया, किसका पक्ष रखा? …(व्यवधान) यह आपको सदन के अंदर बताना चाहिए।

श्री प्रहलाद जोशी: सर, वर्ष 2012 में कांग्रेस की सरकार के द्वारा यह हुआ है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जो कुछ भी भारत सरकार के खिलाफ अन-नसेसरली इन्होंने कमेंट्स किए हैं, उनको एक्सपंज करना चाहिए। …(व्यवधान) इसको एक्सपंज किया जाना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष: हां, कर दिया जाएगा।

श्री चिराग पासवान जी।

श्री चिराग पासवान (जमुई): धन्यवाद, सर। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया है।

सर, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बीच हुए पूना पैक्ट का ही परिणाम है कि अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग से आने वाले लोगों के लिए आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है। आरक्षण किसी को मिली हुई खैरात या दया नहीं है, यह एक संवैधानिक अधिकार है।

1237 बजे

(इस समय श्री गौरव गोगोई और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

आज यह इस सदन में चर्चा करने का कारण इसलिए बना कि जिस तरीके से 7 फरवरी, 2020 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ये फाइंडिंग्स दी गईं, जिनमें कहा गया कि आरक्षण, चाहे सरकारी नौकरियों में या प्रमोशन में, एक मौलिक अधिकार नहीं है।

सर, लोक जनशक्ति पार्टी पूरी तरह से, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए इस दिशानिर्देश को खारिज करती है, उसके साथ हम लोग सहमत नहीं हैं। मैं आग्रह करूंगा कि हमारी केन्द्र सरकार इस विषय पर हस्तक्षेप करे और आरक्षण से जुडे हुए जितने कानून हैं, उनको वन्स एंड फॉर ऑल, 9वीं सूची में डालने का काम करें, ताकि समय-समय पर, रह-रहकर जो लोग न्यायालय में जाकर आरक्षण के बारे में प्रश्न-चिह्न उठाने का काम करते हैं, उनके लिए यह डिबेट ही हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। सर, मंडल कमीशन लागू होने के बाद समय-समय पर …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री टी. आर. बालू जी।

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, Shri Raja is speaking on the same subject. I will speak later on.

माननीय अध्यक्ष: आप मुझसे मिले थे, आपने कहा था कि मैं यह विषय उठाना चाहता हूं। क्या आप यह विषय उठाना चाहते हैं?

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नहीं, यह गलत बात है।

चिराग पासवान जी, आप बोलिए।

श्री चिराग पासवान (जमुई): सर, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इसको 9वीं सूची में डाला जाए ताकि समय-समय पर आरक्षण को लेकर जो लोग न्यायालय में चले जाते हैं, वन्स एंड फॉर ऑल वह डिबेट ही समाप्त हो जाए।

सर, जब मंडल कमीशन लागू हुआ, वह भी कहीं न कहीं आरक्षण की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लागू किया गया, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने देखा कि 2 नवम्बर, 1992 को …(व्यवधान) सर, मुझे दो मिनट का समय दीजिए। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। …(व्यवधान)

1238 बजे

(इस समय श्री गौरव गोगोई और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, article 16 (4) clearly talks about reservation for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and also for the Other Backward Classes. This article 16(4) is a part of the Fundamental Rights under part III of the Constitution. Therefore, the contention which was made before the Supreme Court by the AG Counsel on behalf of the State of Uttarakhand, was not correct and the Uttarakhand Government is being run by the Bhartiya Janta Party …(*Interruptions*)

(1240/RU/IND)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं कि वर्ष 2012 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी। उस सरकार ने यह डिसीजन लिया और उसके साथ पीआईएल आई। भारत सरकार का इस विषय में कोई लेना-देना नहीं है। भारत सरकार आरक्षण के प्रति कटिबद्ध है। मेरा कहना है कि चिराग पासवान जी को अपनी स्टेटमेंट पूरी करने दी जाए।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से जब यह निर्णय होगा कि हम वक्तव्य देंगे। मेरा कहना है कि इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, सुप्रीम

कोर्ट का निर्णय है। फिर भी सरकार कह रही है कि हम अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे। निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, यह सरकार का निर्णय तो नहीं है।

…(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): अध्यक्ष जी, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत सरकार का इसमें कुछ लेना-देना नहीं है। वर्ष 2012 में उत्तराखंड सरकार ने निर्णय लिया था। उस समय उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस सरकार ने निर्णय लिया था। उसके ऊपर पीआईएल हुई। इस विषय में भारत सरकार को कटघरे में खड़ा करना बिल्कुल ठीक नहीं है।…(व्यवधान)

श्री चिराग पासवान (जमुई): अध्यक्ष जी, बार-बार इस तरह की जो बातें कही जाती हैं कि यह सरकार आरक्षण विरोधी है, यह सरकार दलित विरोधी है, यह ठीक नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि थोड़ी गंभीरता से इन बातों का जिक्र किया जाए, क्योंकि इन बातों का प्रभाव देश भर की जनता पर पड़ता है। बहुत बड़ी आबादी अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग से आती है। ऐसी बातें करके आप उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। यदि आरक्षण विरोधी हमारी एनडीए की सरकार होती, तो आरक्षण को जो मजबूत करने का काम किया गया, ऊंची जाति के गरीब वर्ग के लोगों को भी जो आरक्षण देने का काम किया गया, वह काम हमारी सरकार न करती। हमारी सरकार ने आरक्षण प्रणाली को मजबूत करने का काम किया। जब अनुसूचित जाति, जनजाति एट्रोसिटी एक्ट को दंतहीन करने का प्रयास किया गया, तो हमारी सरकार और लोक जनशक्ति पार्टी पहली पार्टी थी, जिसमें हम लोगों ने पुनर्विचार याचिका डाली। सरकार ने हाउस का समय दो-तीन दिन एक्सटेंड करके उस कानून को लोक सभा और राज्य सभा से भी पास कराया। हमारी सरकार पूरी तरह से आरक्षण को लेकर कटिबद्ध है। आरक्षण को समाप्त करना तो दूर की बात है, उस पर चर्चा की भी गुंजाइश नहीं हो सकती है।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. किरिट पी. सोलंकी और श्री प्रिंस राज को श्री चिराग पासवान द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): Mr. Speaker Sir, let the Members of the Treasury Benches have patience to hear us.

There are reasons to believe that ever since the inception of this Government, there is a continuous onslaught on the policy of reservation and social justice.…(*Interruptions*) I will come to you.…(*Interruptions*)

SHRI PRALHAD JOSHI: You cannot say like this. Why are you talking against the Government now? What is the role of the Government in that? …(*Interruptions*) Shri Raja, you are a learned and senior Member. Do not try to attribute it to the Government. …(*Interruptions*)

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): The political entity of the Uttarakhand Government and this Government is one and the same. It is identical. Nobody can deny it.

The argument that has been advanced before the Supreme Court on behalf of the BJP Government in Uttarakhand.…(*Interruptions*) It is on record. Is it not your Government? (*Interruptions*) It is an argument that has been advanced before the Supreme Court on behalf of the Uttarakhand Government which is a BJP Government. Senior advocates appeared before the Supreme Court and they were categorical and paved way to the Supreme Court by claiming and arguing that reservation of SCs and STs is neither a fundamental right nor a constitutional right. …(*Interruptions*) Article 16(4) and Article 16(4)(a) are enabling provisions for reservation to socially and educationally backward classes including OBCs, BCs, Scheduled Castes, Scheduled Tribes and others. (1245/NKL/ASA)

Sir, it has been settled in the B.K. Pavitra Case in the Supreme Court, with the larger Bench, not to go for any opinion of the State, not to go for any enumeration work. It is immaterial whether the socially or educationally backward people, BCs, SCs and STs, have been adequately represented or not. They are entitled for reservation by birth. That has been settled in the B.K. Pavitra Case. As against this Judgment, now, a new Judgment came into existence. So, I urge upon the Government. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : लम्बी डिबेट थोड़े ही करनी है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : राजीव रंजन जी, एक मिनट। अगर आप इस पर चर्चा करना चाहते हैं तो आप नोटिस दें। नियम प्रक्रिया के तहत अगर होगा तो एलाउ किया जाएगा। सबको बोलने का अधिकार है। आपको अधिकार है तो सबको है। राजीव रंजन जी, आप बोलिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप एक मिनट में बोलिए। बालू जी, आप तो हर विषय सुबह लेकर आते हैं, शाम को बोलते हैं।

…(व्यवधान)

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): Sir, if the Central Government really have an inclination towards the people belonging to OBC, SC, ST to ensure their social justice, there are two options. Let them file a Review Petition before the Supreme Court or let them prepare a special legislation and include it in the Ninth Schedule. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले को श्री ए.राजा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह (मुंगेर): माननीय अध्यक्ष जी, 7 तारीख को जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है, यह विषय बहुत संवेदनशील है और हम समझते हैं कि इस सदन में कोई भी दल और कोई भी सदस्य इस विषय पर दो मत नहीं है। …(व्यवधान) पूरा सदन एकमत है और जब पूरा सदन एकमत है और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है तो ऐसे संवेदनशील मामलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।…(व्यवधान) राजनीति करने का प्रयास नहीं होना चाहिए।…(व्यवधान)

जब एससीएसटी एक्ट के बारे में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया था तो सदन के बाहर पूरे देश में भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया और सरकार ने अध्यादेश लाकर यह साबित किया कि सरकार की मंशा क्या है। …(व्यवधान) ऐसे मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए और हम समझते हैं कि सरकार इस मामले को भी सुलझाने में सक्षम है और सरकार सुलझाएगी।…(व्यवधान)

1247 hours

(*At this stage, Shri Kodikunnil Suresh, Shri T.N. Prathapan and some other hon. Members came and stood near the Table.*)

नियम 377 के अधीन मामले – सभा पटल पर रखे गए

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यों, आज नियम 377 के अधीन मामले को उठाने की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। वे अपने मामलों पर अनुमोदित पाठ को व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रखें।

Re: Need to review the decision to phase out IASE, CTE and DIET from 1 April, 2020

श्री रामचरण बोहरा (जयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान स्कूली शिक्षा मैं गुणवत्ता सुधार की तरफ आकर्षित करना चाहूँगा। वर्तमान सरकार हमेशा से ही स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में सुधार को लेकर प्रयासरत रही है। इसी कड़ी में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत राजस्थान सहित सम्पूर्ण देश मैं सर्व शिक्षा अभियान योजना लागू की गयी थी। इसी योजना के तहत सम्पूर्ण देश में राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बालक बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ नवाचारों एवं प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों का कौशल विकास करना था ताकि देश में साक्षरता दर बढ़ सके एवं गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा मिल सके।

अध्यक्ष महोदय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार मानव संसादन विकास मंत्रालय ने देश भर में शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए अनेक प्रयास किए हैं जिसमे एक प्रयास देश भर मैं राजकीय शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए केंद्र सरकार परवर्तित योजना के तहत आई ए एस ई. सी टी ई. डाइट जैसे संस्थाओं का गठन कर शिक्षा में आमलचल परिवर्तन लाने का प्रयास किया है किन्त मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा समग्र शिक्षा अभियान की गाइड लाइन में 14 वे वित आयोग की समाप्ति पर आई ए एस ई, सी टी ई डाइट जैसी संस्थाओं को 1 अप्रैल 2020 से फेज आउट किए जाने की योजना बना रहा है। इन परीक्षण संस्थाओं को फेज आउट किए जाने से आई ए एस ई, सी टी ई डाइट संस्थाओं को ही 31 मार्च 2020 के बाद समग्र शिक्षा अभियान से बाहर किया कर दिया जाएगा। अप्रैल 2020 में यदि उपरोक्त संस्थाओं को बाहर कर दिया जाएगा तो राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने एव शिक्षा की गुणवत्ता सुधार पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा इसके अतिरिक्त इन संस्थाओं को फेस आउट किए जाने से इन संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को राज्य के उच्च शिक्षा संस्थाओं में समायोजित करने से मानव संसाधन विकास मंत्रालय की उपरोक्त योजनाओं के सफल क्रियान्वयन पर भी विराम लग जाएगा। अध्यक्ष महोदय इस समय सम्पूर्ण देश में 152 सी टी ई और 28 आई ए एस ई संस्थान संचालित हैं। राजस्थान राज्य के 8 सी टी ई संस्थाओं में कार्यरत कार्मिकों को विगत कई माह से वेतन एव अन्य भत्तों का भुगतान भी नहीं किया जा रहा है तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा लगातार इन्हे फेस आउट किए जाने के संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किए जाने से इन संस्थानों में कार्यरत कार्मिकों की कार्य क्षमता प्रभावित हो रही है। अध्यक्ष महोदय राजस्थान राज्य समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्य मे क्रमोनत 8 सी

टी ई संसथाओं के सी एस एस के स्वीकृत पदों पर कार्यरत कर्मियों के वेतन में अपना निर्धारित राजयांश 2018-19 में 58 प्रतिशत एंव 2019-20 में 64 प्रतिशत व्यय नहीं कर रहा है जिससे इन संस्थाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

अत: अध्यक्ष महोदय मेरा आपके माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध है कि राजकीय विधालयों में अध्ययनरत बालक बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत उपरोक्त संस्थाओं को फेज आउट किए जाने के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के फैसले पर पुनर्विचार करने की कृपा करें।

(इति)

Re: Need to fix the norms for banana crop under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana

श्रीमती रक्षा निखिल खडसे (रावेर): महाराष्ट्र राज्य ने इस वर्ष 2019-20 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) के तहत केले फल के अंबिया बहार के पैरामीटर नॉर्म गठित किये हैं जो कि इन्शुरन्सकंपनी को ज्यादा फायदा हो ऐसे प्राथमिकता में दिख रहे हैं । इस नये पैरामीटर में ठंडे मौसम कम टेम्परेंचर व दिन के लिए कोई बदलाव नहीं लेकिन इन्शुरन्स क्लेम की राशि जो पर हैक्टर दी जाती है उसे बड़े तौर पर कम किया है तथा गर्मी मौसम (ज्यादा टेमपटेंचर) की रेंज को बढ़ाते हुए 40.5 से 44 की जगह 42 से 45 डिग्री सेल्सियस तथा 3 दिन से 5 दिन तक बटाई है | मेरे जलगाँव जिल्हे में अधिकतम कृषि क्षेत्र में केले की खेती करने वाले किसान है। इस नये फसल बीमा योजना के पैरामीटर में संबंधित प्रतिकुल मौसम के परिणामस्वरप संभावित फसल हानि से होने वाली वितीय हानि मिलने की कोई संभावना नहीं दिखाई देती मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करती हूँ कि किसान की कठिनाई कम हो और प्रतिकूल मौसम में फसल हानि से होनेवाली वितीय हानि कम से कम उसे मिल सके ऐसे केले फल के अबिया बहार के पैरामीटर नॉर्स (RWBCIS) से गठित करने की सिफारिश राज्य सरकार से करें।

(इति)

Re: Economic condition of weavers in Bankura Parliamentary Constituency, West Bengal

DR. SUBHAS SARKAR (BANKURA): Recently concluded Census in 2019 shows the precarious economic condition of Handloom workers in West Bengal with *65%* of Weaver households earning less than Rs. 5000/month. In my parliamentary constituency Bankura, situation is more serious. Earnings per weaver for one *Gamchha* is a meagre Rs.20-25 and one produces 2-3 pieces a day.

Earnings being less than the MNGREGA wages for unskilled labourers and often lower than the daily wages of construction workers or auto rickshaw drivers, their economic status is lower than that of unskilled casual labourers in the unorganized sector.

Workers are shifting from handloom to other occupations in urban areas like construction, shop- keeping and transport (mainly auto-rickshaws). The Clusters in most cases are functioning with much less than the declared number of weavers or not functioning at all.

I request the Ministry of Textiles to look into the matter and take measures so that the economic condition of the weavers in Bankura could improve.

(ends)

Re: Need to set up a committee to review the NCERT history books

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): भारत वर्ष जिसका शाब्दिक अर्थ ऐसा क्षेत्र जो ज्ञान के प्रकाश से प्रज्जवलित हो। ज्ञान के प्रमाणीकरण का संस्कार भारतीय संस्कृति की मौलिकता है। परिणाम स्वरूप भारत में परिष्कृत विचारो का निरंतर संरक्षण एवं संवर्धन होता रहा है। परंतु NCERT की इतिहास की विभिन्न कक्षाओ की पुस्तकों में उल्लिखित पाठ्य सामग्रियों में और वेदो में वर्णित जानकारियों में विरोधाभास है। यहाँ पर यह कहना उचित ही होगा कि वैदिक काल से संबन्धित ज्ञान की प्रामाणिकता का सबसे मजबूत साक्ष्य आधार वेद ही है। क्योंकि इस काल के पुरातात्विक साक्ष्यों की उपलब्धता दुर्लभ है। इस लिए इन विसंगतियो को दूर करना बहुत जरूरी है। कुछ आपत्तियां इस प्रकार है:

1. कक्षा 6 की इतिहास की पुस्तक में पृष्ठ 4 पर उल्लिखित है की भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगो के लिए किया जाता था परंतु ऋग्वेद में भरत शब्द है और इसको क्रिया के रूप में लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है धारण करना। देश का नाम जिस शब्द पर पड़ा है उसके संदर्भ में भ्रामक तथ्य को पढ़ाया जाना शोचनीय

2. कक्षा 6 की इतिहास की पुस्तक में पृष्ट 72 पर यह बताया गया है कि बुद्ध काल में वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया गया था जबकि वर्ण व्यवस्था वैदिकोतर न हो कर वैदिक कालीन है। और इसका उल्लेख वेदों में हुआ है।

इसी तरह की अनेक विसंगतियां है जिनका निराकरण करना अत्यंत आवशयक है और पूर्व में भी मेरे द्वारा मंत्रालय को कई बार अवगत कराया गया है। अतः पुनः मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से यह अनुरोध करता हूँ कि सभी विरोधाभासी तथ्यो की समीक्षा के लिए एक जांच कमेटी का निर्माण किया जाये जिससे देश का सही इतिहास सभी के सामने लाया जा सके।

(इति)

Re: Need to construct a bye-pass road in Dhanbad city, Jharkhand

श्री पशुपति नाथ सिंह (धनबाद): मेरे संसदीय क्षेत्र का मुख्यालय धनबाद है। राष्ट्रीय राजमार्ग 32 धनबाद शहर के बीचों बीच स्थित सड़क से कोर्ट कचहरी, रेलवे स्टेशन, प्रमुख बाजार होते हुए गुजरता है जिससे आए दिन बड़ी संख्या में दुर्घटनाएं हो रही हैं तथा प्रतिदिन सड़क जाम की समस्या भी बनी रहती है जिससे धनबाद के बीच गुजरते राष्ट्रीय राज्य मार्ग पर आने जाने में लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। इस समस्या से निपटने के लिए धनबाद शहर के बाहर बाई पास का निर्माण कार्य लोकहित में बनाना अति आवश्यक है।

अतः सरकार से मांग करता हूँ कि धनबाद शहर के बाहर से बाईपास रोड बनाया जाए जिससे शहर के बीच जाने वाले यातायात को बाई पास से होकर चलाया जा सके एवं शहर में होने वाले जाम एवं होने वाली दुर्घटनाओं से मुक्ति मिल सके।

(इति)

Re: Need to set up a Central University in Darjeeling, West Bengal

SHRI RAJU BISTA (DARJEELING): Darjeeling is a hub of education, not only in India, but also across the South and South-East Asian countries. It is home to some of the best schools in India and students from all over Asia come to study in the hills.

However, in terms of higher education, this region lags behind as compared to the rest of India. Lack of higher education facilities have seen huge proportions of brain drain from the region. The best and the brightest from this region are forced to take their knowledge, skills and passion elsewhere.

Institutions of higher and technical learning have been a long standing aspiration and pertinent demand of the people. Establishing a Central University in Darjeeling will turn it into one of the hubs for higher education in India, and in South and South East Asia. This will greatly compliment Government's 'Act East Policy'.

(ends)

Re: Need to correct the land records in Sikar and other districts of Rajasthan

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): सीकर जिले सहित राजस्थान के अनेक ग्रामों को प्रशासनिक भूल से वन विभाग की भूमि में दर्शा दिये गए। महोद्य ये ग्राम 500 वर्ष से भी अधिक समय से बसे हुये थे। इन गाँववासियों के पास नित्य प्रतिदिन वन विभाग के नोटिस आते रहते हैं, कि आप यह स्थान खाली करो। यह ग्रामवासी कोई भी सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। मैं अनेक बार इस विषय में अधिकारियों को पत्र लिख चुका हूँ। परंतु इस समस्या का समाधान नहीं हो सका है। अत: मेरा वन एंव पर्यावरण मंत्री जी से निवेदन है कि इस समस्या का अतिशीघ्र समाधान करवाने का श्रम करें ताकि लोग सुख से रह सकें।

(इति)

Re: Setting up of a Passport Seva Kendra in Kolar, Karnataka

SHRI S. MUNISWAMY (KOLAR): Kolar is a very progressive district of Karnataka which housed Asia's first gold mine and has been progressing rapidly since several decades. Many MNCs have their establishments in order to benefit from a positively encouraging environment. Therefore, the demand for passport will increase in the days to come. It is also important that many young talents from Kolar district should be able to get their passports in time if they desire to make use of opportunities available globally.

I request the Government to establish a Passport Seva Kendra in Kolar.

(ends)

Re: Need to provide money through DBT to school children for Mid-day Meal

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): अध्यक्ष महोदय, हम सभी जानते है कि सर्व शिक्षा अभियान सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के उद्देश्य से कि थी जिसके कई उल्लेखनीय परिणाम सामने आए है। परंतु इन दिनो "मध्याहन भोजन योजना" अपनी उपलब्धियों को लेकर नहीं बल्कि, दूषित भोजन परोसने, अनियमितताओ व सामाजिक भेदभाव की वजह से ज्यादा चर्चा में रहता है। महोदय, दुख के साथ सदन को बताना चाहती हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र अंतर्गत शिवहर, सीतामढ़ी एवं पूर्वी चंपारण जिले सहित बिहार के लगभग सभी सरकारी स्कूलो में सर्व शिक्षा अभियान के तहत जारी मध्याहन भोजन कार्यक्रम में भारी अनियमितता व्याप्त है। इस कारण सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष करोड़ो रुपये खर्च किए जाने के बावजूद यहाँ के सरकारी विध्यालयों एवं इसमें पढ़ने वाले बच्चो की दशा में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। क्षेत्र भ्रमण के क्रम में ऐसे कई मामले सामने आये है जिसमें विद्यालयो में शिक्षको द्वारा छात्रो की वास्तविक उपस्थिति से अधिक संख्या दर्शायी जाती है। कई स्कूलो के शिक्षक तो पठनपाठन का कार्य छोड़कर सिर्फ मिड डे मील के रजिस्टर मेंटेन करने की खानापूर्ति में लगे रहते है। इससे बच्चो के शिक्षा भी प्रभावित हो रही है। जो खाना बच्चो के लिए बनाया जाता है वह सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरूप नहीं होते और उस में गुणवत्ता की भारी कमी होती है। मेरा मानना है कि सरकार की अन्य योजनाओ के तर्ज पर बच्चो के लिए DBT के माध्यम से मध्याहन भोजन की राशि के आबंटन का विचार करे तो बेहतर होगा।

अतः सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध होगा कि मध्याहन भोजन योजना में व्याप्त अनियमितताओ को देखे हुए इसके निवारण हेतु ठोस कदम उठाते हुए बच्चो के लिए DBT के माध्यम से मध्याहन भोजन की राशि उपलब्ध कराई जाये जिससे कि सरकार द्वारा बच्चो को शिक्षा के साथ भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश की पूर्ति हो सके |

(इति)

Re: Need to provide a rake point near Maharajganj and Chainwa Railway Stations in Maharajganj parliamentary constituency, Bihar

श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल (महाराजगंज): महोदय, आपके माध्यम से रेल मंत्री जी का ध्यान मैं अपने संसदीय क्षेत्र के पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल के महाराजगंज एवं चैनवा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे की खाली पड़ी जमीन की ओर दिलाना चाहता हूँ। यह जमीन बिना उपयोग के ऐसे ही खाली पड़ी हुई है। इसलिए उक्त खाली पड़ी जमीन में किसान हित एवं व्यवसायियों के हित में रैक प्वाईंट बनाना बहुत ही अच्छा रहेगा।

हमारा संसदीय क्षेत्र कृषि प्रधान होने के साथ ही व्यावसायिक दृष्टि से भी काफी महत्वहपूर्ण है। हमारे संसदीय क्षेत्र के महाराजगंज, गोरियाकोटी, भगवानपुर, मशरक और एकमा के साथ ही कई अन्य व्यावसायिक केन्द्र हैं जो अलग-अलग वस्तुओं के थोक व्यवसाय के लिए काफी प्रसिद्ध हैं। इन व्यवसायियों और क्षेत्र के किसानों को रैक से अपना माल सिवान या छपरा से मंगवाना पड़ता है जोकि काफी दूर है। इससे इन्हें माल अन्य स्थान से मंगवाने में खर्च अधिक होता है और समय भी लगता है।

अतः उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर आपके माध्यम से भारत सरकार के माननीय रेल मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के महाराजगंज एवं चैनवा में रैक प्वाईंट का निर्माण कराया जाये जिससे कि हमारे क्षेत्र के किसानों और व्यवसायियों को इसका लाभ मिल सके।

(इति)

Re: Need to review the functioning of *Cattle Breeding Farm*, Andeshnagar , L*akhimpur* - Kheri district, Uttar Pradesh

श्री अजय कुमार (खीरी): मेरे लोक सभा क्षेत्र लखीमपुर खीरी के अंदेशनगर में 1976 में कैटर ब्रीडिंग फार्म पशुपालन डेयरी विकास मंत्रालाय द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य नस्ल सुधार के साथ देश में दूध का उत्पादन बढ़ाने व अच्छी नस्ल के सांडो को देश के पूर्व व पूर्वोत्तर में वितरित करने की योजना थी जिसके लिए क्षेत्र की लगभग 300 हैक्टेयर भूमि पर यह फार्म बनाया गया था।

परंतु कालांतर में कई कमियों के कारण यह फार्म अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पा रहा है जिसमें न कवल मंत्रालय के स्तर पर उक्त संस्थान को निरीक्षण उपरांत दिशा निर्देश देने तथा संबन्धित संस्थान की कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति की आवश्यकता है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है की उक्त संस्थान का निरीक्षण करने व बेहतर परिणाम हेतु पूर्ण मूल्याकन करने की कृपा करें।

(इति)

Re: Need to connect Gumla district in Jharkhand with rail services

श्री सुदर्शन भगत (लोहरदगा): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सभी यह जानते हैं कि मेरा संसदीय क्षेत्र लोहरदगा जनजातीय बहुल क्षेत्र है, यहाँ के लोगों की मुख्य आय का श्रोत कृषि कार्य होने के साथ-साथ यहाँ के लोगों का बहुत बड़ी संख्या में नौकरियों के लिए देश के अन्य प्रान्तों में आवागमन रहता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यवसाय और अन्य कारणों से भी यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में लोग अन्य प्रान्तों में जाते-आते रहते हैं जिसके कारण मेरे संसदीय क्षेत्र में रेल सुविधाओं की अत्यंत आवश्यकता है। हम सभी के लिए प्रसन्नता का विषय है कि सरकार द्वारा संचालित सभी लोक कल्याणकारी योजनाओं का यहाँ क्रियान्वयन भली प्रकार से हो रहा है। परन्तु दूसरी ओर बहुत दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के गुमला जिले तक अभी भी रेल सेवाएँ नहीं पहुंच सकी हैं। इस क्षेत्र को रेल सेवाओं से जोड़े जाने पर यहाँ के लोगों के जीवन स्तर में गुणात्मक परिवर्तन आ सकेगा।

महोदय, रेल सेवाओं से जुड़ने के बाद यहाँ की जनता के जीवन स्तर में सुधार होने के साथ-साथ यहाँ के लोगों को देश के विभिन्न भागों से जुड़े होने का अहसास होने के साथ-साथ उन्हें बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ने का मौका भी मिलेगा एवं व्यवसाय और बेहतर रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो सकेंगे। अतः मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से यह मांग करता हूँ कि जनभावना और क्षेत्र की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गुमला जिले को अविलम्ब रेल सेवाओं से जोड़ा जाए।

(इति)

Re: Need to improve internet services in Chhota Udaipur parliamentary constituency, Gujarat

श्रीमती गीताबेन वजेसिंहभाई राठवा (छोटा उदयपुर): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र, छोटा उदयपुर (गुजरात) में BSNL नेटवर्क की बहुत बड़ी समस्या है। नेटवर्क की समस्या होने के कारण लोगों का एक दूसरे से संपर्क करने में काफी परेशानियाँ होती हैं।

साथ ही वर्तमान समय में डिजिटल इंडिया होने के कारण सारे कार्य ऑनलाइन हो रहे हैं। लेकिन नेटवर्क की समस्या के कारण सारे कार्यों में बाधा उत्पन्न होती हैं।

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के छोटा उदयपुर, पंचमहल, तथा नर्मदा जिले के ग्रामीण क्षेत्र में नेटवर्क की सुविधा बिलकुल भी नहीं हैं तथा नर्मदा जिले के कुछ स्थानों पर नेटवर्क हैं परंतु फ्रिक्वेन्सी कम होने के कारण नेटवर्क कार्य नहीं करती हैं।

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र पहाड़ी इलाका होने के कारण अधिक फ्रिक्वेन्सी की आवश्यकता हैं।

महोदया, में आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र छोटा उदयपुर में BSNL नेटवर्क में सुधारकर नेटवर्क की फ्रिक्वेन्सी को बढ़ाया जाए, जिससे लोगों को संपर्क करने में परेशानी न हो और डिजिटल इंडिया का सपना भी साकार हो सकें।

(इति)

Re: Need to include Dausa district in Rajasthan in Aspirational Districts

श्रीमती जसकौर मीना (दौसा): भारत सरकार द्वारा आकांक्षी जिलों का चयन कर पेयजल, स्वास्थ्य एंव पर्यावरण के क्षेत्र में सुविधाजनक करने सम्बन्धी अनेक सुधार के कार्य करने का लक्ष्य रखा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि पिछड़ों को आगे लाकर मुख्य धारा में लाया जावे। जिला मुख्यालय की पेयजल योजना अत्यंत क्षतिग्रस्त हो चुकी है। जगह-जगह गन्दगी फैली हुई है। बीसलपुर परियोजना से जिले की 10 प्रतिशत आबादी को भी पेयजल नहीं मिल पा रहा है।

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए आकांक्षी जिलों का सुधार कार्यक्रम का उद्देश्य इन जिलों का त्वरित और कारगर रूप से सुधार करना है। सरकार अपने नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने और सभी के लिए समावेशी विकास सुनिश्चित करने अर्थात सबका साथ-सबका विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उनकी क्षमता का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम फलतीफूलती अर्थव्यवस्था में पूर्ण रूप से भाग लेने के सम्बन्ध में लोगों की क्षमता को सुधारने पर ध्यान केन्द्रित करता है। स्वास्थ्य एंव पोषण, शिक्षा, कृषि एंव जल संसाधान, वित्तीय समावेशन एंव कौशल विकास तथा बुनियादी अवसंरचना इस कार्यक्रम के विशिष्ट क्षेत्र हैं।

इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय जी आपके माध्यम से में माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूँ की दौसा जिले को भी आकांक्षी जिलों का सुधार कार्यक्रम में शामिल किया जावे।

(इति)

Re: Disinvestment of Bharat Earth Movers Limited

SHRI V.K. SREEKANDAN (PALAKKAD): Bharat Earth Movers Limited is a public sector company which has been manufacturing critical defence equipments for the defence of our country since 1964 and is the only metro rail coach manufacturer in India. The company has been paying dividend to the government uninterrupted. This public sector company has one unit in my parliamentary constituency Palakkad also. The government is considering to sell its 26 per cent stake in BEML through strategic disinvestment. All the employees of BEML are against the disinvestment and they have been protesting against it for the last several months. The governments of Karnataka and Kerala had opposed the said disinvestment move. The disinvestment in BEML will also put a question mark on our national security as this company is the only supplier of critical defence equipments to our defence forces. Therefore, I urge upon the government not to make any disinvestment in Bharat Earth Movers Limited in the national interest.

(ends)

Re: East Kolkata Wetland

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): One of the wetlands which provides most of the ecosystem services as designated in the millennium assessment report about wetlands is the East Kolkata Wetlands or EKW. EKW is the world's largest resource recycling ecosystem which helps to treat around 600 million litres of sewage and wastewater daily. This sewage and wastewater are generated mainly by the city of Kolkata (Mukherjee 2016). Canals and creeks, both natural and man-made, constructed during the colonial times are used to bring sewage to flow through the wetlands.

Development of such a system to treat sewage has been possible because the old city Calcutta (now Kolkata) is located between the river Hooghly, a distributary of the Ganga on its west and numerous Wetlands on its east. These wetlands are the inter-distributary marshes between the Hooghly and the now dead Bidyadhri river (declared dead in 1920), another distributary of the Ganga and the Brahmaputra delta (Chatterjee 1993). These water bodies, being the spill basin of the estuarine river Bidyadhari, are salty in nature and thus earned the name salt lakes. From the 1940s, the distributary is further east of the city. Before this, since the last decade of the 19th century, the locals had embanked these salt lakes and started saline water fishing. But the treated sewage water is sweet in nature since it is domestic sewage and thus the local fishers switched to sweet water fishes from the saline ones. This treated water is also used for paddy and vegetables cultivation. The wetlands, over a period of time, not only treated sewage of the city but also performed various ecosystem services which appealed to the locals who adapted to the wetland.

The beautiful wetland is a victim of human aggression including builders and promoters. This needs to be protected.

I urge upon the concerned ministry to look into the issue.

(ends)

Re: Need to upgrade state roads in Telangana as National Highways

SHRI KOMATI REDDY VENKAT REDDY (BHONGIR): I would like to bring to the notice of Central Government that after formation of Telangana state, the Central Government was kind enough to approve in-principle the up-gradation of about 3155 km. length of state roads as National Highways. Out of 3155 km. of in-principle approved sections, so far 1388 km. have been notified as NHs and 1767 KMs are yet to be notified as National Highways. The roads are :-

(1) Hyderabad (Junction of ORR at Gowbelly-Valigonda -Thorrur-Nellikuduru-Mahabubabad-Yellandu-Kothagudem (Junction of NH30-234 kms.).
(2) Medak-Yellareddy-Rudur-92 kms.
(3) Bodhan-Basar-Bhainsa-76 kms.
(4) Medak-Siddipet-Elkathurthy-133 kms.
(5) Choutupal-Shadnagar-Kandi-186 kms.

It is requested to notify the above five roads as new National Highways in Gazette of India at an early date for initiating the process of land acquisition.

(ends)

Re: Setting up of an IT park at Viluppuram in Tamil Nadu.

SHRI D. RAVIKUMAR (VILUPPURAM): Viluppuram Lok Sabha Constituency has several Engineering colleges and producing thousands of engineering graduates every year. It is also well connected by Road with NH 45 with Chennai and by NH 234 with Mangalore Railways- with fully electrified double BG line and Airways-airport at Pondicherry (40 KMs).

An IT park should be set up at Viluppuram to boost the economic activity and employment opportunity.The neighbouring Kanchipuram district has already become one of the hubs of IT industries.It can be easily expanded to Viluppurarn.

(ends)

Re: PMGSY in Andhra Pradesh

DR. BEESETTI VENKATA SATYAVATHI (ANAKAPALLE): PMGSY is a very good scheme to develop Rural Road connectivity to hospitals schools and markets. Due to heavy rains in monsoon almost 80% of our Rural Roads get badly damaged in our state of Andhra Pradesh. My request to the Rural Development Ministry is to increase the allocation of roads from the present 3285 Km to 8000 Km and also for my Anakapalle Parliamentary Constituency from 121 Km to 659 Km.

(ends)

Re: Financial condition of Life Insurance Corporation

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): I want to raise the matter of LIC. The unrealized loan in LIC upto September, 2019 is Rs. 30000 crore. This loan has been taken by some companies like Deccan Chronicle, Essar Port, Gammon, IL&FS, Bhushan Power, Videocon Industries, Alok Industries, Amtrak Auto, ABG Shipyard, Unitech, GVK Power and GTL. Out of Rs. 30,000 crore, Rs. 25,000 crore were disbursed from insurance business fund, Rs. 2500 crore from premium fund, Rs. 5000 crore from pension fund, and Rs. 500 crore from ULIP fund. This was all the money of the public. We do not know what proceedings have been taken against these defaulting companies. In addition to this, the LIC had to purchase shares from the loss-making IDBI Bank amounting to Rs. 21,024 crore on Finance Ministry's instruction. Each share of IDBI was bought at Rs. 61 and in a short time the share value fell to Rs. 27. This was the beginning of destruction of LIC. Now, the government has decided to sell shares of LIC and IDBI. LIC insures the lives of lakhs of Indians, but there is no insurance for LIC which was nationalized by Pt. Nehru in 1956 with Rs. 5 crore capital. In the current fiscal, the LIC had paid Rs. 2610 crore as dividend to the government. It has mopped up Rs. 1816 crore as new business premium. Now the government is killing this organization.

(ends)

Re: Outstanding dues to be paid to Maharashtra

SHRI ARVIND SAWANT (MUMBAI SOUTH): I would like to draw the attention of Hon'ble Finance Minister towards central government legitimate dues of tax devolution and GST compensation to Maharashtra government. The matter has already been raised by Hon'ble Chief Minister of Maharashtra through his letter to Hon'ble Finance Minister for immediate release of tax dues to state. With present slowdown in economy and state's huge outstanding dues which the centre has to pay, any government would face acute fiscal pressure. Instead of receiving the enhanced amount, the state has received less than the budgeted amount. Such huge deficits have the potential to disrupt the budget and planning processes. With further slowdown of the economy, it is anticipated that there will be further reduction in tax devolution and shortfall in GST collection.

(ends)

Re: Need to provide compensation to maize farmers in Purnia parliamentary constituency, Bihar

श्री संतोष कुमार (पूर्णिया): बिहार राज्य में मेरे संसदीय क्षेत्र पूर्णिया के सीमांचल एंव कोशी क्षेत्र में मक्का, किसानों की मुख्य फसल है और यहाँ के किसान मक्का की खेती पर ही निर्भर हैं। एक अनुमान के अनुसार पूरे देश में बिहार के सीमांचल और कोशी क्षेत्र में मक्का की खेती सबसे अधिक होती है। एक शोध से पता चला है कि एक तितली किस्म का कीड़ा जो अमेरिका में पाया जाता है, उसके प्रकोप से इस क्षेत्र में मक्का की फसलें बुरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। बताया जाता है कि यह कीड़ा केवल मक्का की फसलों को खाता हैं उस पर जहाँ यह बैठता है तो अंडे देता है और उसी अंडे से कीड़ो की संख्या काफी बढ़ जाती है। यह कीड़े मक्के की बाली को खोखला बना देते हैं। यह कीटाणु इतने फैल गए हैं कि किसानों की हजारों एकड़ जमीन में लगी मक्के की खेती नष्ट हो गई है। इससे किसान अपने को असहाय महसूस कर रहा है। उसकी आमदनी का जरिया खत्म हो गया है।

अत: आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि बिहार राज्य के अन्तर्गत सीमांचल एंव कोशी क्षेत्र के मक्का किसानों को, जिनकी मक्का की फसल कीटाणुओं के प्रकोप से नष्ट हुई है, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की कार्यवाई की जाय।

(इति)

Re: Exemption to Defence personnel at Toll Gates

SHRI ANUBHAV MOHANTY (KENDRAPARA): It is a matter of great concern as the matter relates to the personnel of the Defence forces. As per 'The Indian Tolls (Army and Air Force) Act 1901' Section 3 (A) which clearly says that the Defence forces personnel, whether on duty or off duty, when they produce their Defense Identity Card, should be exempted from paying the Toll Tax. But it has come the notice that on some Toll Gates in some of the States even the Defence Personnel are not exempted and that too on the orders of some General Manager. The General Manager who has no authority to amend or change the provisions of law, has suo-motu assumed the authority and has withdrawn the privilege of the soldiers.

The Road Transport Minister may recall his instructions issued to the Toll Gate operators that whenever a Defence Personnel produces his Identity Card at the Toll Gate, they are to be greeted with a smile and should be given a salute or a standing ovation in their honour.

It is earnestly requested that the Hon'ble Minister of Road Transport and Highways may please look into the matter and once again issue orders clearly mentioning the exemption granted to the Defense personnel at all the Toll Gates and also should mention that severe action may be taken against those who violate the instruction. They should be asked to display the instruction clearly and prominently on all the Toll Gate.

(ends)

Re: Need to expand the capacity of Ganga Kisan Sahkari Chini Mills Limited, Morna in Uttar Pradesh and also ensure its proper maintenance

श्री मलूक नागर (बिजनौर): महोदय, पूरे देश में व पूरे उ0प्र0 में कई सरकारी चीनी मिलों की क्षमता नहीं बढाई गयी है व मेंटीनेंस भी नहीं की गयी है। ऐसी ही एक चीनी मिल - दि गंगा किसान सहकारी चीनी मिल, मोरना बीते 28 जनवरी, 2020 की रात्रि में पावर टर्बाइन का मेन गियर बॉक्स टूटने से बंद हो गयी है। इससे क्षेत्र के सेंकडो गांवो के किसानो के सामने गन्ना आपूर्ति का संकट छा गया है। इन सभी गांवो के गन्ने के आपूर्ति तुरंत दूसरे चीनी मिलो को कराई जाये। किसानो के मामलों में हमेशा से ही सरकारो का ढुलमुल रवैया रहा है। सरकारी शुगर मिलो का उचित ढंग से रखरखाव और मेंटीनेंस नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण आए दिन इस तरह की समस्याओ का सामना करना पड़ता है। कई बार मांग उठाने के बावजूद उस मिल की क्षमता क्यों नहीं बढाई गयी। ऐसा सुनने में आया है कि सरकारी लोग प्राइवेट मिल मालिको से मिले हुए है। वे नहीं चाहते कि इस सरकारी मिल की क्षमता बढ़े और यह सही तरीके से चले क्योंकि इससे प्राइवेट मिल मालिको को नुकसान होगा।

महोदय, आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि किसानो का गन्ना खरीद का बकाया भुगतान तुरंत कराया जाये व उपरोक्त चीनी मिल की तुरंत क्षमता बढाई जाये व इसका रखरखाव अच्छे स्तर पर कराया जाये व इसमें घोटाले की जांच कराकर दोषियो को तुरंत सजा दिलाई जाये।

(इति)

Re: Need to set up the National Police University within the precincts of Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad

DR. G. RANJITH REDDY (CHEVELLA): People of the country are unable to control their senses due to various factors, be it relating to decisions of the Government of the day or be it due to sudden spurt in tempers between groups or individuals and, at times, such tempers spread across the length and breadth of the country. In such a situation, it will be a challenging task for Police to bring the situation under control.

As per the Constitution, Law and Order is a State Subject. But, at the same time, Government of India also supplement the efforts of the States, through various interventions, be it Modernisation of Police Force or through other schemes/programmes to train and provide other facilities to police.

Sardar Vallabhbhai National Police Academy is one such institution which is playing a pivotal role in imparting training to Police to lead with courage, uprightness, dedication and a strong sense of service to the people. But, this institute is catering only to the needs of IPS officers. But, there is no institution or university in the country run by Government to impart education in policing and internal security through UG and PG academic programmes in specialized subjects like policing, science, cyber forensic, risk management, forensic science, correctional administrative aspects, criminology, etc.

Now,. Ministry of Home Affairs is proposing to set up National Police University to focus on the above issues. I strongly feel, since SVPNPA is imparting necessary training, management skills, etc., to IPS officers, it is most appropriate to set up the proposed National Police University within the precincts of SVP National Police Academy which will be a befitting tribute to this great freedom fighter and also is the most suitable place since it has huge tracks of land to set up National Police University.

Hence, I once again request Ministry of Home Affairs to set up National Police University at SVPNPA, Hyderabad, and give it the name as SVP National Police University.

(ends)

Re: 'Merit-cum-Means' Scholarship

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): The Scheme "Merit-cum-Means' Scholarship is being implemented by the Government of India for students from minority communities pursuing professional and technical courses. The Central Government has set a quota of 5797 students from the state of Maharashtra who may avail the scholarship. As it stands, the unutilized quota for Buddhist students (from Maharashtra) is being diverted for Buddhist students from other states. Considering the increasing number of applications for this scholarship, I urge the Central Government to increase the quota for the minority students from the state of Maharashtra. I further urge the Central Government to consider a policy where the unutilized Buddhist quota from the state of Maharashtra may be utilized for students from other minority communities, who also come from Maharashtra. This has been a repeated request of the Maharashtra state government since December 2016, and I would request the Central Government to grant this request.

(ends)

Re: Need to provide legal assistance to an Indian national arrested by Egyptian Coast Guard

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): One innocent resident of Srikakulam has been sentenced to death by an Egyptian court. He was working as a seaman for a marine company which fraudulently made him board a drug trafficking ship from Iran and alongwith the crew he was arrested by Egyptian Coast Guard on 18 December 2016.

It was only after two years that his family got the information of his arrest. He was hired for the seaman job through 'SKD Marine Company based in Vizag. The company also allegedly took Rs. 4 lakh from him and is now refusing to provide any assistance to his family.

Sir, I request the Government to provide legal assistance to him at the earliest and also help his family to communicate with him once. His mother hasn't seen him for the last 4 years. It is my earnest request to facilitate his mother talk to him through video-conferencing.

(ends)

प्रमोशन में रिज़र्वेशन विषय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में - जारी

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो आदेश आया है, इस पर हमारी पार्टी और हमारी पार्टी मुखिया का व्यू पहले से था कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने यह करके दिखाया था और प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था करवाई गई थी।...(व्यवधान) यह व्यवस्था आर्टिकल 16 के तहत पूरी तरह से व्यवस्थित है और उसके तहत यह संविधान में अधिकार दे रखा है कि कोई भी राज्य सरकार प्रमोशन में भी आरक्षण दे सकती है।...(व्यवधान) इस तरह की टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालय से आना और उसके पक्ष में उस प्रदेश की सरकार को इन लोगों के विरोध में कोर्ट में जाना यह साबित करता है कि ये पूरी तरह से एससीएसटी और दलित विरोधी सरकार है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री मलूक नागर को श्री रितेश पाण्डेय द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्जापुर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी पार्टी अपना दल की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस ताजा फैसले के खिलाफ अपनी आपत्ति, अपनी असहमति दर्ज करती हूं जिसके माध्यम से उन्होंने कहा है कि राज्यों को सरकारी नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था लागू करने को वे बाध्य नहीं हैं और प्रमोशन में आरक्षण का दावा करने का उनको अधिकार नहीं है। (1250/RAJ/KSP)

अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहती हूं कि एससी, एसटी और ओबीसी के संविधान प्रदत्त आरक्षण के खिलाफ दिया गया, यह कोर्ट का आज तक सबसे दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है और वंचित वर्गों के अधिकारों पर इससे भयानक कुठाराघात और कुछ भी नहीं हो सकता है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, कोर्ट के माध्यम से एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण के खिलाफ बार-बार इस प्रकार के जो फैसले आते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारी न्यायपालिका के अंदर एससी, एसटी और ओबीसी का प्रतिनिधित्व नहीं है।...(व्यवधान) इसलिए मैं अपनी पार्टी, अपना दल की ओर से बार-बार यह मांग करती हूं कि न्यायपालिका के अंदर एससी, एसटी और ओबीसी का जो प्रतिनिधित्व है, उसको सुनिश्चित किया जाए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, संसद के पास यह अधिकार है कि कानून बना कर ऐसे मामलों का निपटारा करे। इससे पहले भी एक परिस्थिति आई थी, जब एससी/एसटी एट्रोसिटीज एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बदलाव किया गया था, तब हमारी सरकार ने अध्यादेश लाकर और एक नया कानून बना कर वंचित वर्गों के अधिकार को संरक्षित करने का काम किया था।...(व्यवधान) आज फिर वैसी ही भयावह स्थिति खड़ी हुई है।...(व्यवधान) इसलिए मैं अपनी पार्टी की ओर से सरकार से मांग करना चाहती हूं कि इस मामले में त्वरित हस्तक्षेप करे और इस मामले का निपटारा करे, क्योंकि आज देश का वंचित वर्ग हाशिए पर खड़ा है और अपनी चुनी हुई सरकार से यह उम्मीद करता है कि

इस तरीके के फैसले जो बार-बार कोर्ट के द्वारा दिए जाते हैं, सरकार को इसमें सामने आ कर वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए।…(व्यवधान) धन्यवाद।

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Mr. Speaker, Sir, if the verdict given by the Supreme Court on last Friday is implemented, the very principle of social justice will be jeopardized. …(*Interruptions*) Now, the Government is asking as to what they have to do in this matter. The Government should not be a silent spectator because the basic principle of social justice should be adhered to. …(*Interruptions*) We all know that work and employment participation of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Minorities and the Other Backward Classes is very low in this country. …(*Interruptions*) In these circumstances, I humbly appeal to the Government to file a review petition in the Supreme Court against this verdict. …(*Interruptions*)

ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA): Mr. Speaker, Sir, the Government should file a review petition against this verdict. …(*Interruptions*) On behalf of our party, the Communist Party of India (Marxist), I demand that the Government should file a review petition and make a legislation in this regard, if necessary. …(*Interruptions*)

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Hon. Speaker, Sir, I request the Government to immediately address this issue because it is creating confusion. …(*Interruptions*) I appreciate the Treasury Benches saying that they are doing something. But we need action; we do not need just words. …(*Interruptions*) So, I take this opportunity to request the Government to immediately intervene in this matter instead of just keep talking about it. …(*Interruptions*) We would appreciate if the Government could intervene in this matter urgently. …(*Interruptions*)

रक्षा मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): अध्यक्ष महोदय, मैंने सदन की कार्यवाही प्रारंभ होते ही, आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों से अनुरोध किया था कि इस संबंध में हमारे सामाजिक न्याय मंत्री जी स्टेटमेंट देने वाले हैं। मैंने सभी से विनम्रतापूर्वक यह अनुरोध किया था कि उनके स्टेटमेंट की प्रतीक्षा की जाए। यदि आप उनके स्टेटमेंट से संतुष्ट नहीं हैं और आज बहस चाहते हैं, तो इस संबंध में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से इस सदन में बहस भी हो सकती है।…(व्यवधान) क्षमा कीजिएगा, वर्ष 2012 में उत्तराखंड में आपकी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट नहीं थी।…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि इतने संवेदनशील मुद्दे को जिस तरह से कांग्रेस के लोगों द्वारा, मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, यह बहुत ही गंभीर मामला है।...(व्यवधान) सभी को प्रतीक्षा करनी चाहिए। ...(व्यवधान) सामाजिक न्याय मंत्री स्टेटमेंट देने वाले हैं, उसके बाद आपको जो बहस करनी है, आप वह कीजिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही भोजनावकाश के लिए दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1254 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न-भोजन के लिए चौदह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1400/VB/KKD)

1403 बजे

मध्याह्न-भोजन के पश्चात् लोक सभा चौदह बजकर तीन मिनट पर पुनः समवेत् हुई।

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, जिस विषय पर चर्चा हुई थी, उस विषय पर माननीय मंत्री जी राज्य सभा में वक्तव्य दे रहे हैं। राज्य सभा से आने के बाद वे यहाँ वक्तव्य देंगे।

…(व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): No, Sir. Till then, you adjourn the House …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: सुरेश जी, बैठिए। आप यह फैसला कैसे करने लगे कि हाउस एडज़र्न कर दिया जाए। No. यह गलत है। आज के बाद ऐसा वक्तव्य सदन में न दें।

…(व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Whatever assurance has been given by the hon. Minister should be fulfilled …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: आप सचेतक हैं। आप कैसे नीचे से आसन की व्यवस्था देने लगे?

…(व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): The Government should fulfil their assurance …(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No.

…(व्यवधान)

सामान्य बजट - सामान्य चर्चा – जारी

1404 बजे

श्री रामप्रीत मंडल (झंझारपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे वर्ष 2020-21 के बजट पर बोलने की अनुमति दी, इसके लिए आपका धन्यवाद।

मैं इस बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सरकार द्वारा काफी अच्छा और संतुलित बजट पेश किया गया है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को, जो देश के विकास के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं और माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। (1405/PC/RP)

उन्होंने मेरे संसदीय क्षेत्र झंझारपुर का पूरा ख्याल रखा है।

मैं पहले भी कई बार सदन में प्रश्न कर चुका हूं और अब बजट में सकरी-लौकहा बाजार-निर्मली व सहरसा-फारविसगंज आमान परिवर्तन के लिए 150 करोड़ रुपये की घोषणा की है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ-साथ जयनगर-बारदीबास-बीजलपुरा (नेपाल) में 100 करोड़ आवंटित किए गए हैं। मैं इसके लिए भी माननीय वित्त मंत्री महोदया को धन्यवाद देता हूं। सुरसंड से सीतामढ़ी होते हुए निर्मली की ओर जाने वाली रेल लाइन की मंजूरी वर्ष 2008 में हो गई थी, लेकिन अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। मैं माननीय मंत्री जी से उसके ऊपर ध्यान देने का आग्रह करना चाहता हूं।

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र झंझारपुर के शहरी क्षेत्र नगर पंचायत की राम चौक पर रेलवे लाइन का आमान परिवर्तन कार्य चल रहा है। वहां अधिक ट्रैफिक रहता है, जिसके कारण हमेशा जाम लगा रहता है। अत: मैं वहां पर आरओबी निर्माण की मांग करता हूं। इसी प्रकार जयनगर में गुमटी बंद रहती है। अधिक ट्रैफिक जाम होने के कारण वहां भी मैं आरओबी निर्माण की मांग करता हूं।

महोदय, इस वर्ष सरकार ने बिहार की रेलवे परियोजनाओं पर पूरी तरह ध्यान दिया है। जैसे हाजीपुर-सुगौली लाइन-148 किलोमीटर (100 करोड़ रुपये), नेउरा-दनियांवा-बिहार शरीफ-बरबीघा-शेखपुरा – 83 किलोमीटर (90 करोड़ रुपये)। इसी लाइन पर दनियांवा तक कार्य हो चुका है और आगे कार्य रुका हुआ है। …(व्यवधान) इसे जल्द पूरा करने की आवश्यकता है। छपरा-मुजफ्फरपुर-85 किलोमीटर (35 करोड़ रुपये), बिहटा-औरंगाबाद-118 किलोमीटर (20 करोड़ रुपये)। यह लाइन भी वर्ष 2008 में स्वीकृत हुई थी, किंतु अभी तक लंबित है। अररिया-सुपौल और मोतीहारी-सीतामढ़ी लाइन पर भी जल्द कार्य चालू करने की आवश्यकता है।

1406 hours (Dr. Kirit P. Solanki *in the Chair*)

महोदय, दोहरीकरण परियोजना पर भी सरकार ने ध्यान दिया है। मैं इसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी को ध्न्यवाद देता हूं। सरकार ने बिहार के न्यू-मुजफ्फरपुर टर्मिनल स्टेशन, भभुआ रोड एवं बरौनी स्टेशन के विकास के लिए भी राशि आवंटित की है। मैं आग्रह करता हूं कार्य जल्द पूरा किया जाए।

महोदय, डालमिया नगर में माल डिब्बा के कारखाने के लिए 38 करोड़ रुपये, गया में न्यू मेमू कार शेड की स्थापना के लिए 27 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

महोदय, इस बजट में बिहार के रेल यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ नई गाड़ियों की घोषणा नहीं की गई है। इससे राज्य की जनता में असंतोष है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि बिहार में दिल्ली से दरभंगा और दिल्ली से पटना के लिए एसी एक्सप्रेस गाड़ी चलाने की व्यवस्था करें।

महोदय, मेरी सरकार से मांग है कि बिहार की राजधानी पटना जंक्शन, दरभंगा जंक्शन, समस्तीपुर जंक्शन, मुजफ्फरपुर जंक्शन, हाजीपुर जंक्शन, बरौनी जंक्शन, कटिहार जंक्शन, गया जंक्शन एवं बिहार शरीफ जंक्शन को विश्व स्तरीय मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित किया जाए। मधेपुरा रेल कारखाना, समस्तीपुर रेल डिब्बा मरम्मती कारखाना, छपरा पहिया कारखाना आदि पूर्णरूपेण कार्य नहीं कर रहा है। उसका विस्तार हो और पूरी क्षमता का उपयोग होना चाहिए।

महोदय, मैं इन्हीं बातों के साथ वर्ष 2020-21 के इस आम बजट का समर्थन करता हूं।

धन्यवाद।

(इति)

1409 hours

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Hon. Chairman, Sir, I stand here today to deliberate on the General Budget 2020-21 which is the first Budget of the third decade of 21st Century. Keeping that in view, the Finance Minister presented this Budget amid high expectations of a demand stimulus for the economy.

(1410/RCP/SPS)

The slowdown in the economy, combined with the existing fiscal stress, made this a challenging task. Economists have said realistically that there was little scope for a big fiscal stimulus. She has tried to do her best under the given circumstances. One may ask why she did not try to do more on policy and legislative changes that are not necessarily tax, revenue, and expenditure-related. But these can be done later, as they are not part of the Money Bill.

Before I delve into the nuances of this year's Budget, I would like to know from the Government whether any consensus has emerged on defining poverty line in the country. The Governing Council of NITI Aayog had held a meeting on 8th February, 2015 under the Chairmanship of hon. Prime Minister. A Task Force under the Chairmanship of Dr. Arvind Panagariya submitted a report to the Prime Minister on 11th July, 2016. The Terms of Reference for the Task Force included to "Develop a working definition of poverty".

Regarding estimation of poverty, the report states: "a consensus in favour of either the Tendulkar or a higher poverty line did not emerge." It recommended to form an expert committee – one can understand a Committee recommending to form another expert committee – to arrive at an informed decision on the level at which the poverty line should be set. We are told on 5th February this year that it is still under consideration in reply to a Question which was put up before this House to the Government. But it has not been decided yet since 2016.

The Economic Survey 2019-20 has very candidly and even arguably pushed forward pro-market reforms. It has delved into India's own past. It has argued that India's civilisational ethos has celebrated wealth creators. That is why, it had allowed the country to be the dominant economic power globally for more than three-fourths of known economic history. Our four-decade long dalliance with socialism, the Survey states, was an aberration from this norm. I may agree; I may not agree. Many may agree; many may not agree. But what

The Economic Survey has stated this year very candidly is that the four-decade long dalliance with socialism was an aberration from this norm.

This is a nation which worships Goddess Lakshmi. The earning is not supposed to be appropriated fully but to be divided in four. One quarter to be kept as savings; one quarter to be spent on alimony; one quarter to be spent for the society; and the last quarter for his own expenses. Many of us today even practise this in our daily life. That is the reason why India's resilience was on the savings.

Coming to the Budget, one may say there is focus on agriculture, on infrastructure, a boost to the corporate sector, tax cuts, and disinvestment which are positive steps. Slowing economy, falling aggregate demand, and poor credit flows and exports were all pointing to the need for a sharp fiscal stimulus. But fiscal space was limited. Yet, several measures and initiatives have been taken to address these challenges and build them around the themes of, as it has been said in the Budget, aspirational India, economic development, and caring society. Review of Rules of Origin norms under the FTAs and provisions against dumping are welcome steps.

(1415/SMN/MM)

This Budget indicates that the Government is alive to a new set of environmental challenges confronting us.

Sir, what is the state of economy today? That is read through key economic indicators – GDP, inflation, industrial production, balance of payments, and fiscal deficit. People say there is a slowdown. Some say it is structural and to correct it, we need structural reforms. Some others say it is cyclical for which one needs policy intervention. Since 2011-12, investment has been declining. And here, I would like to mention this because there was a question during the Question Hour and the hon. Minister of State for Finance has given a written reply and also was replying but I would like to keep it on record here. Outcome in this country has not been lowered and has not come down since 1991. No doubt, we are measuring GDP growth but outcome has not come down as it had in the sixties and in the seventies. Three times, there was a serious slump in outcome. I would say in 1966, in 1973, and again in 1979 but after 1991, the outcome has never come down in this country and that is the

reason for the resilience of this country to withstand different international slowdowns or depressions that are occurring in other parts of the world.

Here I would like to mention that the problem today in our country is that it is not the outcome or the GDP, but it is the investment which is coming down at a rapid pace.

We have always made our comparison with the East Asian Tigers. How have they improved themselves? How have they built-up their economy? Their investment was on manufacturing and was on production. Our growth has to depend on investment and that is the reason why there is always a comparison between us and China, between us and Indo-Sino countries. So, the more investment is there in our country, the growth would be faster and quicker. As investment has slowed down, I would like to mention from where the investment has to come.

In India, the investment was being done by respective public sector banks and respective public sector banks are unable to disinvest in a greater way after 2011 because majority of the investment went towards infrastructure.

These are all on record. From 2000, the investment which was for MSME and for the small traders that was in a bigger way, had come down and is still sliding down. I would expect that in this Budget, adequate corrective measures are necessary so that the resilience is brought in through the banking so that they can invest more in the MSME sector and on the small traders so that they can actually bring the output growth and the output growth will also occur. Since 2011-12, investment has been declining in India. Investment has been the main driver of growth whereas in East Asia, it is the exports which is the engine of growth. Till 2008-09, investments were more by the public sector banks. Bond market did not do the investment in India. Small business thrives on the bank finance but if it is not….. …(*Interruptions*)

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): The Speech is for the Government. …(*Interruptions*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): I think Madam Member from Maharashtra should have the patience to listen to me till the last.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): I am happy if you speak for three hours.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): But it is not happening after 2000. In the last part of the first decade of this century, banks were investing in infrastructure projects. Today, banks are no longer in a position to lend in infrastructure and they are not providing credit to small business also.
(1420/MMN/SJN)

This has led to the problem. Has this Budget addressed this issue? I believe there is a need for financial sector reforms. There is a huge amount of NPAs. Wilful defaulters are to be tackled sternly. Unless the MSMEs are revived, it will be tough to reverse the current economic slowdown and ensure growth in employment. There is a need to focus on banking sector to tackle the slowdown. Unless the banking sector is brought back to health, one cannot expect a reversal of the economic slowdown this year. The big borrowers are still able to borrow but the MSMEs are being squeezed of loans for not being viable in the eyes of bankers.

An interesting piece is there in *The Economic Survey.* In a strong critique of the performance of public sector banks, *The Economic Survey* says "while Rs.4.3 lakh crore of taxpayers' money has gone into the public sector banks, every rupee invested has lost 23 paise as on 2019." Yet I would say the Government should not lose sight of wider reforms in the public sector banks. Bankers today have been reluctant to take lending decisions. In the absence of reforms, the public sector banks will remain vulnerable to frauds and fear of investigation despite safeguards put in place by the Government. There is a need for wide reforms to build capacity in evaluating risk associated with lending. There is a need to get competition within the banking sector. Is there any competition today? None.

An attempt was made to bring in FRDI Bill during the last Lok Sabha. I think I read it yesterday in the newspaper where the Finance Minister has said that they are considering of bringing in the FRDI Bill. I would say there is a talk of it now. No doubt, there was some concern but do not throw the baby with the bathwater.

The Budget Estimates of the next fiscal year, to a large extent, depend on achieving the ambitious disinvestment target. You intend to raise a massive 2.1 trillion next year compared with the revised estimate of Rs.65,000 crore this year. The Government had budgeted 1.05 trillion in July, 2019. However,

Rs.18,000 crore only has been managed to be raised. The Government is planning to raise Rs.90,000 crore by selling its stake in the financial institutions like the Life Insurance Corporation. People say there are reasons why this proposal is a good one. Apart from invoking value, it will not only allow investors, both retail and institutional, to own the largest insurance venture but also it will improve transparency.

माननीय सभापति (डॉ. किरीट पी. सोलंकी) : महताब जी, आपके बाद दो और सदस्यों को भी बोलना है।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : महोदय, हमारी पार्टी से बोलना है?...(व्यवधान) Should I stop?

HON. CHAIRPERSON: Mahtab Ji, you please conclude.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): I conclude my speech.

(ends)

1423 बजे (माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

…(व्यवधान)

प्रमोशन में रिज़र्वेशन विषय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में वक्तव्य

1423 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दिनांक 7 फरवरी, 2020 को सिविल अपील संख्या 1226/2020 मुकेश कुमार एवं अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य में प्रमोशन में रिज़र्वेशन विषय पर फैसला आया है। यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार इस पर उच्च स्तरीय विचार कर रही है। मैं यहां यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस मामले में न तो भारत सरकार को कभी पक्षकार बनाया गया है और न ही भारत सरकार से शपथ पत्र मांगा गया है। उक्त मामला एसएलपी उत्तराखंड सरकार के द्वारा दिनांक 5.09.2012 में लिए गए निर्णय के कारण उत्पन्न हुआ है, जिससे उत्तराखंड में प्रमोशन में रिज़र्वेशन लागू नहीं करने का निर्णय लिया गया था। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि वर्ष 2012 में उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी।...(व्यवधान) हमारी सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए समर्पित और प्रतिबद्ध है।...(व्यवधान) इस विषय पर उच्च स्तरीय विचार के बाद भारत सरकार समुचित कदम उठाएगी।...(व्यवधान)

(1425/GG/VR)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठ जाइए।

आज केन्द्रीय बजट पर सामान्य चर्चा है।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, हमारी बात रखने दी जाए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: स्टेटमेंट के बाद बात नहीं होती है। कानून बताओ, स्टेटमेंट के बाद बात थोड़े होती है।

...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): अध्यक्ष जी, कृपया जनरल बजट के ऊपर चर्चा कंटीन्यू करायी जाए। ...(व्यवधान) माननीय सोशल वैलवेयर मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है। उसमें साफ हो गया है, दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आज केन्द्रीय बजट पर सामान्य चर्चा लंबी चर्चा चलेगी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: न आपकी बात नोट हो रही है और न इनकी नोट हो रही है, बाकी बोलते रहना।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: केन्द्रीय बजट पर सामान्य चर्चा लंबी होगी। लंबी चर्चा होगी तो मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूँ कि वे सामान्य बजट की चर्चा पर अधिकतम उपस्थित रहें।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जो अपने भाषण सभा पटल पर रखना चाहते हैं, वे ऐसा कर सकते हैं। भाषण बिंदुवार न हो कर धाराप्रवाह रूप में होना चाहिए। भाषण में कोई एनेक्श्चर शामिल नहीं करें। मेरा सभी माननीय सदस्यों से यह आग्रह है।

श्री गिरीश चन्द्र जी। …(व्यवधान)

1427 hours

(At this stage, Shri Adhir Ranjan Chowdhury, A. Raja and some other hon. Members left the House.)

सामान्य बजट - सामान्य चर्चा – जारी

1427 बजे

श्री गिरीश चन्द्र (नगीना): माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बजट पर अपने विचारों को रखने का मौका दिया है। मैं आपको दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, प्रस्तावित बजट में आम आदमी की कमर तोड़ दी गई है। रसोई घर का बजट दोगुना कर दिया गया है। इस बजट से रोज़मर्रा के लिए इस्तेमाल होने वाली सभी वस्तुएं …(व्यवधान) सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके विपरीत मंहगाई को नियंत्रित करने का कोई प्रयास बजट में नहीं किया गया है। रोज़गार का कोई अवसर उत्पन्न करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। इन परिस्थितियों में बेराजगार और युवाओं को समुचित अवसर प्राप्त होने के आसार नहीं के बराबर हैं। अर्थव्यवस्था और बेराजगारी के आंकड़े आर्थिक मंदी बढाने के संकेत दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त महिलाओं, दलितों, पिछड़ों के कल्याण की किसी भी योजना का बजट में जिक्र नहीं किया गया है। टैक्स स्लैब के नाम पर धोखा दे कर इसमें भी अधिक लाभ पूंजीपतियों का होने वाला है। हाऊस लोन में दी जाने वाली छूट को भी समाप्त कर नौकरीपेशा एवं मध्यम वर्ग के साथ धोखा किया है। किसानों की आय और खेती के संसाधनों में कोई इजाफा नहीं किया गया है। बजट में किसानों के साथ भी छल किया गया है। बजट के पहले ही दिन शेयर बाजार सदमे में है और निवेशकों के लाखों रूपये डूब गए हैं। इसके अतिरिक्त उपरोक्त बजट से राजकोषीय घाटा बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है।

माननीय अध्यक्ष जी, वर्तमान में देश आर्थिक सुस्ती और बेरोजगारी जैसी दो बड़ी समस्याओं का सामना कर रहा है। विकास दर पिछले करीब छह साल में सबसे न्यूनतम स्तर पर है। इसी प्रकार बेरोजगारी की दर पिछले करीब 40 वर्षों में सबसे अधिक है। देश की अर्थव्यवस्था को इन दोनों समस्याओं से निजात दिलाने के लिए सरकार क्या करेगी, इस बजट में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। बजट में आर्थिक संकट को दूर करने के उपाय नहीं हैं। किसानों की आय दुगुना करने का वित्त मंत्री का दावा खोखला है और तथ्यात्मक वास्तविकता से परे है। कृषि विकास दर वर्तमान में लगभग दो प्रतिशत हो गई है, जबकि आय दुगुनी करने के लिए कृषि विकास दर को 11 प्रतिशत रहना चाहिए जो किसी प्रकार भी इस बजट में संभव होता नहीं दिख रहा है।

(1430/KN/SAN)

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस देश में रहने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति के विकास हेतु दिए जाने वाले धन के बारे में भी आकृष्ट करना चाहूँगा। बजट में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए दिया गया धन बहुत ही कम है। यदि देश की आबादी की अनुपात में तुलना किया जाए, तो यह धन 'ऊँट के मुँह में जीरे' के समान है। मैं सरकार से चाहूँगा कि अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के विकास के लिए धन की बढ़ोतरी आने वाले समय में करें, जिससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों का सर्वांगीण विकास हो सके।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, दिल्ली पर चर्चा बहुत हो चकी है।

श्री गिरीश चन्द्र (नगीना): माननीय अध्यक्ष जी, बजट में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के तहत प्रत्येक केन्द्रीय बजट सेंट्रल सेक्टर और केन्द्र सरकार से अनुदानित स्कीमों की तरफ आवंटित धन का 16.6 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होना चाहिए। इसी तरह ट्राइबल सब प्लान के तहत 8.6 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। यह आरक्षित धन भारत के दो सबसे बड़े समुदायों अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उत्थान व विकास के लिए, क्षेत्रों के लिए सुनिश्चित करना है। यह सच है कि माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट वर्ष 2020-21 में दलितों के लिए 83.256 करोड़ का आवंटन और आदिवासियों के लिए 56.652 करोड़ रुपये की घोषणा की है।...(व्यवधान)

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव कुमार बालियान): पॉइंट हटा दो।

श्री गिरीश चन्द्र (नगीना): जो बजट का कुल 8.5 प्रतिशत दलितों के लिए और स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के तहत आने वाले प्रतिशत का कुल 5.6 प्रतिशत है। इन परिस्थितियों में इन दोनों के उपेक्षित समुदाय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का विकास इस बजट के माध्यम से हो पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसी कड़ी में बताना चाहूँगा कि द नेशनल कैम्पेन ऑन दलित ह्यूमन राइट्स ने गणना की है कि दलितों के विकास के लिए 83.256 करोड़ रुपये के बजाय कम से कम डेढ़ लाख करोड़ होना चाहिए और आदिवासियों के जनहित के लिए 53.652 करोड़ के बजाय कम से कम एक लाख करोड़ आवंटित होना चाहिए। सामाजिक उत्थान और विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि सभी बच्चों को समान शिक्षा के अवसर मिलें। कॉलेज और विश्वविद्यालयों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए छात्रवृत्ति में बहुत गिरावट देखी गई है। एससी छात्रों के लिए 39 करोड़ से गिर कर इस साल 15 करोड़ पहुँच गया है और आदिवासियों के लिए 19.5 करोड़ से गिर कर 8 करोड़ पहुँच गया है। यह बहुत सोचने और विचार करने का गम्भीर विषय है। इसके साथ राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की गुणवत्ता में सुधार के लिए जिम्मेदार मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एकमात्र केन्द्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के आवंटित धन में भारी गिरावट देखी जा रही है।

माननीय अध्यक्ष जी, इस बजट में रेलवे स्टेशन पुनर्विकास की चार परियोजनाओं और 150 यात्री गाड़ियों का संचालन सरकार की निजी भागीदारी नीति से करने की बात कही गई है। इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में भी विदेशी पूंजी निवेशकों को आमंत्रित करने तथा एलआईसी में भी सरकारी हिस्सा बेचने का प्रस्ताव है।

1433 बजे (डॉ. किरीट पी. सोलंकी पीठासीन हुए)

बजट में यह स्पष्ट है कि सरकार अन्य क्षेत्रों के साथ रेलवे व शिक्षा को भी निजी हाथों में सौंपना चाहती है। अपने नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य व सुरक्षा देना सरकार का संवैधानिक दायित्व है, परन्तु सरकार शिक्षा में विदेशी पूंजी निवेश को आमंत्रित करके शिक्षा को भी पूंजीपतियों व व्यापारियों के हाथों बेचना चाहती है। आज जो निजी स्कूल हैं, उनमें केवल धनाढ्यों के बच्चे ही शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। गरीब व दलितों के बच्चों की पहुँच से निजी स्कूल व कॉलेजों की शिक्षा कोसों दूर हैं। यदि

शिक्षा पूंजीपतियों के हाथों में सौंप दी जाएगी तो गरीबों व दलितों के बच्चों को शिक्षा मिल पाना सम्भव नहीं है।

माननीय सभापति जी, बजट में विदेशों के लिए शिक्षक, नर्स व डॉक्टर तैयार करने की बात कही गई है, जबकि उत्तर प्रदेश में डॉक्टर व नर्सों की भारी कमी है। देश के स्कूल व कॉलेजों में लाखों शिक्षकों की कमी है। मात्र उत्तर प्रदेश में ही बेसिक व माध्यमिक शिक्षा में लगभग 2 लाख से अधिक शिक्षकों की कमी है।

माननीय सभापति (डॉ. किरीट पी. सोलंकी): समाप्त कीजिए।

श्री गिरीश चन्द्र (नगीना): इस कमी को दूर करने के लिए बजट में कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि शिक्षकों की कमी का इन सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब व दलित बच्चों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए यह बजट किसान विरोधी, युवा विरोधी, दलित विरोधी, गरीब विरोधी है।

सब का बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

(1435/RBN/CS)

1435 hours

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): I stand here to speak against a very long and tiresome Budget which we all heard. I do not know on what note this Government has brought this Budget? It was a tiresome exercise hearing the speech. This debate has been one of the longest debates which has seen maximum breaks. We have been preparing for the last four days and finally we have got an opportunity to speak on the Budget.

I would like to quote *The Economic Survey*. I think the vision of the Finance Ministry seems to be a bit confused because *The Economic Survey* says one thing and the Outcome Budget says something else. *The Economic Survey* quoted Kautilya, who says: “The root of wealth is economic activity and lack of it brings material distress. In the absence of fruitful economic activity both current prosperity and future growth are in danger of destruction.”

This is one side of the vision of the Economic Survey. The entire Budget seems to be, I think, a document which seems like a vision of a party or a Government. It is very interesting because normally what I understand is that the Budget is only for one year. Most of their commitments are for five years and ten years. When the Member from the Treasury Bench spoke, it was very interesting because they are living in a bubble, absolutely away from reality, in a fairy tale world. It is because most of the targets that they are committed to are or what came from Treasury Benches were numbers which are absolutely unrealistic and unreal given the fiscal health of the situation.

Actually the Budget has exposed the failings of this Government when it comes to fiscal health. The fact is that the Government seems to have run out of revenues completely when it really needed it the most. Talking about five trillion dollar economy, I would like to say that the Treasury Bench is actually talking about ten trillion dollar economy. Especially coming from them, I just wanted to ask them one humble question. To achieve five trillion dollar economy, what is the growth rate that is required? And you are talking of ten trillion dollar economy. We are not even crossing five trillion dollar with all the numbers that you are giving. It is absolutely worrisome for the commitments that they are giving.

They are very proud of Insolvency Code. It is a very good thing if the Government is going to reduce NPAs and that the people are going to pay back. It is a wonderful thing. I am really very happy to hear that. We all supported it. If it is going to be a fair and equal market play, we support any such reforms which are in the interest of the economy and development of the country.

I would like to ask the hon. Minister who is present here one humble question. You are very proud of your Insolvency Code. There is a Company called Alok Industries, which has taken a loan of Rs. 49,000 crore. They paid back Rs. 4,900 crore. So, the balance is 90 per cent. You can verify this. I am giving you all these information from the newspapers.

They want to ply bullet train. The bullet train is in my State. You want to ply bullet train. It is wonderful. But are you going to pay entirely for this? As regards the land acquisition, when they were in power for five years, nothing has happened. But for DombivIli-Kalyan-Thane section, which the maximum number of people use, you have really done nothing for it. You are again in that fairy tale mode. It is like Cinderella. These things happen only in fairy tales; they do not happen in reality. So, bullet train is like that. They keep committing about it, but they have not acquired even one acre of land for it. There is a huge requirement. There are seven people who die every day on Mumbai suburban railway. Imagine, seven people die every day. But there is not even a mention of that, but there is a mention about bullet train as they are in fairy tale mode.

The hon. Minister talked about capital expenditure and the feel good factor. I do not know how they are feeling good because our stock market crashed by 1,200 points when we were sitting here for two hours 47 minutes. Of course, it recovered a little, but finally closed at minus 450 points. So, I do not know what feel good factor this Government is talking about.

Another thing they talked about was that all the sectors are doing well. This morning the hon. Minister of State for Finance, Shri Thakur, talked about how well the economy is doing. I was really happy to hear that. Again, this shows their fairy tale mode. They are living in a make-believe world because I do not see any of them really happening in reality. I come from a producer-State. Maharashtra has, probably, the largest investment, especially in the district that I come from. All the core sectors, be it the telecom sector, be it the auto sector, be it the realty sector, be it the coal sector, are in the negative. I do not know

where we are getting the data on the field vis-à-vis this data this Government is getting.

(1440/SM/RV)

I was very happy that he said that the banks were doing exceptionally well. I take this opportunity and humbly remind the hon. Minister of State for Finance that the Punjab Maharashtra Cooperative Bank is under a lot of distress.

We have asked for help from the Central Government. Yes, it is a multi-State Bank. I do understand that it is partly a State subject. But the Ministry of Finance of Maharashtra has written to them, asking RBI to give a clarification and help us because it is the bank which is not in Maharashtra only; it is in six other States also. So, would the hon. Minister in his reply give a clear-cut picture because we are willing to help?

I think this is not about you versus us. It is about you and us, helping the poor depositors of the PMC Bank in Maharashtra who are really under distress. This is hard-earned money which people are losing. Nobody is at fault; neither are you at fault, nor are we at fault. It is the system that was faulty which needs a change. So, I would urge and take this opportunity to ask him to give us some help.

He was talking so well about the sectors, be it CREDAI, be it SIM etc. These are all agencies which were pan India, the auto sector, the telecom sector and all kind of other sectors. Each of them has reacted negatively. I will give you a little data, Sir, to share with you.

The GDP which this Government has stated to be at 12 per cent, is growing not more than 8.5 per cent. The fiscal deficit was expected to be 3.5 per cent. Now it is already 3.8 per cent. We do not know where it is going to go. The estimated net tax revenue was Rs.16,49,582 crore. It is actually now only Rs.15,04,587 crore. The disinvestment target is very important. They are looking at selling LIC, Air India – God knows how many things! The disinvestment target was Rs.1,0,5000 crore. Their yield is only Rs.65,000 crore. They have not reached more than 60 per cent anywhere.

The Government's spending should have been Rs.2786379 crore despite the borrowing of Rs.63,086 crore. In the gross tax revenue, there is a huge lag. The number is rupees three lakh crore. We will have to verify what really the number is.

I still like to quote Shri Arunji, whom I remember clearly here. Unfortunately, he is not with us anymore. Sir, he came up with the FRBM Act. What was the FRBM Act? It was not just for the country but it was even for the State. The intent of the Government was exceptionally very good. What was it for? It was to control deficit; have good fiscal discipline and even the States so that nobody overspends and there is no bankruptcy. Nobody needs to be bankrupt because all the social sector related programme – be it healthcare, be it education – gets affected when the economy slows down.

What has been done in the FRBM Act? I still remember Shri Arunji, speaking from here. In 2014, he said that fiscal deficit has to stay at not more than 3.2 per cent and always less than 3.2 per cent. In your Government, it has reached 3.8 per cent. It is probably going to reach 4 per cent. You are using the Act. Now, why are you using the Act? The commitment was 3.4 per cent. If you disagree, I will be happy to listen to you in your reply. It would reassure us that if that is not the case. I will be much happy to know that that is not the case.

But the whole debt structure looks really very worried …(*Interruptions*).

Sir, I have only the last point about the farmers. I had a lot of points. But I will try to finish as soon as I can. Just two minutes.

For farmers, you have talked about doubling incomes. How are you going to do it in two years? The 16-point plan that you had made is a wonderful plan. Again, there is a fairy tale moment. It sounds wonderful on paper. But it is not going to happen because the whole 16 measures are like a long laundry list. There are only wishes and intentions.

I would like to highlight one point out of it. They talked about solar. The intention is exceptionally good. It is just to bring to the notice of the hon. Minister, in solar, 92 per cent solar modules come from China. I do not know where the Make in India business is headed. But 92 per cent modules come from China. There is a tax of 20 per cent on PV module part of the solar and you have capped imports. So, imports are capped. The taxation is going on. You have disrupted the whole thing. The policy has changed and the sentiment is that India is going through the difficulties.

The service tax now has become 18 per cent and the goods tax is 10 per cent. So, there is a gap of 8,000 crore of people who have already invested in the solar business. Who is going to pay this? States cannot afford to pay it; you

are not willing to pay it. The sentiment of the country is that there is a continuous disruption of policies.

(1445/SPR/MY)

That is the problem of the entire scheme of things. How are you going to mobilise the finance? Who are the investors? Which are the start-ups? How are you going to do? Another very good intention is, zero budget natural farming. These are very good steps. I am very happy to have organic farming. But where is the yield? We all grew up eating organic food? Can you quickly tell us what is this all about?

I need a clarification because I come from a producing State which is suffering due to the slabs of GST. They have made two major mistakes. They are doing in taxation again like they did in GST. There are multiple slabs. You put everybody in a slab. I do not know which Chartered Accountant's life has become serious. At least the ones who studied with me are not sounding very happy with the situation.

On cess and surcharges, I would say that so much cess is collected. How come we do not get cess for education in our State? They say that it is there in the kitty. It is your kitty. Same thing is about the NREGA. My friend Kanimozhi *ji* had spoken about the NREGA. Somebody said that it is very demand-driven. Yes, it is a demand-driven programme but the Labour Ministry had recommended the increase. If your economy is doing well, if you have so much money, if your banks are doing well, why do you not increase it to Rs.375 which is the recommendation of the Labour Department? …(*Interruptions*)

I want to raise two points concerning my State. I come from a State which needs answers to these. In the 15th Finance Commission, Maharashtra is being deprived by a 0.69 per cent cut. What is the reason? In the 14th Finance Commission, they said, it will be based on population. Whichever State manages population well, we will give them an incentive. The 15th Finance Commission says that it would be density-driven. So, when we are controlling population, हम कहते हैं कि यह घाटे का धंधा है। It is again resulting in disruption. It is 70 points. We fit them all. So, we should not have listened to all the recommendations. …(*Interruptions*) It is a very serious matter. When it comes to Centrally-sponsored schemes, when it comes to my State, there is five per cent less for Mid-Deal Meal Programme. There is a cut of 13 per cent due to the

recommendations of this Commission. My State is suffering because of the issues concerning the Commission.

On GST, I saw Shri Jayant Sinha speaking that my State is doing exceptionally well. I am happy to know that we are doing so well in GST. Please give us our Rs.15,000 crore, we would also say the same thing. My State has not got any of the monies. Now, they have given us a little amount of money. Now, they are saying that they would give it in two parts. If the money is in surplus here, if the banks are doing well, if the economy is doing well, and the whole fairy tale is going on that side of the nation, please give it to this kind of the nation also.

I just urge that this Government should wake up; they have to target; disinvestments are not doing well; the economy needs revival. The Government needs to accelerate growth; look into the fiscal deficit; promote private investments.

About the sentiment of fear, I am not saying only of speech, there is a general sentiment in this country; do not blame it on the other country; we can work on ourselves; if you do not take disruptive decisions, things can go well. If you cannot do it, there are a lot of good people in this country who would be happy to help you. I am sure the sense of this House is that in the larger interest of the nation, we do not want a defunct economy. We will help you; please take some suggestions. Thank you.

(ends)

1449 hours

SHRI DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): Thank you, Sir, for giving me an opportunity to talk on this Budget 2020-21. If I have to describe this Budget, in my late leader Dr. *Kalaignar* M. Karunanidhi's words, this is how he would have described this Budget. *"Oyyara kondayam, thazhampoovam, ulle irukkumam, eerum penum"* I will translate for you. Look at the beautiful woman. She has got lovely hair. Take a closer look. It is full of lice. Pun intended when I say `lice'. The reason I am saying is, the devil is in the details.

The Finance Minister stood here and made her speech as if she had ensured that the public, the middle-class population of India need not go to the auditor; they just have to click, double or triple click, and all the taxes are paid. To understand your new tax law, I have to pay more money to the auditor to find out in which bracket I fall and in which bracket I do not fall.

(1450/UB/CP)

Sir, is the hon. Finance Minister aware that the citizens of India are after her? It is not my thing. It is called Dosa Kada where they have explained a new taxation in a lovely way. Normally, a masala dosa is sold for Rs. 50. After the new taxation, the masala is sold for Rs. 45 but conditions apply. What are the conditions? If you want Sambhar, pay extra Rs. 15 or if you want chutney, pay extra Rs. 15. So, what I was getting for Rs. 50 is now for Rs. 80.

1450 hours (Shrimati Rama Devi *in the Chair*)

Sir, when I was born, and probably when you were born, the Indians would be asked to save. Savings was part and parcel of our blood. Everywhere you would go, they would say, "save, save, India needs savings". The Indian population is embedded with savings. What is the Government doing? The Government is discouraging people from saving. The Government has reduced the interest rate on savings to 7 - 8 per cent. There was a time when the interest rate was 11 - 12 per cent and there was a time when I used to get 13 per cent interest rate on my savings. Now, they want the public to spend their money.

Sir, there is one more dangerous fact here. Right now, if a person is getting Rs. 15,000, his PF contribution is taken for his protection. It is for the protection of a poor man. A youngster has just got a job, his PF account is opened in which contribution of the company is there and the employee also puts his contribution. With the new system in place, I do not get any exemptions.

If I were the employee, I would say, “Please do not deduct it. Increase my salary. Let me cross Rs. 15,000”. Countries like America can have it because they have a social security system. If something happens to a poor individual, he will be protected by the social security net. Where is this Government’s social security net? There is nothing. Instead of increasing the purchasing power of the common man, they are taking the money away from him.

Sir, even now, there are a lot of NGOs. Exemption was given under 80G when an individual gave donation to the NGOs. Why should I contribute? If I contribute, according to Shrimati Nirmala Sitharaman, since my tax slab has been turned into a new slab, I would not get any concession. The Government is going to discourage people instead of helping them.

Sir, they are the Government of India. Earlier, under the previous deposit insurance scheme, it was guaranteed that on the deposit, up to Rs. 1 lakh will be paid. You have increased it to Rs. 5 lakh. They should say that they will give 100 per cent sovereign guarantee for any individual who has deposited. Why can they not do that? It puts them in a very poor light.

Sir, I am surprised that the hon. Finance Minister never bombarded the Congress Party and blamed Nehru ji, Indira Gandhi ji and Rajiv Gandhi ji. It is because they made LIC profitable. LIC was created by the Congress Government. Here, they are conveniently not trying to use it because whatever suits them, they want to blame the Congress Party forgetting that, for the last five years, they are in power and they failed to realise all their mistakes. Today, everyone believes that they have to invest in LIC. The Government gave a sovereign guarantee that whatever money we invest in LIC, we can get the interest and we can get a rebate in the income tax. Now, the Government says, “Sorry boss, if you have invested in LIC, get lost. There is nothing. You have to go by the old slab”. I do not see how many countries in the world have dual layer tax system. Why can the Government not come with a single layer tax system and make sure that the people of our country are safe?

Sir, there is a preset recorded message of our Ministers, like Shri Ravi Shankar Prasad and Shri Hardeep Singh Puri. If anything happens, Shri Ravi Shankar Prasad would give his speech and say, “When there is a national calamity or when there is an earthquake, the only telecom service which functions will be BSNL” and Shri Hardeep Singh Puri will say, “If anything

happens, the first airlines to go is Air India". Even now when there is a crisis, two Air India aircraft went to China to get our Indians. What is the Government doing? The Government is selling it away. Then what are they going to do? You have nothing. Did SpiceJet go? Did Indigo go to get the Indians? No. Tomorrow, if the Government sells the BSNL and MTNL, whom are they going to give credit? Probably, they have to train Shri Ravi Shankar Prasad to change his preset recording to say, "Probably Jio". That is the name you like. Will Jio come and help them?

(1455/KMR/NK)

The Finance Minister is not only selling LIC, she is not only selling Air India, she is not only selling BPCL, BSNL and MTNL; she is selling the national highways too on the sly. She referred to it in the Budget Speech. She said that fast tag mechanism encourages greater commercialisation of our highways and the NHAI can raise more resources. The Government has started selling our highways now. You are making fast tags compulsory and now you want to sell it. She said, "I propose to monetise at least 12 bundles of highway of over 6,000 kilometres in the next four years". Why do you not sell the *… (Not recorded)* also? You can turn the *… (Not recorded)* into a marriage hall so that marriages can take place here! This shows that the Government has spent all the money.

The middle-class investor invests in companies like Reliance. Reliance is formed based on majority of the investors. Earlier, Reliance would pay 15 per cent dividend tax because of which its profit would reduce. Now, a middle-class man who invested in good shares has to pay 25 per cent to 30 per cent as dividend tax. So, the Government has not reduced the tax. It has conveniently, again on the sly, increased the tax.

Are you a good Finance Minister? A good Finance Minister's job is to reduce wasteful expenditure. Rs.12,000 crore of public money was spent on implementation of Aadhaar. Today if I want to get a passport, I have to have Aadhaar; if I want to open a bank account, I need Aadhaar; if I want to have a mobile connection, I have to have Aadhaar. Tomorrow when I die, to burn me or bury me they would ask for my Aadhaar. If my child has to go school, he would need Aadhaar. Aadhaar contains dynamic data. Why does the Government want to spend another Rs.4,800 crore on NPR? When you have the dynamic data with you under which every detail is captured, why do you need to spend that

money? You may say that the Supreme Court has objected to it. It is your court! Go there and tell the court that you are not using the secured data of fingerprints, iris data; you just want to use the metadata of people which is now being used for everything. The Finance Minister says you can use Aadhaar or PAN or passport, everything.

I read a newspaper article saying we do not know how many people are coming into the country and how many are going out. Your immigration system is completely computerised. You know everyone that is coming in and going out. As a good Finance Minister, you should have told the Home Minister not to destroy the country. Why do you want to spend Rs.4,800 crore when you have the dynamic data already with you?

Tamil Nadu gave the first call against NRC and NPR. My leader Mr. M.K. Stalin collected more than 2.5 crore signatures and we are going to send them to the President in order to wake you up from your slumber. You are trying to divide the country. …(*Interruptions*)

The Finance Minister talks about faceless appeals and says that hereafter income tax officers would not be there and it would not be biased and there would be tax-based data. What is happening in Tamil Nadu now? Because the elections are coming next year, Mr. Rajnikant got Rs.1 crore relief. …(*Interruptions*) Fantastic! Your offers are working. But your faceless office is targeting actor Vijay. Actor Vijay was picked up from his shooting spot and his whole schedule got cancelled resulting in a huge loss. …(*Interruptions*) I am concluding, Madam.

You say you are going to double the farmers' income. I think 35,758 farmers have committed suicide in India. Yet you say you are going to double their income. You want to launch Kisan Udan, Kisan Rail, cold storage facilities and all that. Where is the infrastructure in the villages for all this? Without developing the basic infrastructure in the villages, how are you going to do all this? After selling Air India, what are you going to do? …(*Interruptions*)

There was a question on AIIMS yesterday in the House. Of all the approved AIIMS, not a single AIIMS has come up yet. None of them has started any work.

(1500/SNT/SK)

I saw the Finance Minister talking like the CEO of Apple or Google. She used fancy words like Disruptive Technology, Artificial Intelligence, Internet-of-Things, 3D Printing, Quantum Computing, etc. And at last, it was said we are going to open data centres. You have allocated Rs.8,000 crores for the next five years for quantum computing through which you are going to snoop on us. That is the reason you are going to do that because it helps you snooping.

America spent 2 billion dollars in one year…(*Interruptions*) Madam, I am concluding. It is my last point. Regarding semiconductor manufacturing, the TSMC has said it will build a new semiconductor plant which will cost around 20 billion dollars. …(*Interruptions*)

माननीय सभापति (श्रीमती रमा देवी): आप बैठ जाइए, 11 मिनट हो गए हैं।

SHRI DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): I would like to ask a question, through you, Madam, to the hon. Minister. You speak about Tamil language everywhere. What have you done for Tamil language? You have not done a single thing for Tamil language. Here, you speak about Thirukkural. Have you even nationalised Thirukkural? No. You are trying to abuse us. You are spending crores and crores of rupees on a *… (Not recorded)* whereas you are not trying to spend any money on the classical language, Tamil.

Thank you, Madam.

(ends)

माननीय सभापति: श्री गोपाल शेट्टी जी।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर): माननीय सभापति जी, संस्कृत के बारे में जो टिप्पणी की गई है, इसे निकालना चाहिए और इन्हें खेद प्रकट करना चाहिए। ये तमिल लैंग्वेज के बारे में जो भी कहना चाहें, ठीक है, …(व्यवधान)

माननीय सभापति: हम रिकॉर्ड चैक करवा लेंगे।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): इसमें गलत क्या है?

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : क्या कांग्रेस पार्टी और आप इस बात का समर्थन करते हैं कि …(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) माननीय सदस्य ने भी कहा है। आपने तमिल लैंग्वेज की जो प्रशंसा करनी है कीजिए लेकिन आप संस्कृत के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे तो यह मंजूर नहीं होगा।…(व्यवधान) यह गलत है, आपको इस पर माफी मांगनी चाहिए और इसे कार्यवाही से बाहर निकालना चाहिए।…(व्यवधान)

माननीय सभापति: इसे निकाल दीजिए।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: ये गलती करते हैं लेकिन माफी नहीं मांगते हैं।

…(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : आपको बजट की जितनी आलोचना करनी है कीजिए, आपको एफएम की आलोचना करनी है कीजिए, आपको सरकार की आलोचना करनी है कीजिए, लेकिन आप संस्कृत भाषा के बारे में अपशब्द बोलेंगे तो यह मंजूर नहीं है, यह गलत है।…(व्यवधान) यह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए।…(व्यवधान)

माननीय सभापति: मैंने शब्द कार्यवाही से निकालने के लिए कह दिया है।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: केवल गोपाल शेट्टी जी की बात रिकॉर्ड में जाएगी।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: कृपया, आप शांत हो जाइए।

…(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरह से माननीय सदस्य ने संस्कृत के बारे में अपशब्द कहे हैं, वह निंदनीय और अशोभनीय है। उन्हें खेद प्रकट करना चाहिए।…(व्यवधान)

1538 बजे

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर): माननीय सभापति जी, आपने मुझे जनरल बजट 2020-21 का समर्थन करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

मैं देश के प्रधान मंत्री सम्मानीय मोदी जी का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। मैं इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने बहुत ही अच्छा बजट प्रस्तुत किया है। मैं मानता हूं कि संसदीय इतिहास में किसी महिला वित्त मंत्री ने ढाई घंटे से भी ज्यादा भाषण दिया और देश के सामान्य लोगों के बारे में सोचा, देश के मध्यमवर्गीय लोगों के हित के बारे में सोचा, देश के उच्च मध्यम वर्गीय लोगों के बारे में सोचा। उन्होंने कारपोरेट सैक्टर के लोगों के बारे में भी सोचा है और बजट में बड़े उद्योगपतियों के बारे में भी सोचा है। यह बजट दर्शाता है कि सबका साथ, सबका विकास वाला बजट है।

(1505/MK/GM)

इसलिए, मैं उनका एक बार फिर से धन्यवाद अदा करना चाहता हूं, उनका अभिनन्दन करना चाहता हूं। प्रधान मंत्री जी की अनेक योजनाओं में से एक सबके मन को भाने वाली योजना 'जन-धन एकाउंट' की है। जब हम लोगों ने जन-धन खाता प्रारंभ किया तो देश के सामान्य लोगों के घरों से, एक हिस्से से दो सौ रुपये, पांच सौ रुपये, हजार रुपये, ऐसा करते-करते साठ हजार करोड़ रुपये देश के खजाने में आया और देखते-देखते पांच सालों में यह पूंजी एक लाख करोड़ रुपये पार करके आगे गई है। इसके लिए हम सबको खुश होना चाहिए। ये सारे पैसे जो सामान्य लोगों के घरों में पड़े थे, वे चलन में आ गए। यह पैसा कामकाज में उपयोग आने लगा है। यह पैसा इतने बड़े पैमाने में, साठ हजार करोड़ रुपये से एक लाख करोड़ रुपये पार कर जाना यह बताता है कि सामान्य लोगों के पास आज भी पैसे आ रहे हैं। विपक्ष के लोग अपना रोना रो रहे हैं। लेकिन, यह बजट और बैंक में जो पैसे सामान्य लोगों के पास से आ रहे हैं, उससे पता चलता है कि सामन्य लोगों के पास आज भी पैसे आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा स्रोत, मैं मानता हूं कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ है, जो बिचौलिए के पास पैसा जाता था, जो येन-केन प्रकार से कुछ लोग पैसा खा जाते थे, जो सामान्य लोगों के हक को मारते थे, वह सारा पैसा प्रधान मंत्री के प्रयास के बाद सामान्य लोगों के पास आने लगा। सामान्य लोगों को जितना चाहिए, वे उसका उपयोग करते हैं और बचे हुए पैसे फिर से बैंक में जमा करते हैं। ये आंकड़े बताते हैं। इसलिए, मैं प्रधान मंत्री जी का फिर एक बार धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। 38 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने खाता खोलकर एक बहुत बड़ी क्रांति करके पूरे देश को ही नहीं बल्कि दुनिया को बता दिया है कि भारत कितनी तेजी से आने वाले दिनों में आगे बढ़ने वाला है। यह पैसा स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से सामान्य लोगों को मिलता है और इसके माध्यम से छोटे-छोटे व्यवसाय करने वाले लोगों को मुद्रा योजना के माध्यम से पैसे दिए जा रहे हैं। सामान्य लोग आज अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसमें एक बहुत बड़ा योगदान देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का और बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोगों का भी है। हम एक मानसिकता से बाहर निकल रहे हैं। वर्ष 2014 के पहले येन-केन कुछ ही लोगों को यह पैसा मिलता था। अब यह पैसा बड़े पैमाने पर सामान्य लोगों को मिल रहा है। इसलिए, मैं निश्चित ही सामान्य जनों का एक

प्रतिनिधित्व करने वाला हूं, इसलिए मैं उनके माध्यम से यहां सरकार का अभिनन्दन करना चाहता हूं।

प्रधान मंत्री जी की अनेक योजनाओं में से एक योजना 'एलपीजी कनेक्शन' के बारे में भी मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं। मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने आठ करोड़ लोगों के घरों में एलपीजी गैसे पहुंचाने का काम किया। हमारे विपक्ष के लोग आंकड़े दे रहे हैं कि अभी बहुत लोगों को मिलना बाकी है, बहुत लोगों को मिला नहीं है। मैं भी इस बात से सहमत हूं कि अभी बहुत लोगों को मिलना बाकी है। लेकिन, सर्वे के बाद जो बीपीएल का आंकड़ा बना था, वह वर्ष 2011 में बना था। वर्ष 2011 में इसको किसने तैयार किया? यह तो इन्हीं लोगों ने तैयार किया है। मैं मानता हूं कि इस सर्वे को फिर एक बार वर्ष 2020 में करके मैक्सिम लोगों को इसमें जोड़ने की आवश्यकता है। मैं मानता हूं कि जो सामान्य लोग हैं, ऐसे सारे लोगों को इसमें जोड़ने की आवश्यकता है।

बहुत सारे लोग 200 फीट के घर में, 300 फीट के घर में रहते हैं। वे दलित नहीं हैं, वे आदिवासी नहीं हैं, लेकिन वे गरीब हैं। हम ऐसे लोगों को एक गरीब की निगाह से देखते हुए सभी लोगों को, जो सरकार का जो लाभ है, वह पहुंचाना चाहिए। इसके लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। एलपीजी के कनेक्शन के बारे में तो मैं यही कहूंगा कि क्यों विपक्ष के लोग इस बात की मांग नहीं करते हैं, प्रधान मंत्री जी को एक सुझाव दें कि पचास प्रतिशत पैसा आप दीजिए और पचास प्रतिशत पैसा राज्य के लोग लगाएंगे और यदि ये दोनों फिफ्टी-फिफ्टी के पार्टनर्शिप में आते हैं तो बचे हुए सभी लोगों को, एलपीजी कनेक्शन मिल सकता है और देश में एक बहुत बड़ी क्रांति होकर महिलाओं के जीवन में एक नया बदलाव हम सब लोगों को देखने को मिलेगा।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मैंने अपने मतदार संघ में एक प्रयास किया, मैं आपके माध्यम से देश के लोगों को इस बात को पहुंचाना चाहूंगा। हमारे पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान जी ने इसका बहुत बार उल्लेख भी किया है। मुम्बई में बहुत बार आकर उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। मैंने अपने मतदार संघ में सीएसआर के माध्यम से प्राइवेट डोनरों के पास से पैसा इकट्ठा करके लोगों को चूल्हा मुफ्त में दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि लोग सामने आए, उन्होंने गैस के कनेक्शन का पैसा भरा, डिपॉजिट का पैसा भरा और सिर्फ एक चूल्हा देने की वजह से पन्द्रह हजार लोगों को मैं अपने मतदार संघ में एलपीजी का कनेक्शन पहुंचा पाया। इसकी एक दूसरी वजह यह भी है कि जब सामान्य लोग एलपीजी का कनेक्शन पाने के लिए एजेंटो के पास, ऑफिसरों के पास जाते हैं तो उनको कोई नहीं पूछता है।

(1510/YSH/RK)

जब एक चुना हुआ प्रतिनिधि इस प्रकार की स्कीम को हाथ में लेता है तो ऑफिसर्स हमारे पास से लोगों तक स्कीम को ले जाते हैं। इसमें बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव लाकर बहुत से लोगों को लाभ हुआ है। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि राज्य सरकारों के साथ मिलकर, जो गरीब लोग हैं या मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, उन सभी लोगों को तुरन्त एलपीजी का कनेक्शन मिले।

सभापति महोदया, जल मिशन के बारे में राष्ट्रपति महामहिम के अभिभाषण में भी उल्लेख हुआ है और इसका बजट में भी उल्लेख हुआ है। मैं हमेशा एक बात से चिंतित रहता हूं कि हमारी जो संघवाद प्रणाली है, उसका एक महत्व है और होना भी चाहिए, लेकिन सामान्य लोगों के जीवन-यापन करने की जो आवश्यक वस्तुएं हैं, उसके बारे में हम संघवाद प्रणाली के कंसेप्ट को लेकर कितने दिनों तक आगे चलेंगे? क्या इसके बारे में कोई डिबेट या डिसकशन नहीं होना चाहिए? क्या इसके बारे में मानसिकता बदलने की आवश्यकता नहीं है? सामान्य लोगों को जो कुछ भी चीजें चाहिए, उदाहरण के तौर पर, चाहे पानी हो, बिजली हो, एलपीजी का कनेक्शन हो या लोगों को घर मिलना हो तो इन सारी बातों को हमें फेडरेलिज्म के चश्मे से न देखकर सामान्य लोगों की निगाह से देखना चाहिए। केन्द्र सरकार द्वारा जो योजनाएं लाई जाती हैं, उन योजनाओं को राज्य सरकार द्वारा तुरंत हाथ में लेकर सामान्य लोगों का भला करने की जरूरत है।

मैं मुम्बई शहर से आता हूं। मुम्बई शहर का पूरे देश में बोलबाला है। मुम्बई शहर देश की आर्थिक राजधानी है। मैं शिव सेना के मेरे मित्रों से इस बात के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि हम आज भी मुम्बई शहर में वर्ष 2000 का डेटम लाइन लेकर चल रहे हैं। आज हम वर्ष 2020 में आ गए हैं। वर्ष 2000 से वर्ष 2020 तक मुम्बई शहर में बड़े पैमाने पर झुग्गी-झोपड़ियां बढ़ गई हैं, लेकिन आज भी उनको पानी नहीं दिया जा रहा है। यह मुम्बई जैसे शहर की स्थिति है तो पूरे देश की क्या स्थिति होगी? हमें इसके बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। प्रधान मंत्री जी चिंतित हैं कि लोगों को पानी मिलना चाहिए। प्रधान मंत्री जी चिंतित है कि लोगों को लाइट मिलनी चाहिए। प्रधान मंत्री जी चिंतित है कि सभी को घर मिलना चाहिए, लेकिन सरकार में बैठे हुए कुछ सरकारी अधिकारी हैं, जो अपनी मानसिकता से बाहर नहीं आते हैं। फॉरेस्ट लैंड पर आज भी इलैक्ट्रिसिटी का कनेक्शन देने के लिए लोगों को क्या-क्या परेशानी होती है, यह हमारे जैसे सांसद बहुत नजदीक से अनुभव करते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि जब हम अगला बजट पेश करें तो उससे पहले देश के सभी लोगों के लिए शौचालय, पानी और बिजली के कनेक्शन के साथ-साथ एलपीजी कनेक्शन की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी।

सभापति महोदया, आजादी के 72 सालों के बाद भी अगर लोगों को अपने घरों को रिपेयर करना हो तो उसके लिए भी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। डिफेंस लाइन के अगल-बगल बसे हुए लोगों को आज भी कमरे को रिपेयर करने की परमिशन नहीं मिलती है। जिन लोगों के घर टूट गए तो कॉरपोरेशन द्वारा परमिशन देने के बाद वर्ष 2011 का एक सर्कुलर आ गया, जिसके बारे में मैंने लोक सभा में बहुत बार आवाज उठाई, लेकिन आज भी उस सर्कुलर का अंत नहीं हुआ है।

मैं इस बजट के माध्यम से कहना चाहूंगा कि वर्ष 2011 का जो डिफेंस का सर्कुलर है, जिसको हमारे स्वर्गीय पर्रिकर जी ने रैक्टिफाई किया था, वह सर्कुलर तुरंत इंप्लीमेंट होना चाहिए। आज वर्ष 2016 के सर्कुलर को भी चार साल हो गए है, लेकिन हमारे अधिकारियों की मानसिकता नहीं बदलती है इसलिए मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वर्ष 2011 के सर्कुलर को रद्द करके वर्ष 2016 के सर्कुलर को अमल में लाया जाए। इसके लिए हमें प्रयास करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदया, इस बजट में और राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी कर्त्तव्य के दशक का उल्लेख हुआ है। हमें अपने कर्त्तव्यों का पालन करना चाहिए। हम अपने अधिकारों की बात तो सभागृह के बाहर भी करते हैं और सभागृह में भी करते हैं। हमें जहां पर भी मौका मिलता है, वहां हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन हम सभी को अपने कर्त्तव्यों का भी पालन करना चाहिए, इसका संकेत हमें राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के माध्यम से और बजट से भी मिला है।

मैं किसानों के बारे में संक्षेप में बात करना चाहूंगा। किसानों की हालत दयनीय है। किसानों के बारे में महानगर पालिकाओं में चर्चा होती है। किसानों के बारे में विधान सभाओं में चर्चा होती है। किसानों के बारे में लोक सभा में भी चर्चा होती है। सभी लोग एक सुर में बात करते हैं कि किसानों की हालत को बदलना है, लेकिन जब देश के प्रधान मंत्री जी किसानों के लिए कोई स्कीम लाते हैं तो फिर से फेडरेलिज्म स्ट्रक्चर बीच में आ जाता है और फिर कुछ राज्य सरकार के लोग कहते हैं कि हम इसे अमल में नहीं लाएंगे। हम इसे इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि सभी के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से खाते खुले हुए हैं तो क्यों केन्द्र सरकार सारा पैसा उनके खाते में नहीं भेजती है? राज्य सरकार को सम्मान देना चाहिए, यह लोकशाही है, लेकिन आप कितने दिनों तक उनका सम्मान करते रहेंगे। वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। सामान्य लोगों को लाभ नहीं पहुंचाते हैं। केन्द्र सरकार द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से प्रधान मंत्री जी ने किसानों का जो पैसा घोषित किया है, वह किसानों को मिलना चाहिए। मैं इसकी भी मांग करना चाहूंगा।

(1515/RPS/PS)

सभापति जी, मैं कभी-कभी इस बात से भी हैरान-परेशान होता हूं कि अपने देश में कुछ किसान ऐसे हैं, जो बहुत कम जमीन में किसानी करते हैं और बहुत बड़ा मुनाफा कमाते हैं। मैं अनुराग ठाकुर जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे सारे किसानों की आप एक लिस्ट बनाइए और वह लिस्ट प्रधान मंत्री जी को दीजिए, उनके नाम पद्म श्री और पद्म भूषण की लिस्ट में इन्क्लूड कीजिए। जैसे प्रधान मंत्री जी ने हम सभी सांसदों को दत्तक बस्ती योजना के माध्यम से एक-एक सांसद क्षेत्र हम लोगों को दिया और हम लोगों को काम पर लगाया, उसी तरह से कम जमीन पर प्रॉफिट करने वाले लोगों को पांच-पांच, दस-दस किसान दें, अगर वे एक साल में उनके भी खाते में इतना ही प्रॉफिट कमाकर देते हैं तो उनको पद्म श्री और पद्म भूषण देना चाहिए। इससे बहुत सारे लोग आगे आएंगे और किसानों का भला होगा। सरकार के ऊपर जो लोड है, उससे भी हम छुटकारा पाएंगे, यह भी मुझे विश्वास है। मैं इस बात को आपके माध्यम से सरकार और अन्य जो कोई भी सुनते हैं, उन तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं।

सभापति जी, जब कर्त्तव्य की बात आती है, तब मैं कभी-कभी हैरान-परेशान इसलिए भी हो जाता हूं कि जो फल-भाजी पैदा करने वाले लोग हैं, फूल वाले हैं, फल वाले हैं, इन सारे लोगों को उपभोक्ता के रूप में अधिक पैसे देने की मानसिकता में हम सभी लोगों को आना पड़ेगा। हम सामान्य होटल में जाते हैं तो 100 रुपये या 200 रुपये की एक प्लेट भाजी खाते हैं, लेकिन अगर कोई भाजी वाला पांच रुपये या दस रुपये ज्यादा मांगेगा तो उसे देने की मानसिकता इस देश के हम जैसे सारे

लोगों में नहीं होती है। मैं मानता हूं कि जब हम कर्त्तव्य का यह दशक मनाते हैं तो हमें इस पर भी सोचकर, इन सारे लोगों की मदद करने का प्रयास करना चाहिए, इससे इनके जीवनमान में एक बड़ा बदलाव आएगा। मुझे मालूम है कि हम डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं और हम सारी दुनिया के साथ जुड़े हैं, इसलिए हम दाल की कीमत अपने तरीके से नहीं तय कर सकते हैं, शक्कर की कीमत अपने तरीके से नहीं तय कर सकते हैं क्योंकि अगर हम कम या ज्यादा भाव में देंगे तो एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट में इसका भी एक मामला आता है। लेकिन कम से कम इस प्रकार की चीजों पर हमें तुरन्त सोचने की आवश्यकता है।

हाउसेस टू आल के बारे में प्रधान मंत्री जी ने बात कही है, मैं इसे ज्यादा विस्तार में न बताते हुए, सीधे मुंबई शहर पर आना चाहूंगा। मुंबई शहर में आज सभी प्रकार के उद्योग बन्द पड़े हैं। मुंबई शहर में एक ही इंडस्ट्री चलती थी – हाउसिंग इंडस्ट्री। लेकिन यह इंडस्ट्री भी इन दिनों पूरी बन्द पड़ी है। जब हम हाउसिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं तो पोलिटिकल फील्ड हो या मीडिया हो, इन सारे लोगों को लगता है कि पोलिटिशियन लोग बिल्डर लोगों की बात करते हैं। बिल्डर लोग सिर्फ घर बनाते हैं, लेकिन हाउसिंग इंडस्ट्री के माध्यम से लाखों लोग रोजगार से भी जुड़े हुए हैं। जब हाउसिंग इंडस्ट्री बन्द पड़ती है, तब लाखों लोगों का रोजगार चला जाता है। मैं 100 चीजों का उल्लेख कर सकता हूं, इतने सारे लोगों को काम देने वाली यह इंडस्ट्री है। इसलिए आने वाले दिनों में अगर हमें इकोनोमिक ग्रोथ करना है तो हाउसिंग इंडस्ट्री पर हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ...(व्यवधान) सभापति जी, मैं संक्षेप में अपनी बात को पूरी करूंगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस इंडस्ट्री के बारे में भी हमें तेजी से ध्यान देने की आवश्यकता है।

सभापति जी, मैं रेलवे के बारे में संक्षेप में अपनी बात रखना चाहूंगा। हमारी बहन सुप्रिया सुले ने यहां बताया कि हर दिन मुंबई जैसे शहर में सात लोगों की मृत्यु होती है। रेलवे के बारे में मेरा पहला भाषण रिकॉर्डेड है, उस समय यह आंकड़ा दस मौतों का था, इसलिए मैं उनके आंकड़े को छ: या पांच पर नहीं लाना चाहता हूं। मैं उनकी बातों का समर्थन करते हुए, कहना चाहता हूं कि आज भी मुंबई शहर में सात लोग हर दिन मरते हैं। मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि डोर क्लोजर लगाने के बारे में, जिस बात का मैंने 2014 के बजट के समय उल्लेख किया था, आज मुंबई शहर की बहुत से ट्रेनों में डोर क्लोजर लगे हैं और जानें जाना कम हो गयी हैं, दस से हम सात तक आए हैं, लेकिन हमें आने वाले दिनों में तेजी से इन आंकड़ों को कम करना पड़ेगा। मैं अपने शिवसेना के मित्रों से अपील करना चाहूंगा कि मुंबई शहर में देवेन्द्र फडनवीस जी ने मेट्रो रेल का काम बहुत कम समय में बहुत तेजी से आगे बढ़ाया है, उस मेट्रो रेल का काम शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ाएं, तभी मुंबई शहर में रोज इतने लोगों का मरना बन्द हो जाएगा और मुंबई शहर के लोगों को बहुत बड़ी राहत पहुंचेगी।

अन्त में, इस बजट में हजारों फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलने की बात देश के प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने की है, मैं उसका स्वागत करता हूं। इसमें भी एक बहुत बड़ी ताकत है। कोर्ट में जो इतने केसेज चलते हैं, अगर उनका निपटारा हो जाए तो इकोनोमी बूस्ट होने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। आज कारपोरेट सेक्टर के लोग दूसरों को सिर्फ हैरान-परेशान करने के लिए भी कोर्ट में बहुत

सारे केसेज दर्ज कराते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पांच-दस साल इसका निपटारा होने वाला नहीं है। इस तरह से इकोनोमी को स्लो-डाउन करने का यह भी एक बड़ा जरिया है।

(1520/IND/RC)

महोदया, फास्ट ट्रैक कोर्ट खुलने से सारे झमेले खत्म हो जाएंगे और कोई नया झमेला खड़ा करने का कोई प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि कोर्ट में जाने से तुरंत केस का निपटारा हो जाएगा, ऐसा डर लोगों के मन में पैदा होगा। प्रधान मंत्री जी ने पांच ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कही है, कुछ लोग इस बात का मजाक बनाते हैं। हम जब बचपन में थे, तब गरीब घर के लोग अपने बच्चों के बारे में यह सपना देखते थे कि मेरा बच्चा पढ़कर यदि एसएससी का एग्जाम भी पास करता है और पैसे कमाता है, तो उनका सपना 15 साल में पूरा होता। आज प्रधान मंत्री जी ने तो केवल पांच साल का सपना देखा है और हम सभी लोगों को मिलकर प्रधान मंत्री के सपने को सच करके देश के लोगों को इस झंझट से बाहर निकाल कर अच्छा जीवन जीने का अवसर देने का काम करना है। मैं मानता हूं कि यदि सभा में सभी इस बात के लिए खड़े हो जाएंगे, तो पांच ट्रिलियन ही नहीं, जयंत सिन्हा जी ने जो दस ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कही है, उसे भी हम प्राप्त कर सकते हैं।

महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

(इति)

1521 hours

SHRIMATI PRENEET KAUR (PATIALA): Madam Chairperson, I thank you for giving me time to speak on the Union Budget.

At the outset, let me say that the Union Budget is a sacrosanct document, a document that every Indian looks to with great hope and expectation - something that might improve their lot and alleviate the problems of their lives. Therefore, my comments as a Member of this House's principal Opposition Party may not be treated as partisan but as a small part of the large collective responsibility that we all share.

We must discuss ways and means of how to steer ourselves out of our present predicament. The last time India was in this predicament was when there was a serious economic crisis, *i.e*. the balance of payments crisis. In 1990-91, Dr. Manmohan Singh as the then Finance Minister guided the country out of the economic crisis and, in the process, imparted a new direction and orientation to our economy.

Our problems are not unknown to the people seated here - low economic growth, increasing unemployment, falling exports, and rising farm distress - all amidst the great expectations of our people who gave a decisive mandate to this government only last year.

The Budget is based as always on certain presumptions -
presumptions of 10 per cent nominal growth, and presumption of 12 per cent growth in revenue. These presumptions certainly look a little optimistic given the current tepid economic scenario.

Let me speak about some issues that are pertinent to the State I represent, the State of Punjab

Firstly, there is little denying the fact that distress in rural areas is growing. The concessions which were given earlier in this financial year to business have naturally aroused similar aspirations from the rural sector also. However, that special stimulus for the rural economy is missing. It is really surprising that allocation for MGNREGS for the next year has been reduced below the Revised Estimates of the current year at a time when there is general talk of a need to boost rural economy. I hope the Finance Minister will take note of it. Today, across the country, the rural poor look forward to NREGA funds to undertake small infrastructure works in villages. Let us keep their hopes alive.

In agriculture, there are some issues especially the one that has been expressed on converting fertilizer subsidy into DBT. These steps must be taken with due caution and after factoring both intended and unintended consequences lest our farmers are put to undue harassment.

Similarly, the Pradhan Mantri Krishi Bima Yojana deserves to be reviewed and re-oriented as it does not suit the interests of Punjab's farmers. This scheme should be farm / plot based instead of being area based. The indemnity level should be more than 90 per cent (up to 95 per cent) should be allowed and it should be based on last year's yield of affected and insured farmers. Post-harvest losses in the *mandies* due to natural calamities should also be covered. The localized calamities should also cover the losses due to unseasonal rainfall during Rabi crops and increase in cost of cultivation of Kharif crop due to deficient rainfall.

(1525/SNB/ASA)

As most of the farmers are facing huge economic distress, no premium should be charged from them and it should be shared between the Central and State Governments on 60:40 basis. The State has already taken up the matter with the Prime Minister’s Office in a letter dated 31/05/2019.

The next point is that the State of Punjab is facing a ground water crisis putting a serious question mark on the long-term sustainability of our agriculture and in turn, our country’s food security. The Budget does not offer anything for the State in this regard. In fact, notwithstanding that Punjab has the highest rate of decline of groundwater in the country it has sadly been omitted from the list of seven States selected under the *Atal Bhujal Yojana.* The State Government has taken up this matter with the Prime Minister and the Ministry of Jal Shakti and I would only expect that Punjab is given its due.

In parallel, there must be strong steps taken by the Government of India to promote diversification of agriculture through assured marketing of alternative and less water-intensive crops like maize etc. We were hoping for an announcement in the Budget, but it seems to have missed the attention of the Government. Let us not delay anymore, lest it would be too late.

I would also like to highlight one aspect that needs the collective attention of the House. The Commission on Agricultural Costs and Prices (CACP) has unfortunately given some recommendations of ending MSP based open-end

procurement of paddy and wheat largely on account of the inefficiencies in food management. This will be the final nail in the coffin of our already beleaguered farmers. I strongly urge the Government to put aside any such plan in case it truly believes in the welfare of farmers.

As I end, let me say that India's growth story, with dreams of becoming a super power that we dared to flirt with, is now at crossroads. The optimistic talk ten years ago – that we can become a developed nation in two to three decades – has today been replaced by cautious pragmatism of economists who warn of the real danger of India falling into the `middle-income trap'.

In the backdrop of this growing pessimism that we must renew our pledge to fulfil, in the words of Pandit Jawaharlal Nehru, `our tryst with destiny'. Here, the words of Franklin D Roosevelt in his famous speech during the Great Depression may also be instructive in this -- `The only thing we have to fear, is fear itself'. While I pray that we may economically rise once again as a great nation, I only hope that the Government will equip the country with the right economic policies to help catalyse our economic growth and development.

Thank you.

(ends)

1529 hours

SHRIMATI APARAJITA SARANGI (BHUBANESWAR): Madam Chairperson, thank you for giving me this opportunity. As I stand here to speak on the Budget for the financial year 2020-21, I would be failing in my duty if I do not thank the hon. Prime Minister whose vision has guided the Budget and the hon. Finance Minister who has worked extremely hard to present this Budget which addresses the needs and concerns of the common man. As our hon. Prime Minister has rightly said, this Budget has both vision and action and it focuses on boosting economic growth which would strengthen the foundations of Indian economy in this current decade.

Madam Chairperson, I would say with all conviction at my command that this particular Budget is an extraordinary reflection of the balance between intent and content, vision and provision. When we read this Budget, about six major sectors and 24 key areas come to mind. Against the backdrop of the current economic scenario, this particular Budget will definitely facilitate investment, spur consumption growth, give a push to infrastructure projects, give a fillip to rural and agricultural development and strengthen social sector interventions which would go a long way in bringing relief to the poor, the needy and the vulnerable sections of the country.

(1530/RU/RAJ)

This is an age of technology and we are all aware of the fact that emerging technologies like blockchain, 3D printing, artificial intelligence, quantum computing, etc. have evolved and encompassed all aspects of our day-to-day existence. And I am extremely glad to inform this august House that this particular Budget has recognised this fact and is all out to leverage the technologies for the benefit of society and the common man.

There are two things which I would like to mention here. All of us are aware of them. Firstly, there is a provision of Rs. 8000 crore for National Mission for quantum applications and technologies. We are also talking of the use of artificial intelligence in healthcare, in streamlining GST and different direct taxes. We are also talking of setting up of Data Centre Parks. It is very encouraging and it is a very wonderful step.

There is also a provisioning of about Rs. 6000 crore for BharatNet Programme. This particular Programme is very interesting in the sense that

there will be one lakh panchayats which would be having fibre connections to homes. I am sure that all these efforts in boosting technology and leveraging technology will go a long way in benefiting all of us and will create ample job opportunities in the days to come.

After technology, we move to the next area which is agricultural and rural development. There are eight key areas which come to my mind out of the list of 16 points. I would definitely try to list out eight action points. The first and foremost is this and I would like to draw the attention of this august House to the debate on an allegation which I have been hearing for the past two days regarding less allocation for Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme.

With all humility, I would like to inform the House that I had the privilege of working as a Joint Secretary to the Government of India and I was handling Mahatma Gandhi NAREGA for five full years, from 2013-2018. This particular allegation that there is less allocation is baseless.

Madam, the comparison of BE can always be BE. The comparison of RE of last year cannot be compared with BE of this year. The Budget Estimate for 2019 for MGNREGS was Rs.61,115 crore and this time, the BE says that it is Rs.61,500 crore. Now, last year, RE for MGNREGS went up Rs. 71,000 crore. I have handled this Programme and I know the concern of this Government for the poor, the vulnerable sections and the labourers. the MGNREGS is a demand driven Programme, and whenever there has been a need for money or wages, the Government has come up and has checked in a lot of funds for actually meeting the wages.

From an amount of Rs. 61,115 crore last year, it went up to Rs. 71,000 crore and this Government being so very considerate for the needs of the poor, there is no reason why we should believe that this Government will not come up again at the RE stage if the demand is there on the ground.

So, my dear friends on the right, let us all compare apples with apples and let us not compare apples with oranges. We have to compare BE with BE and we cannot compare BE with RE. That is the whole point.

Secondly, I would like to mention a very major step that the Government has planned through this Budget regarding agriculture and rural development. That particular step is taking the States on board with a spirit of cooperative and

competitive federalism, by encouraging them to go for a massive structural reform in the farming sector by formulating Acts on the basis of model Acts for contract farming, for land leasing and for agricultural and livestock production and marketing. These reforms have been pending for long. If these are done, there would be tremendous employment generation in the farming sector and many of the long standing problems of the farmers would be solved.

(1535/NKL/VB)

Now, the third issue which I would like to point out here is the idea of the 'Kisan Rail' and the 'Krishi Udan'. These are extremely good ideas. We are aware of the fact that we have a lot of fresh fruits and vegetables that go waste. We need to have transport logistics, we need to have proper coal supply chain, and for that matter, we are talking of Indian Railways coming up with 'Kisan Rail' for transport logistics, and 'Krishi Udan' for taking our fresh fruits and vegetables to national and international destinations.

We are talking of PM-KUSUM. This is the fourth point. We are talking of leveraging solar energy. About 20 lakh farmers would be given funds for solarising their pumps, and 15 lakh farmers, who already have grid connected water pumps would be given funds for solarising them. What a wonderful idea it is! If it is executed properly, what benefit it would give to the farmers, I think, we all can understand that.

Madam Chairperson, all of us, over a period of time have been talking of diversification in agriculture. But the credit goes to our farmers and to our Government that today, 311 metric tonnes of horticulture produce actually is much more than the food grain produce. This is all because of the farmers' and the Government's intervention. So, to encourage such farmers, the Government has come up with the concept of 'One district, One Crop', which I am sure is going to encourage exports in the days to come.

We are talking of bridging the infrastructure gap. As far as Agri-storage facilities are concerned, our women would come up as *Dhanya Lakshmi*, and there would be storage godowns by the women for the farmers of the villages.

Madam Chairperson, we are also talking of milk production. The milk processing capacity is planned to be enhanced from 53.5 million tonnes to 108 million tonnes. Just imagine the kind of encouragement the milk producing farmers would be getting. We are talking of marine fishery changes and marine

fishery revolution, I would say, if it is not an exaggeration. I would say that we are talking of the development of marine fisheries sector in a major way. We are talking of 'Sagar Mitras'. More than 3000 'Sagar Mitras' would come up. The rural youth would be getting employment. Apart from that, we are aiming at 200 lakh tonnes of fish production by 2022-23. What a major leap we are thinking of; what a dream it is! This Government has shown, in the last five years, that whatever it dreams, it actually translates that into reality.

The next point I would definitely like to focus on is the 'Jal Jeevan Mission'. This shows our hon. Prime Minister's vision, his dream, and his focus on water stressed districts of the country. This is a welcome step. The agricultural credit is planned to go up hugely from Rs. 11.5 lakh crore to Rs. 15 lakh crore, which is going to be a major step, and we all need to thank the hon. Prime Minister, the hon. Finance Minister, and her entire team for having conceptualised such a wonderful Budget.

Madam, now we come to investment. I will just take about 10 to 15 minutes. This is a very important point. Therefore, I would request you to give me some more time. To strengthen the investment sector, we are talking of a single investment cell for expediting grant of licenses and promoting entrepreneurship. Five new smart cities would come up in PPP mode for promoting entrepreneurship.

Madam, we have all been talking about the Dividend Distribution Tax. This will almost release Rs. 25,000 crore for the companies to invest, and of course, the rejig of the Personal Income Tax slab would leave a lot of money in the hands of the individual for spending.

Madam, now, I come to infrastructure. Just give me one more minute. I would like to read out what hon. Prime Minister said on the speech of his Excellency, the hon. President of India, and that says all about the vision of the Government about infrastructure. This is what our hon. Prime Minister said in this House, the other day.

(1540/KSP/PC)

I would read out. I quote:

> "For us, infrastructure is a combination of aspirations and achievements, about connecting people to their dreams, people's creativity to consumers, infrastructure is connecting a child to her

school, a farmer to the market, a businessman to his customer; it is about connecting people to people."

We are talking of National Infrastructure Pipeline, and we are talking of 6,500 projects. As far as social sector interventions are concerned, in the health sector, there is an increase of 15.4 per cent in the health budget. We are talking of about Rs. 69,000 crore which is a huge amount. The Jan Aushadi Kendras will have 2,000 medicines from this year with about 300 surgical equipment. What a leap? Urban local bodies will provide internships and degree level online education programmes started by institutions which rank within top 100 in the National Institutional Ranking Framework.

Madam, I would like to inform this august House about one thing. If you really read the Budget carefully, if we think about the works that this Government has done in the last five years and the kind of vision that our hon. Prime Minister has, I would definitely say that we have moved from a regime of policy paralysis to a regime of policy action, we have moved from policy of scams to a policy where the Government is trying to provide a transparent Government.

As I conclude, I am reminded of the words of Ex-US President Barrack Obama. He had said, "A Budget is not just a series of numbers on a page; it is the embodiment of the value of a nation", and this particular Budget, which was presented by our Finance Minister, is the embodiment of our values. We are trying to care for our society, supporting innovation, and building good human resources.

With these words, I fully endorse this Budget for the financial year 2020-21 presented by our hon. Finance Minister.

(ends)

1542 hours

SHRI HASNAIN MASOODI (ANANTNAG): Madam Chairperson, I thank you for permitting me to speak on the Budget.

Madam, Budget is not a mere Statement of Revenue and Expenditure. It reflects the ambitions and aspirations of the masses, an effort to address the failures, rectify the mistakes, and help realise the dreams. The Budget must reasonably take cognizance of challenges and propose steps to meet those challenges.

The status of economy is disturbing. There is an agreement between all of us that it is not to the satisfaction of the people and to the satisfaction of the decision makers. All the universally accepted indices, all the indicators of fiscal health point to a downslide in the economy, including the sluggish growth of GDP. Some key challenges were expected to be taken note of and they confronted the Government. One of them was the ever-increasing unemployment. It is not only millions of our young men are unemployed, but even those in employment are under-employed or their employment is not commensurate with their qualification.

The Budget was also expected to take note of the decrease in consumption and the consequent decrease in demand which, in turn, leaves manufacturing subdued. The Budget was expected to go in for some massive tax reforms to give relief to the tax payers and also promote investment.

Madam, one of the major challenges before the Government was also resource mobilisation and giving a fillip to agriculture. A closer look at the Budget points to a mere patch work. We see a mere patch work. The Budget lacks vision. We do not find path breaking decisions on thrust areas. The deficit, though estimated to be 3.8 per cent, would anywhere be around 4.6 per cent.

(1545/KKD/SPS)

The Government owes FCI Rs. 2 lakh crore, and there are borrowing by those to whom the Government has to pay in the same way. But the agriculture does not get the due attention. Eleven per cent decrease in subsidy on fertilisers will hit the farmers hard. It may lower the use of fertilisers, and in turn, impact

agricultural production. Though PM-KISAN Scheme has shown an increased allocation of 37.9 per cent, the benefit has not reached the beneficiaries. A mere Rs. 1,241 crore has reached the target group out of previously allocated Rs. 20,000 crore.

The resource mobilisation is not to go on expected lines. It is highly doubtful if the Government would be able to get the money it plans to mobilise by disinvestment. With the success rate of 62 per cent disinvestment the previous year, it is highly doubtful and hard to believe that the Government would be able to mobilise the additional Rs. 2.10 lakh crore from disinvestment.

The tax reforms are also lackadaisical with half-hearted measures. Most of the tax payers are not to benefit by the new tax regime because of non-availability of benefits of deductions and exemptions. Changes in tax governance are also not to get the desired results, and stripping the Appellate Authority of its powers may prompt the tax payers to flock to the high courts and invoke the writ jurisdiction.

Though there is some relief to the start-ups, but the Dividend Distribution Tax relief is also not going to get the desired result because the recipient shall have to pay, in most of the cases, tax at the higher rate. Even if, as has been pointed out, it helps the corporates to have an additional amount of Rs. 25,000 crore, but the real target may be the recipient, who receives the dividends. So, so far so much is the overview of the tax.

But let me now come Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir has recently experienced a massive assault on its autonomy, territorial integrity and identity. It is true that Rs. 20,000 crore has been earmarked for Jammu and Kashmir in the current Budget, but there can be no trades-off between political aspirations and budgetary allocations. The State that has 5,000 years history has been reduced to a Municipality, and Rs. 20,000 crore may not be that important, more so when Rs. 80,000 crore was previously allotted and the benefit did not reach the target or did not reach the ground.

There are 61,000 casual workers, consolidated workers and daily waged workers. I expect and I would request the hon. Finance Minister to ensure that steps are taken for their regularisation. They are on the streets. They have not been paid for months together, and they are waiting for their regularisation from anywhere between five and 10 years.

The electricity distribution system is in shambles. In sub-zero temperature, most of the villages, most of the rural Kashmir and parts of Jammu are without electricity. It is expected that some kind of exemptions would be given.

HON. CHAIRPERSON (SHRIMATI RAMA DEVI): Please conclude.

SHRI HASNAIN MASOODI (ANANTNAG): When it comes to Jammu and Kashmir, you say, it is our crown, it is the crown of India. Now, you are ringing the bell. Please give me a minute.

HON. CHAIRPERSON: Okay.

SHRI HASNAIN MASOODI (ANANTNAG): There are frequent blockades of national highways, and connectivity between Jammu and Srinagar and other parts of Kashmir is at its worst.

(1550/RP/MM)

People are stranded on national highways for days together without adequate support. So, all these areas need attention. We will continue to demand that the decisions of 5th August should be revoked and the status before 5th August should be restored in Jammu and Kashmir to fulfil the political aspirations of the people. Mere allocations will not be a substitute for fulfilment of political aspirations. These are only some of the areas which I expect will find attention of the Government and, in particular, the attention of the Finance Minister of India.

(ends)

1551 बजे

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज): माननीय सभापति महोदया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बजट पर अपनी बात रखने का मौका दिया। हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं हमारे माननीय मुख्य मंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में देश एवं बिहार राज्य क्रमश: प्रगति के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। देश के लिए पेश किए गए बजट से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह सरकार सबके लिए विकास का काम कर रही है।

महोदया, केन्द्रीय बजट वर्ष 2020-21 में किसानों की आमदनी वर्ष 2022 तक दोगुनी करने का लक्ष्य बहुत ही सराहनीय है। बजट में कुसुम योजना के दायरे में और 20 लाख किसानों को लाने का प्रस्ताव है तथा 15 लाख अतिरिक्त किसानों को उनके बिजली के पंपों को सौर ऊर्जा से चलाने में भी मदद का प्रावधान है। यह एक ग्रामीण विकास की अहम पहल है। ब्लॉक स्तर पर भंडार गृह बनाने के लिए 15 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य है। इससे अनाज भंडारण के क्षेत्र में प्रगति होगी। इस बजट में जीरो बजट प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया गया है। इस बजट में खास बात यह भी है कि जल संकट की समस्या से जूझ रहे देश के 100 जिलों की समस्याएं निपटाने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं।

इस बजट में पशुपालन क्षेत्र में योगदान बढ़ाया गया है। मवेशियों के खुर और मुंह में होने वाली बीमारी ब्रूसिलोसिस तथा बकरियों को होने वाली बीमारी पीपीआर को पूरी तरह से खत्म करने का प्रावधान है। वर्ष 2025 तक देश में दूध प्रोसेसिंग केपेसिटी 53.5 मिलियन मीट्रिक टन से दोगुना करके 108 मिलियन मीट्रिक टन कर दी जाएगी, जो कि बहुत ही सराहनीय है।

महोदया, इस बजट में सरकार ने सभी के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए 69000 करोड़ रुपये दिए हैं जो कि एक महत्वपूर्ण कदम है। जहां अस्पताल नहीं हैं, वहां अस्पताल खोलने का भी प्रावधान है।

मेरा संसदीय क्षेत्र गोपालगंज है। यहां एवं आस-पास के जिलों में कोई भी बड़ा अस्पताल नहीं है। लोग बड़े शहरों से इलाज के लिए बाहर जाते हैं। इनमें से कई रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। मैं इस सदन के माध्यम से यह आग्रह करूंगा कि गोपालगंज में एक मेडिकल कॉलेज देने का प्रावधान है, उसके काम को अनुमोदित किया जाए।

महोदया, जैसा कि हम जानते हैं कि अभियान “टीबी हारेगा, देश जीतेगा” की शुरुआत की गयी है। इसके ज़रिए वर्ष 2025 तक टीबी को पूरी तरह से समाप्त करने का प्रावधान है। यह भी एक सराहनीय पहल है कि देश के सभी जिलों में 2000 किस्म की दवाइयां एवं 300 सर्जिकल उपकरण उपलब्ध कराने वाले जन औषधि केन्द्रों का विस्तार होगा। यह भी सराहनीय है कि पोषण के लिए 35,600 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। यह पहल 10 करोड़ से अधिक परिवारों की पोषणात्मक कंडिशन को अपलोड करने के लिए 6 लाख से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्ट फोन दिए गए हैं। इन बदलावों का पैमाना अभूतपूर्व है।

महोदया, बजट वर्ष 2020-21 में स्वच्छ भारत मिशन के कुल 12300 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इससे सभी घरों के लिए स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता पर विशेष बल दिया गया है। साथ ही साथ जल जीवन अभियान के लिए 3.60 लाख करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। आज हमारे माननीय मुख्य मंत्री श्री नीतीश कुमार जी की पहल से "जल जीवन एवं हरियाली" प्रोग्राम बिहार में काफी प्रगति पर है, जिसे अगले तीन वर्षों में पूरा कर लेना है। इसके तहत करीब 24 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य है, जिसमें से 19 करोड पेड़ लगाए जा चुके हैं और केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित राशि के साथ-साथ 24524 करोड़ रुपये का प्रावधान इसकी सफलता के लिए राज्य सरकार द्वारा भी किया गया है। आज लगभग हर घर को नल के द्वारा जल मिल रहा है। हर गांव को स्वच्छ पानी मिल रहा है। हर घर को बिजली मिल रही है। वर्षा जल का संचय हो रहा है। सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र के लिए 99300 करोड़ रुपये एवं कौशल विकास के लिए 3000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो सराहनीय है।

(1555/SJN/RCP)

महोदया, पूरे भारतवर्ष को जोड़ने वाली एवं सेवा देने वाली भारतीय रेल के जो प्रावधान किए गए हैं, वह देश एवं आम लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि 100 दिनों के भीतर 550 स्टेशनों में वाई-फाई, 27,000 किलोमीटर रेल लाइनों का विद्युतीकरण, रेलवे की जमीन पर सोलर पावर क्षमता स्थापित करना इत्यादि सराहनीय कदम हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज से कोई भी ट्रेन लंबी दूरी या महानगरों के लिए नहीं है। मैं इस सदन के माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि गोपालगंज से विभिन्न महानगरों के लिए ट्रेन चलाई जाए, ताकि हमारे क्षेत्र के लोगों को रेल की सुविधाएं मिल सकें।

महोदया, मैं इसके साथ ही इस बहुमुखी बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

(इति)

1556 बजे

श्रीमती सुनीता दुग्गल (सिरसा) : आदरणीय सभापति महोदया, मुझे आपने बजट 2020-21 पर बोलने का समय दिया है, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने इस दशक के पहले यूनियन बजट को इस सदन में जिस तरह से माइक्रो लेवल पर प्रस्तुत किया है, उसमें उन्होंने सभी देशवासियों को यह बताने और समझाने की कोशिश की है कि यह बजट आम आदमी, गरीबों, किसानों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और सभी लोगों के लिए है। इसीलिए, उन्होंने इसको तीन थीम्स में डिवाइड किया है। जैसा कि पहले अर्थशास्त्र में भी उसको इसी तरह से तीन भागों में वर्णित किया जाता था। एस्पिरेशनल इंडिया, इकोनॉमिक डेवलेपमेंट फार ऑल एंड केयरिंग सोसायटी। ये जो तीन थीम्स हैं, इनका जो सार है, ईज ऑफ लिविंग और ईज़ ऑफ डूइंग। एक आम इंसान की जिन्दगी को किस तरह और ज्यादा से ज्यादा से आसान बनाया जा सके, इस बजट में इस बात की कोशिश की गई है।

आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का लक्ष्य 5 ट्रिलियन डालर की इकोनॉमी को हासिल करना है। मुझे लगता है कि यह लक्ष्य केवल प्रधान मंत्री जी का या केवल वित्त मंत्री जी का नहीं है। सरकार जो है, वह आपको सहूलियतें दे सकती है, आपको सुविधाएं दे सकती हैं, लेकिन उस लक्ष्य को हासिल करना हम सबकी जिम्मेवारी है। मुझे लगता है कि हम लोग इसको इस तरह से पूरा कर पाएंगे -

न संघर्ष न तकलीफें, फिर क्या मजा है जीने में,
तूफान भी रुक जाएगा, जब लक्ष्य रहेगा सीने में।

हमारा 5 ट्रिलियन डालर का जो लक्ष्य है, यह हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम इसको किस तरह से पूरा करते हैं। एस्पिरेशनल इंडिया के तहत एग्रीकल्चर, इर्रिगेशन, रुरल डेपलेपमेंट, जो 16 एक्शन पाइंट्स हैं, आदरणीय वित्त मंत्री जी ने इसमें दिए हैं। मैं यह कहना चाहूंगी कि पहली बार किसान, जो हमारा अन्नदाता है, उसके बारे में सोचा गया है। वर्ष 2014 से पहले केवल और केवल 27,000 करोड़ रुपयों का बजट किसानों के लिए जाता था। लेकिन इस बजट के अंदर अब की बार 2.83 लाख करोड़ रुपयों का जो बजट है, वह एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एलोकेट किया गया है। इसमें 1.60 लाख करोड़ रुपये इर्रिगेशन और एग्रीकल्चर के लिए हैं और 1.23 लाख करोड़ रुपये रुरल डेवलेपमेंट के लिए हैं। मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट के तहत किसान अपनी जमीन का सही तरीके से कैसे उपयोग कर सके, उसमें इस बात का ध्यान रखा गया है।

आदरणीय सभापति महोदया, फसल बीमा योजना के तहत किसानों ने सिर्फ 13 लाख करोड़ रुपयों का प्रीमियम दिया है और उसके बदले में हमारे किसान भाइयों को 56 लाख करोड़ रुपयों का बीमा मिला है। प्रधान मंत्री किसान निधि योजना के तहत 45,000 करोड़ रुपया सीधे किसानों के खाते में गए हैं। कांग्रेस की सरकार में क्या होता था? उनको दो या ढाई रुपये का चेक मिलता था। मैं सिरसा लोक सभा क्षेत्र से आती हूं, वह कृषि प्रधान एरिया है।

सभापति जी, वहां पर किसान हैरान होते हैं कि हमारे खातों में सीधे पैसा आ रहा है। उनको इस बात का यकीन नहीं होता है। आदरणीय प्रधान मंत्री किसान निधि योजना के तहत उनके खातों में 45,000 करोड़ रुपये सीधे गए हैं। पहली बार किसानों के लिए इस तरह का बजट आया है। मैं हमारी वित्त मंत्री जी को इस बात के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। 'उठाती है, जो खतरा हर कदम पर डूब जाने का', एक बहुत बड़ा खतरा है।

(1600/GG/SMN)

यह ठीक है हमारी इकॉनोमी को बहुत अच्छा करने के लिए आप बिज़नस के लिए बहुत लगाते हैं, किसान की तरफ कोई नहीं देखता है। लेकिन हमारी वित्त मंत्री जी ने यह किया है कि –

" उठाती है जो खतरा हर कदम पर डूब जाने का,
वही कोशिश समुंदर में खजाना ढूंढ लेती है।"

इसीलिए मुझे लगता है कि पांच ट्रिलियन डॉलर की उम्मीद को हम पूरा करेंगे।

सभापति जी, मैं यह कहना चाहती हूँ कि चाहे हम बात करें 20 लाख किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए, 15 लाख किसानों को ग्रिड कनेक्टिड पंप्स देने के लिए सरकार अपनी तरफ से पूरी सहायता करेगी। सोलर पॉवर जनरेट कर के वे इसको ग्रिड में बेच भी सकते हैं। उससे भी आमदनी हो सकती है। क्योंकि जब तक हम किसान का ध्यान नहीं रखेंगे, वह हमारा अन्नदाता है। कल ही हमारे गुरु रविदास जी का जन्मदिन था, उनकी जयंती थी और गुरु रविदास जी ने कहा है कि

" ऐसा चाहूं राज मैं, मिले सभी को अन्न।
छोटे-बड़े सब सम बसें, रविदास रहें प्रसन्न। "

जब तक हमारे किसानों का ख्याल नहीं रखा जाएगा, जब तक इनको मेनस्ट्रीम के अंदर नहीं लाया जाएगा, तब तक मुझे नहीं लगता है कि हमारा भारतवर्ष तरक्की कर पाएगा। यह हिम्मत हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री और हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने दिखाई है। मैं यह कहना चाहूंगी कि सैल्फ-हैल्प ग्रुप – सभापति जी, पिछले दिनों हमारे फतेहाबाद जिले में गीता जयंती हुई। आप हैरान होंगी कि सैल्फ-हैल्प ग्रुप के तहत वहां पर महिलाओं ने इतना स्वादिष्ट भोजन परोसा, इतने अच्छे सैल्फ-हैल्प ग्रुप वहां पर बने हैं, उनके तहत जो वहां पर सरकारी दफ्तर हैं, वहां वे टिफिन सर्विस प्रोवाइड करती हैं। आप हैरान होंगी कि वह खाना इतना स्वादिष्ट था। उसके साथ-साथ उनको आय का साधन मिल रहा है। मैंने बहुत देर तक उनके साथ समय बिताया। मैं यह कहना चाहूंगी कि इसीलिए हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने 58 लाख सैल्फ-हैल्प ग्रुप्स को पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठाने का काम अबकी बार इस बजट में किया है। हमारे सैल्फ-हैल्प ग्रुप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।

महोदया, पिछले दिनों मुझे क्लाइमेट पार्लियामेंट के तहत आबू-धाबी जाने का मौका मिला था। आप हैरान होंगी कि वहां पर उन लोगों ने प्रकृति को भी हिला कर रख दिया है। पहली बार दुबई में इतनी रिकॉर्ड बारिश हुई कि वे हिल गए। उनको इतनी बारिश की आदत नहीं थी। वे लोग रिन्युएबल एनर्जी की तरफ इतनी जबरदस्त तरीके से लगे हैं। वहां पर 48 हजार गीगावॉट की एनर्जी उन्होंने स्टोर कर ली है और आगे भी वे इस तरह से लगे हुए हैं तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि प्रधान मंत्री जी की कोशिश है कि किसान बैरन लैंड पर भी खेती कर सके। हमारे सिरसा में भी बहुत बैरन लैंड है। वहां पर वे सोलर प्लांट लगाएं और उसके तहत वे सोलर एनर्जी जनरेट करें। उससे खुद भी लाभ पाएं और जो उनके पास स्टोरेज होता है, तो उसको वे सरकार को बेच कर आमदनी का साधन भी बना सकते हैं। मैं यह कहना चाहूंगी कि इसी तरह से सरकार की तरफ से 100 वॉटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट्स को चिह्नित किया गया है और उन पर पूरा ध्यान हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री का है। वे बार-बार कहते हैं कि हमारा ध्यान माइक्रो इरिगेशन की तरफ होना चाहिए। अभी पिछले दिनों विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम था। उसमें प्रधान मंत्री जी ने बताया कि एक बच्चा बहुत कमजोर है तो आप क्या करेंगे? उस बच्चे को

सवेरे, दोपहर और शाम तीन टाइम दूध में मेवा डाल कर उस बच्चे को नहला दीजिए, क्या वह बच्चा ताकतवर हो जाएगा? नहीं होगा। उसकी बजाय अगर आप उसको सौ-सौ ग्राम दूध दो टाइम पिला देंगे तो वह ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने माइक्रो इरिगेशन की तरफ ध्यान दिया कि हमारे किसान भाई जो माइक्रो इरिगेशन की तरफ चलेंगे और 100 वॉटर स्ट्रेस्ड जिलों को उन्होंने चिह्नित किया है कि वहां पर उनको हर तरह से सरकार की तरफ से लाभ दिया जाएगा। धीरे-धीरे हम लोग कैमिकल फर्टीलाइजर्स को छोड़ कर अपनी एग्रीकल्चर को ऐसे प्रोत्साहित करें ताकि वे संपन्न हो सकें।

1604 बजे (श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी पीठासीन हुए)

सभापति महोदया, आप हैरान होंगी कि भटिंडा में, कांग्रेस की सदस्य परनीत जी अभी यहां पर नहीं हैं, भटिंडा से एक ट्रेन चलती है, जिसको कैंसर ट्रेन बोला जाता है। कारण क्या है कि वहां पर इतना ज्यादा यूरिया इस्तेमाल होता है, वहां पर इतना ज्यादा कैमिकल फर्टिलाइजर यूज़ होता है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग कैंसर से पीड़ित हैं। हमारी सरकार की कोशिश है कि वहां पर जैविक खाद को प्रोत्साहित किया जाए।

(1605/KN/MMN)

वेलनैस, वाटर एंड सेनिटेशन, इसके बारे में भी अगर हम बात करें, सरकार ने 69,000 करोड़ रुपये इसके लिए एलोकेट किए हैं। हेल्थ सेक्टर के लिए 69,000 करोड़ रुपये ओवरऑल हेल्थ सेक्टर के लिए हमारी सरकार ने इसके लिए दिए हैं। इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहूँगी, अगर मैं अपनी कॉन्स्टीट्यूएंसी की बात करूँ, प्रधान मंत्री नेशनल रिलीफ फंड से लाखों रुपये वहाँ पर जो पीड़ित लोग हैं, उनको मिल चुके हैं।

मैं जल जीवन मिशन की बात करूँ, एजुकेशन की बात करूँ तो 99,300 करोड़ रुपये एजुकेशन के लिए दिए गए हैं। इसके साथ-साथ इनफ्रास्ट्रक्चर में आप देखें कि पाँच नई स्मार्ट सिटीज़ बनाने की सरकार की कोशिश है। इनफ्रास्ट्रक्चर में 103 लाख करोड़ रुपये, ताकि हमारा जो यूथ है, उनको पावर मिले और 6500 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, जो कि 31 दिसम्बर, 2019 को लॉन्च किए गए हैं। इनफ्रास्ट्रक्चर में इतना ज्यादा पैसा सरकार ने लगाया है, ताकि रोज़गार मुहैया करवाए जा सकें।

आज के न्यूजपेपर्स मैं पढ़ कर आई, तो मैंने देखा कि मुम्बई में ट्रैनक्यूलिटी, एक ऐसा रूम बनाया गया है कि जो मोटरमैन है, वे वहाँ पर बैठ कर थोड़ा आराम कर सकें। क्योंकि अभी बात कर रहे थे कि वहाँ पर उनको काफी परेशानी रहती है और बहुत से माननीय सदस्य बता रहे थे कि वहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है। मोटरमैन को कोई दिक्कत न हो, उनके लिए ऐसा सुंदर एक रूम बनाया गया, वहाँ पर वे आराम कर सकें। इस तरह की योजना हमारी सरकार की है, ताकि किसी को कोई दिक्कत न आए।

इसके साथ-साथ मैं कहना चाहूँगी कि हमारी सरकार की यह कोशिश है कि हम वेलनैस सेंटर बना रहे हैं। मैंने खुद कई वेलनैस सेंटर्स के उद्घाटन किए हैं। We do not always need advice. Sometimes, all we need is a hand to hold, an ear to listen, and a heart to understand.

HON. CHAIRPERSON (SHRI P.V. MIDHUN REDDY): Please conclude.

श्रीमती सुनीता दुग्गल (सिरसा): इस तरह की सोच हमारी सरकार की है और इसी के तहत मैं आगे कहना चाहूँगी कि केयरिंग सोसायटी के तहत वीमेन, चाइल्ड, इन सब के मामले में हमारी आदरणीय वित्त मंत्री जी ने पिछले बजट में कहा था कि 'नारी तू नारायणी' और आप हैरान होंगे कि वह करके दिखाया। अब की बार हमारी बेटियां 94.3 परसेंट हायर एजुकेशन में...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Please conclude.

श्रीमती सुनीता दुग्गल (सिरसा): आपने 15 मिनट का समय दिया है। 94.3 परसेंट हायर एजुकेशन में, 59 परसेंट एलिमेंट्री एजुकेशन में, हमारी बेटियाँ आगे बढ़ रही हैं तो मुझे लगता है कि जिस तरह का ध्यान हमारी बेटियाँ का रखा गया है, वह इससे पहले आज तक कभी नहीं रखा गया। पाँच आर्केलॉजिकल साइट्स जो हैं, उनके लिए अब की बार पैसा एलोकेट किया गया है।

HON. CHAIRPERSON: Please conclude. The time allotted is 10 minutes only.

श्रीमती सुनीता दुग्गल (सिरसा): हमारी हरियाणा में राखीगढ़ी एक जगह आती है, तो मैं उसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ।

अगर हम इनकम टैक्स की बात करें, क्योंकि मैं खुद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पहले थी, उसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया है कि किस तरह से पहले सिर्फ चार स्लैब्स थे। अब की बार सेवन स्लैब्स कर लिए हैं। लेकिन मैं अनुराग जी, मंत्री जी को कहना चाहूँगी, हम यह चाहते हैं कि ढाई लाख से 5 लाख, अगर उसमें वह टैक्स 'निल' कर दें, तो बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि-

"हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले
बहुत निकले मेरे अरमां, लेकिन फिर भी कम निकले।"

मुझे लगता है कि अगर थोड़ी सी इसमें और रिबेट कर देंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहूँगी कि कारपोरेट टैक्स 3 परसेंट हमारी सरकार ने किया है।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: You please conclude. Now, Shri Gajanan Kirtikar.

श्रीमती सुनीता दुग्गल (सिरसा): लास्ट में, विवाद से विश्वास। देखिए, यह लास्ट है। विवाद से विश्वास, इसलिए मैं कोई विवाद नहीं चाहती। एक मिनट दीजिए।

लास्ट बजट में सब का विश्वास स्कीम इन-डायरेक्ट टैक्सेस में आई थी, जिसमें एक लाख 89 हजार केसेस सॉल्व हुए थे। अब की बार 4 लाख 83 हजार केसेस डायरेक्ट टैक्सेस में एपीलेट में पैंडिंग हैं। सरकार की तरफ से योजना है कि 31 मार्च, 2020 तक कोई इंट्रेस्ट नहीं लगेगा, कोई पैनल्टी नहीं लगेगी। सिर्फ टैक्स के बेसिस पर अगर करना चाहते हैं तो सॉल्व करवा सकते हैं।

अंत में, मैं यही कहना चाहूँगी-

"सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामया:,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दु:ख भाग्भवेत्।"

(इति)

1604 बजे

श्री गजानन कीर्तिकर (मुम्बई उत्तर पश्चिम): आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। इस बजट में देश के आम आदमी को लाभ देने वाली आसान कर प्रणाली का अमल किया। बैंक एफडी पर 5 लाख का बीमा संरक्षण दिया गया। शिक्षा के लिए 99 हजार 300 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा। कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान रखा। कृषि क्षेत्र के लिए 16 सूत्रीय कार्यक्रम का ऐलान किया। इसका मैं स्वागत करता हूँ।

(1610/CS/VR)

लेकिन इस बजट में सम्पूर्णतया महाराष्ट्र राज्य को अनदेखा किया गया है। महाराष्ट्र से केन्द्र को टैक्स का सबसे बड़ा हिस्सा जाता है, इसके बावजूद भी महाराष्ट्र को बजट में नजरअंदाज करना दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। अनुराग जी, ऐसा मैं बोलता हूँ।

मुंबई में रेलवे यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए व मुंबई रेल विकास कारपोरेशन की माँग के अनुसार गोरेगांव से बोरीवली हार्बर लाइन विस्तारीकरण के लिए 846 करोड़ रुपये, रेलवे स्थानकों के विकास हेतु 942 करोड़ रुपये, बोरीवली से विरार पांचवीं और छठी पटरी डालने के लिए 2, 241 करोड़ रुपये तथा मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट की तीसरी परियोजना के लिए करीबन 50 हजार करोड़ रुपये की निधि केन्द्र से तत्काल मंजूर और रिलीज की जानी चाहिए। मैं यहाँ यह माँग करता हूँ।

महोदय, मैन्ग्रोव्स के संरक्षण हेतु केन्द्र से राज्यों को निधि दी जाती है, परन्तु विगत तीनों बजट में मैन्ग्रोव्स संरक्षण हेतु महाराष्ट्र की झोली खाली रखी है। महाराष्ट्र का 720 किलोमीटर तक का समुद्री किनारा है। इसे देखते हुए मैन्ग्रोव्स वनस्पति संरक्षण के लिए 300 करोड़ रुपये की निधि केन्द्र से महाराष्ट्र को दी जाए।

एक तरफ मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की घोषणा, तो दूसरी ओर बजट में मुंबई उपनगरीय रेलवे नेटवर्क, पश्चिम और मध्य रेल मार्गो के विकास का उल्लेख मात्र नहीं है, यह एक तरह से महाराष्ट्र के साथ सौतेला व्यवहार इस बजट में हमें देखना पड़ता है।

गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय वित्त केन्द्र को मजबूत किया गया है और सही मायने में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की ओर संपूर्णता दुर्लक्ष की गई, इस पर मैं निषेध व्यक्त करता हूँ।

प्रतिष्ठित स्थल के रूप में महाराष्ट्र के एक भी स्थल का नाम नहीं है। आदिवासी बहुल एरिया के बावजूद महाराष्ट्र में आदिवासी संग्रहालय नहीं हैं।

महाराष्ट्र के विविध भागों में बीते जुलाई/अगस्त, 2019 में हुई अतिवृष्टि व बाढ़ से भारी आर्थिक हानि के साथ ही जीवित हानि हुई है। बाढ़ पीड़ितों की सहायता हेतु केन्द्र से आवश्यक 7288.05 करोड़ रुपये की माँग अगस्त 2019 में महाराष्ट्र सरकार ने की है, जिसको शीघ्र मंजूर कर रिलीज करना जरूरी है।

देश में करीब 39 लाख मछुआरे समुद्र के किनारे रहते हैं। केन्द्र सरकार से उनको मकान बनाने हेतु 75 हजार रुपये का अनुदान दिया जाता है, जो कि अत्यधिक कम है। कम से कम 3 लाख

रुपये प्रति मछुआरों को मकान के लिए देना चाहिए। उसके सिवाय उनके लिए 7 लाख रुपये के बीमे का प्रावधान करना चाहिए। मैं ऐसी माँग करता हूँ।

बजट में पर्यटन विकास के लिए 2 हजार 500 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है, परन्तु महाराष्ट्र में ही इतना बड़ा पर्यटन क्षेत्र है, जो आज तक दुर्लक्षित ही होता आ रहा है।

स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कांदिवली, मुंबई में है। यह अच्छा काम करने वाली अथॉरिटी है। कांदिवली, मुंबई के परिसर में पीने के पानी के लिए सेफ्टी टैंक तक की सुविधा नहीं है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुंबई प्रशिक्षण कार्यालय के सर्वांगीण विकास के लिए पिछले दो वर्षों में 9 करोड़ 1 लाख 5 हजार रुपये का प्रस्ताव सादर किया था, उसकी मंजूरी नहीं मिली है। मैं इसकी माँग करता हूँ।

यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के सर्वेक्षण के अनुसार देश के 374 जिले शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। इसमें महाराष्ट्र के बुलढाणा, गढ़चिरौली, हिंगोली, जालना, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिले शामिल हैं। केन्द्र सरकार से महाराष्ट्र का शैक्षणिक दर्जा बढ़ाने हेतु कम से कम 500 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर होनी चाहिए।

महाराष्ट्र की कुल 21 नदियों के पुर्नजीवन करने का रुपये 3 हजार 810 करोड़ 66 लाख का प्रस्ताव नीति आयोग के सामने पेश किया गया है। इस पर तत्काल निर्णय होना चाहिए।

बजट में एक तरफ एजुकेशन के ऊपर 99 हजार 300 करोड़ रुपये की घोषणा की है, परन्तु महाराष्ट्र के आश्रम स्कूलों में पढ़ने वाले 2 लाख 19 हजार बच्चों के लिए सस्ती दरों पर मिल रहा अनाज केन्द्र सरकार ने अगस्त, 2019 से बंद कर दिया है।

वर्तमान में देश की विकास दर मात्र 4.5 परसेंट है।

(1615/RV/SAN)

देश में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या बनी है। 22 लाख से अधिक सरकारी पद खाली हैं। इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, परन्तु इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है। देश का सुशिक्षित बेरोजगार ठगा-सा महसूस कर रहा है।

महोदय, पार्टी की तरफ से मैं अकेला बोलने वाला हूं। मैंने 15 मिनट बोला है। आप इस पर जरा ध्यान दीजिए। मेरी पार्टी के कोई और सांसद इस पर बोलने वाले नहीं हैं।

महोदय, सन् 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की घोषणा इस बजट मे की गई है। ऐसी ही घोषणा सन् 2014 के बजट में भी की गई थी, परन्तु पहले जैसे थे, वैसे ही अभी भी है। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। वास्तव में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए देश की वृद्धि दर 11 प्रतिशत होनी चाहिए, परन्तु प्रत्यक्ष में यह केवल दो से तीन प्रतिशत है। वर्तमान विकास दर की गति को देखते हुए केन्द्र सरकार की यह घोषणा अव्यावहारिक-सी लगती है।

वर्तमान बजट में नए पाँच शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की गई है, परन्तु पिछले बजट के दौरान की गई 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा का क्या हुआ? पहली घोषणा को पूरा न करते हुए दूसरी घोषणा करना काल्पनिक-सा लगता है। यह बजट वास्तविकता से काफी दूर है।

एल.आई.सी. और आई.डी.बी.आई. की हिस्सेदारी बेच देना, एयर इंडिया और रेलवे का संभावित निजीकरण भी चिंताजनक बात है।

देश को 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था वाला देश बनाना केवल सपना-सा लगता है। आज की स्थिति को देखते हुए यह हासिल करने की क्षमता दिखाई नहीं देती है।

जी.एस.टी. के जरिये लोगों की क्रय शक्ति कम हुई, श्रमिकों को परेशानी हुई, जिससे छोटे उद्योगों पर असर हुआ।

HON. CHAIRPERSON (SHRI P.V. MIDHUN REDDY): Kindly conclude now. Already one hon. Member, Shri Arvind Sawant, has spoken from your Party who had taken 22 minutes though your Party has got 15 minutes.

श्री गजानन कीर्तिकर (मुम्बई उत्तर पश्चिम): कई व्यवसाय बंद करने पड़े, जबकि रोजगार पैदा करने वाले उद्योगों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है, लेकिन बजट में ऐसी कोई भी ठोस घोषणा नहीं है।

'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' का केवल नारा ही है। कागजों पर योजना ही बनाई गई है। हर दिन देश की बेटी बलात्कार का शिकार हो रही है। वह भरे चौराहे पर जलाई जा रही है और आरोपी खुले आम घुमते हैं, सजा से बचते हैं, उनको बचाया जा रहा है। बजट में इसके बारे में भी प्रावधान होने चाहिए।

आखिर में, वर्तमान बजट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि महाराष्ट्र के लिए कुछ भी ठोस प्रावधान नहीं है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि इसमें शीघ्र ही सुधार करें।

जय हिन्द। जय महाराष्ट्र।

(इति)

*श्री राजेश नारणभाई चूड़ासमा (जूनागढ़):

---

*Laid on the Table

***डॉ. भारतीबेन डी. श्याल (भावनगर)**:

---

*Laid on the Table

1618 hours

ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA): Hon. Chairperson, Sir, before entering into the discussion on Budget, I want to go through some relevant issues related to Kerala. Hon. Prime Minister, while replying in the Rajya Sabha on Motion of Thanks to the President's Address, distorted the answer given by the Kerala Chief Minister, Comrade Pinarayi Vijayan in relation to a question raised in the State Assembly regarding the intruders of SDPI in the anti-CAA protest. Yes, I am proudly saying that we, the Left Parties, are always keeping an alert on any invaders against the uncompromising struggle against CAA, NPR and NRC. That is why, Comrade Pinarayi Vijayan took a solid stand against SDPI.

Sir, I cannot understand why the Prime Minister is so silent about the firm stand taken by Comrade Pinarayi Vijayan against the implementation of NRC and CAA. Hon. Modiji, have you noticed that the Kerala Assembly has passed a Resolution demanding scrapping of CAA, under the leadership of Comrade Pinarayi Vijayan? Have you seen the human chain created by the Kerala people for a length of 620 kilometres? After passing of the Resolution by Kerala Assembly against the CAA, many other States also came forward against the CAA. Hon. Prime Minister would not have spread some words of his speech for playing his communal agenda.

At the same time, why did you become so silent when the Chief Minister of Kerala talked about the discrimination done by the Central Government in connection with Kerala flood relief package? Kerala faced two massive floods in 2016 and 2017. You gave Rs. 2,000 crore only for flood relief and rebuilding process, and did not give a single paisa for the second flood, despite the fact that the Central Government agencies and the specialist team of the United Nations had estimated that the total loss of the State was around Rs. 31,500 crore. Whenever Kerala asks for help, you turn your face and portray our State as if it is an enemy country.

In connection with the development of the national highways in the State, Kerala has to bear the brunt of half of the total cost of land.

(1620/RBN/MY)

Related to the project of laying an additional railway track, Kerala has to bear half the cost for acquisition of land. In fact, you are taking revenge against the people of Kerala by creating new criteria when it comes to the

implementation of the Centrally sponsored developmental schemes. You are continuously denying the GST share of the State. Besides, you decreased Kerala's tax share. You are always adopting a reluctant approach whenever Kerala demands things such as semi-high speed corridor, Angamali-Sabari rail project, separate AIIMs for the State, Central Ayurvedic Research Centre, more investment in the public sector undertakings, rehabilitation package for Gulf Malayalis, etc.

Despite all these injustices, Kerala has achieved a GDP growth rate of 7.5 per cent and managed to achieve the top most position in the school education in the NITI Aayog's Report. Kerala is also at the top of the MNREGA Scheme as well. Moreover, NITI Aayog's Report also identified that Kerala's health sector stands far ahead with the rest of the country in terms of quality and assurance. The State's Health Department was highly successful in preventing contagious diseases caused by Nipah virus and novel Coronavirus treatment.

At the outset, the General Budget is great in length, but hopeless in content. The speech lasted for two hours and 45 minutes, using poems of great renowned poets. I am thanking the Poets Shri Deena Nath Nadeem of Kashmir, Avvaiyar, Thiruvalluvan and Kalidasan for having extended the speech of our Finance Minister for so much of time.

But the senior leader Dr. Farooq Abdullah from Kashmir could not hear your voice when the poem of Kashmiri Poet Deena Nath Nadeem was read out in this House. Your Government had detained and put him under house arrest for the last five months. Through this Budget you could not address burning issues of this country and people.

We want to know what is the rank of our country in many global indices. According to Poverty Index of the United Nations, India is ranked at 103rd position. This implies that the number of poor has increased considerably. Our Finance Minister and our Prime Minister have not uttered a single word in this regard. Shri Krishnamurthy Subramanyam's Thalinomics is not enough to address this Index.

According to the United Nations' Human Development Index, India is ranked at 135th position. Earlier, in 2014, it was ranked at 130th position.

According to IMF review, our GDP growth was eight per cent during 2015, but now the GDP growth rate is under 4.8 per cent. This is because of insecurity and unemployment.

In the Happiness Index, according to the United Nations Sustainable Development Solution network, India is ranked at 140th position. It was ranked 117th position during 2015. As far as Security Index of Women is concerned, India is now ranked at 133rd position.

In the Budget, did you say any word about Make in India? Now, you are telling 'Assemble in India'. Who will come and invest in a country where you have divided communal voice?

You have hung a board before the Parliament saying that all PSUs are for sale, including the LIC with attractive offers and huge reduction. Anybody can purchase these PSUs for a small price. You should remember the history of our country. East India Company came to India for trade. But at last our country came under its rule.

(ends)

***श्री पी.पी.चौधरी (पाली):**

---

*Laid on the Table

***डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़):**

---

*Laid on the Table

1624 बजे

श्री बृजभूषण शरण सिंह (कैसरगंज): सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अगर हमें वर्तमान को समझना है तो हमें बीते हुए कल को भी देखना होगा। वर्ष 2009 से वर्ष 2014 के बीच, जब यूपीए की सरकार थी तो उनके बजट में पांच साल के अंदर जो वृद्धि हुई थी, वह 6,44,549 करोड़ रुपये की टोटल वृद्धि हुई थी। वर्ष 2014 से वर्ष 2020 के बीच मोदी जी की सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है और उसमें जो वृद्धि हुई है, वह 12,42,338 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।

(1625/CP/SM)

महोदय, मैं अपने भाषण की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करना चाहता हूं। समुद्र के किनारे एक सज्जन टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बच्चा, समुद्र की लहर के साथ जब कुछ मछलियां बहकर किनारे आती थीं, तो वह उन्हें पलटकर समुद्र के अंदर फेंक देता था। उन सज्जन से रहा नहीं गया और उन्होंने पूछा कि जब एक लहर के साथ लाखों मछलियां बहकर किनारे पर आती हैं, तो आप ये दो-चार मछलियों को जो फेंक देते हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? उस बच्चे ने यह उत्तर दिया कि न आपको फर्क पड़ता है, न मुझे फर्क पड़ता है, लेकिन जिन मछलियों को मेरे कारण दोबारा जीवन मिल जाता है, उन्हें फर्क जरूर पड़ता है।

मान्यवर, मैं थोड़ा सा पीछे चलना चाहता हूं। सन् 1991 में मैं पहली बार सांसद बना और देश की राजनीति को समझने की कोशिश की। हम देखते हैं कि सन् 1984 में राजीव गांधी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। वर्ष 1984 के वर्ष 1989 में चुनाव हुआ, सरकार बनी, लेकिन किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। वर्ष 1989 के बाद वर्ष 1991 में किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, वर्ष 1991 के बाद वर्ष 1996 में किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, वर्ष 1996 के बाद वर्ष 1998 में किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, वर्ष 1998 के वर्ष 1999 में किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और इसी तरह वर्ष 2014 आया। 2014 के पहले, मैं चाहूंगा कि आप इसको अन्यथा न लें, लेकिन देखें कि देश की स्थिति क्या थी? कुछ बुद्धिजीवी लोग कहते थे कि संविधान में कहीं न कहीं कोई दिक्कत है। कुछ लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि शायद अब इस देश के अंदर किसी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनेगी। चिंता होने लगी थी, लोग राजनीति से निराश हो गए थे, राजनीतिक दलों से निराश थे और इसीलिए किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। वर्ष 2014 में चुनाव हुआ। प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में देश की जनता विश्वास करती है और पूर्ण बहुमत की सरकार 32 सालों के बाद बनती है। यह भी अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन है।

हमारे प्रधान मंत्री जी ने, हमारी सरकार ने देश के सामने जो चुनौती थी, उसको स्वीकार किया और इस भावना के साथ स्वीकार किया –

"है कौन काम ऐसा जग में,
टिक सके आदमी के मग में?
खम ठोक ठेलता है जब नर,
पर्वत के जाते पाँव उखड़,
मानव जब जोर लगाता है,
पत्थर पानी बन जाता है।"

मान्यवर, कुछ लोगों को नहीं दिखाई पड़ता, नहीं समझ में आता और उनको कोई समझा भी नहीं सकता है। जैसे आज सीएए की चर्चा चल रही है, सब कुछ जानते हुए भी समझ में नहीं आता है। किसी ने कहा है कि कोई व्यक्ति सो रहा हो, अगर वह वास्तव में सो रहा हो, तो उसको एक आवाज मारिए, वह जाग जाएगा, लेकिन अगर वह जान-बूझकर सो रहा हो, तो आप चाहे जितनी आवाज मारिए, वह नहीं जागेगा। यही हाल आज हमारे इन मित्रों का हो गया है। ये सब जानते हुए जान-बूझकर सोने का काम कर रहे हैं।

(1630/NK/SPR)

इसलिए मैंने कहा कि इनको नहीं फर्क पड़ता है तो न पड़े, लेकिन आयुष्मान योजना के कारण दस करोड़ परिवारों की जिन्दगी में फर्क पड़ा है, आप इस बात को मान लीजिए, आपको फर्क पड़े या न पड़े। किसान सम्मान निधि द्वारा बारह करोड़ परिवारों को फर्क पड़ा है। मैं इसमें एक छोटी सी बात जोड़ना चाहता हूं। यह मात्र सवाल छह हजार रुपये का नहीं है। मैं गांव से आता हूं और देखता हूं कि पहले छोटे किसान जिनके पास एक बीघा जमीन है या उससे भी छोटा खेत है, उनके खेत में कुछ पैदा नहीं होता है। जिनको जमीन की जरूरत थी, शहर के किनारे बड़े लोग पहुंचते थे और समझाते थे कि इसमें कुछ पैदा नहीं होता है, मुझको दे दो, दो लाख की जमीन है चार लाख रुपये रेट लगा दिए, चार लाख की जमीन है तो आठ लाख रुपये रेट लगा दिए। गरीब आदमी सोचता है कि इसमें कुछ पैदा नहीं होता है तो इस जमीन को रखकर क्या करूं।

मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस योजना के कारण गरीब की जमीन बिकनी बंद हो गयी क्योंकि गरीब यह जान गया कि यह जमीन रहेगी तभी हमें इस योजना का लाभ मिलेगा, इसलिए बड़े लोग जमीन बेचने के लिए तैयार हैं लेकिन गरीब आदमी आज की तारीख में जमीन बेचने के लिए तैयार नहीं है। 37 करोड़ लोगों के खाते खोले गए। हो सकता है कि किसी को फर्क न पड़े, लेकिन जिन लोगों का बैंक से रिश्ता बना है उनको फर्क पड़ा है।

इसी लोक सभा के अंदर राजीव गांधी जी प्रधान मंत्री थे। उन्होंने कहा था कि जब मैं एक रुपये भेजता हूं तो पन्द्रह पैसे पहुंचते हैं, उस सच्चाई को उन्होंने स्वीकार किया था। जो हम भेजते हैं वह आम आदमी या जिनके लिए भेजते हैं, उसके पास नहीं पहुंचता है। लेकिन आज डॉयरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत 65 हजार करोड़ रुपये देश के बचे हैं। आज इस बात को सभी स्वीकार करेंगे, कहीं न कहीं उस परंपरा में मंदी आने का काम हुआ है।

आज उज्ज्वला योजना के कारण आपको न फर्क तो न पड़े, लेकिन आठ करोड़ परिवारों की जिन्दगी में फर्क पड़ा है। आज विद्युत के क्षेत्र में यही काम हुआ, मातृत्व वंदना योजना के तहत छह हजार रुपये के कारण भी फर्क पड़ा है।

एक चीज और जिस पर किसी की निगाह ही नहीं जा रही है। पहले हम कोई भी आवेदन करते थे तो हमें एक शपथपत्र बनवाने के लिए कचहरी और तहसील जाना पड़ता था। एक सर्टिफिकेट बनवाने का मतलब पांच सौ या हजार रुपये और कम से कम दो-चार घंटे बेकार हो जाते थे। आज कल्पना कीजिए, इस देश में एक दिन में कितने शपथपत्र बनते थे, एक झटके में उसकी आवश्यकता इस सरकार ने समाप्त कर दी।

इसी प्रकार से हमने 370 और 35 ए समाप्त कर दिए। किसी को फर्क पड़े या न पड़े, लेकिन 1989 में रातों-रात जम्मू-कश्मीर से जिनको भागना पड़ा था, उनको फर्क पड़ा। 42,000 नौजवान जिसकी रक्षा के लिए शहीद हो गए, उनको फर्क पड़ा। इसी तरह से राम जन्मभूमि प्रकरण है। यह मामला इतने दिनों से लंबित था। हमारे विरोधी पूछते थे कि बीजेपी के लोग नारा लगाते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। किसी को फर्क पड़ा हो या न पड़ा हो लेकिन जो लोग कई सौ वर्षों से उम्मीद लगा कर बैठे थे, आज उनको फर्क पड़ा है।

(1635/SK/UB)

अब मैं तीन तलाक की बात कहूंगा, कुछ लोग नाराज़ हो जाएंगे। 1984 में राजीव जी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। यहां कानून मंत्री बैठे हैं, शाह बानो को न्याय मिला था, एक महिला को न्याय मिला था। हम जिस लोक सभा क्षेत्र से सांसद हैं, आरिफ मोहम्मद खान, जो आज गवर्नर हैं, कांग्रेस के अच्छे नेताओं में थे। राजीव जी के बड़े करीबी थे, कांग्रेस परिवार के बहुत करीबी थे, लेकिन एक बार सच्चाई उनकी जुबान पर आ गई तो उन्हें कांग्रेस से बाहर का रास्ता देखना पड़ा। आज ऐसी महिलाओं को भी हमने न्याय देने का काम किया है।

राहुल जी, एक टेप चल रहा था- राफेल, राफेल, राफेल। हमें लगता है थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट ने टेप बैन कर दी, अब वह टेप बंद हो गई। अब एक टेप चल रहा है- बेरोजगारी, बेरोजगारी, बेरोजगारी। मैं बड़े खुले मन से पूछना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि यह एक दिन की समस्या नहीं है। हम भी मानते हैं कि बेरोजगारी समस्या है।

“दर्द कौन लेगा यह बताया जाए,
लोग सब चले गए बाज़ार उठाया जाए।
अकेले मेरा गुनाह नहीं है साहब,
अंधेरा बोला - अदालत में रोशनी को भी बुलाया जाए।”

यह एक दिन की समस्या नहीं है। आधे-अधूरे मन से कोई लड़ाई नहीं जीत सकता है। हमारे सामने विपक्ष बैठा है, उसके सामने एक ही दिक्कत है कि वह आधे-अधूरे मन से हर काम करने की कोशिश करता है। इन्होंने हर काम को करने की कोशिश की और इसीलिए समस्याओं का एक अंबार लग गया। माननीय प्रधान मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि इस समस्या का समाधान भी हम ही करेंगे। मुझे विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी को विश्वास है कि हम आपका यह टेप भी जल्द बंद करेंगे, यह टेप भी ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। यह समस्या हमारी देन नहीं है।

मैं वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

(इति)

***श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा (बारदौली):**

---

*Laid on the Table

***श्रीमती रंजनबेन भट्ट (वडोदरा):**

---

*Laid on the Table

*SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAG):

*Laid on the Table

***श्री राजू बिष्ट (दार्जिलिंग):**

---

*Laid on the Table

1638 hours

SHRI LAVU SRI KRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Sir, at the outset, please allow me congratulate the hon. Finance Minister for bringing this Budget. Continued focus on important sectors like sanitation, education, water, and manufacturing is welcome. It will continue to keep India on track to achieving its Sustainable Development Goals. We will be eagerly looking forward to the successful implementation of the Sustainable Development Goals. Further, providing the Viability Gap Funding for the setting up of effective warehouses, hospitals and medical colleges and other reformative proposals will encourage private investments and open up the sectors even more.

Sir, there are certain concerns that I am sure we all would have in our minds. First and foremost among them is how the revenue deficit will be addressed. The revenue deficit not only hurts the Central Government but also the States. The devolution of taxes to States is equally hurt.

(1640/KMR/MK)

Adding to this, the 15th Finance Commission has also reduced the devolution to Andhra Pradesh from 4.3 per cent to 4.11 per cent. This has resulted in a loss of nearly Rs.1500 crore.

The estimated fiscal deficit this year is 3.8 per cent of GDP. However, if the extra budgetary borrowings amounting to Rs.1,72,700 crore are included in the calculation, the fiscal deficit would increase to 4.6 per cent of GDP. Similarly, if the extra budgetary expenditure for 2020-21 is taken into account, the estimated fiscal deficit would increase from 3.5 per cent to 4.4 per cent of GDP. I would ask the hon. Finance Minister to clarify whether this has been accounted for or not.

The government has pinned its hope on disinvestment to arrange for funds. In the financial year 2019-2020 the government has targeted a disinvestment of Rs.1,05,000 crore. Instead it was able to achieve a disinvestment of only Rs.65,000 crore. In the coming year the government has planned to raise Rs.1,20,000 crore through disinvestment. We are eagerly waiting with high hopes that the Government meets its target this time without actually letting go out of its prized jewels.

While it is appreciable that the bank deposit insurance has been increased to Rs.5 lakh from the previous Rs.1 lakh level, there are many issues to be

sorted. The repo rate has been reduced to 5.15%, the lowest in nearly a decade. Even this has failed to translate into increased number of loans to industries, especially the MSME sector.

GST collection between April and November fell short by 40 per cent and it is likely to be lower than the growth target of 25 per cent. The slow pace at which GST dues are transferred to the States has been troubling, especially so in the case of Andhra Pradesh which already had a deficit revenue due to the bifurcation. A mechanism needs to be developed for speedy disbursement of the revenue to the States.

Coming to agriculture, the PMKISAN scheme which had promised so much has delivered little. The budget allocation has remained constant. Until now only Rs.43,000 crore have been distributed out of Rs.75,000 crore. The actual distribution of funds has been extremely low as compared to the budget allocation. The delay in reaching out to farmers hurts their livelihood. We need to find the reason for these delayed payments and the lack of full disbursement of the funds. We are coming up with the new scheme PMKUSUM wherein we are going to give solar panels to the farmers. If we cannot find the farmers to actually disburse funds under PM-KISAN, it will be very difficult to actually deliver the PM-KUSUM scheme.

I would like to bring to your attention that under the YSR Rythu Bharosa scheme that is being implemented in Andhra Pradesh, 46 lakh farmers are being provided an input assistance of almost Rs.13,500 annually. The government must consider increasing the budget allocation under PM-KISAN for Andhra Pradesh which has successfully extended this scheme to the actual tiller of the land.

The budget allocation for PM Fasal Bima Yojana has increased only marginally by Rs.1700 crore to Rs.15,700 crore. Considering the farm distress prevailing in India the government should hike the budget allocation for the scheme.

The primary concern of successive Governments has been to double farmers' income. For this to happen, there must be a comprehensive plan to tackle the issue. The main source of their supplementary income is livestock and dairy. This income too is under threat and diminishing every day. The lack of adequate fodder has resulted in lower milk production and malnutrition amongst

the livestock. We are neither importing nor producing sufficient fodder. According to a Cornell University study, a deficit of 65 per cent of green fodder and 25 per cent of dry fodder is expected for Indian livestock by 2025.

Sir, the revised estimate for the MGNREGA programme has already overshot the 2019-20 budget estimate by Rs.11,000 crore. Yet, the allocation for the programme for the coming financial year is pegged at Rs.61,500 crore. I would hope and also recommend that in light of the slowdown of the economy and the current high rate of employment, the Government would consider increasing allocation for the programme. It should also ensure that pending dues are cleared with immediate effect and funding for the same is ensured on time.

It was good to see that the Government will create warehousing and build a seamless national cold supply chain for perishables through PPP arrangement. However, the details of the same are not clear. I would really appreciate if the details are spelt out clearly.

The Government has increased the allocation for education to Rs.99,300 crore. However, at this rate, the six per cent GDP allocation by 2022 seems distant. The New Education Policy has sought to introduce many new ideas and innovations. It is apparent that to properly implement the New Education Policy the budgetary allocation would have to be at least three per cent of the GDP.
(1645/SNT/YSH)

The hon. Finance Minister in her speech had also stated that she would like to have world-class institutions. However, building is easy but staffing them with quality faculty and providing state-of-the-art resources requires adequate long-term funding.

I would also like to take this opportunity to bring to your attention that the Andhra Pradesh Government has initiated two schemes. One is Amma Vodi and the other one is Nadu-Nedu. Through Amma Vodi scheme, we are giving Rs.15,000 to the mother every January. We have reached out to 43 lakh mothers. Through Nadu-Nedu programme, we are refurbishing almost 15,715 schools. These are shared goals and cooperation between the Centre and the State which would ensure the success of these schemes while, at the same time, reducing the fiscal burden on Andhra Pradesh. I would hope the Finance Minister will try to support us.

I would also like to urge the Government to keep its promise of setting up of 12 national institutes in Andhra Pradesh. Currently, a paltry sum of Rs.2,209 crore have been sanctioned for only 7 institutes and out of this, only Rs.1,020 crore have been released. I hope the Government will release funds according to what was mandated.

Along with education, healthcare too needs to be given due importance. The Government has increased the budget allocation by just 5 per cent. The Government had a target to allot 2.5 per cent of GDP to healthcare by 2025. But in light of the 15 per cent healthcare inflation in India, this target would be difficult to achieve without higher allocation. It is good that the Government seeks to empanel 20,000 hospitals in the aspirational districts. But I hope that it will also address the dues already owed to empanelled hospitals amounting to nearly Rs.1,600 crore.

While we are in the midst of this slowdown, the Government must lend a hand to struggling industries. The overall credit gap in the MSME sector is estimated to be Rs.20-25 lakh crore; and this is despite the fact that the sector accounts for 111 million jobs, over 40 per cent of exports, and 28 per cent of the GDP. The NBFCs need to be bolstered to ensure that adequate credit is available in the market, especially for the manufacturing sector.

The hon. Finance Minister pointed out that India imports significant quantity of technical textiles worth 16 billion dollars every year. In a bid to reverse this, the Government has allocated nearly Rs.1,500 crore for the mission. Such initiatives are very much welcome. However, I would also urge the Government to consider its allocation to the Ministry of Textiles. The Ministry has been allotted a meagre sum of Rs.3,500 crore. In fact, the allocation for the Ministry of Textiles has fallen by Rs.1,300 crore. Weavers and textile industries across the country are facing stiff competition of cheap imported products from Bangladesh and Vietnam. The Textile industry in India is the second largest employer in the country.

The hon. Minster of Textiles is also here. She is very much aware of it. I hope, she will take it up with the Finance Ministry. It is a 100 billion dollar industry, which provides employment to 45 million people directly and 60 million people indirectly in India. I do not have to give these details. But I hope the Textile Ministry will be taking care of it. I hope it will be taken care of and extra

infusion will be done because it is very personal to me. We have the highest number of textile mills, ginning mills, and spinning mills in my district. I hope the hon. Minister will take care of them. I hope things will be sorted out.

The hon. Finance Minister has allocated Rs.103 lakh crore for the National Infrastructure Pipeline and has covered 6,500 projects under it. This is an ambitious and commendable target that will spur desperately required growth and employment. The past record of this Government has been admirable, however, there are still many projects that have been delayed. For example, Bharatmala Project, Sagarmala Project, River-Linking Projects and construction of inland waterways have all been delayed. It would also benefit the Members of this House if the hon. Minister would elaborate in greater detail how the Government intends to implement the PPP model and provide viability gap funding.

I would also urge the hon. Minister to include the projects from Andhra Pradesh which require Government funding within the National Infrastructure Pipeline. Many of these projects were promised under the AP Reorganization Act but still have not been delivered by the Central Government.

Firstly, the Polavaram Project is the lifeline of a successful Andhra Pradesh. It has also been declared as a national project. The Government of Andhra Pradesh has incurred an expenditure of Rs.11,860 crore on the Polavaram National Project as of 4th January, 2020. Furthermore, the Revised Cost Estimate of Rs.55,548 crore was cleared by the Technical Advisory Committee of Ministry of Water Resources. However, it is still pending approval with the Revised Cost Committee.

(1650/GM/RPS)

Secondly, the Government of Andhra Pradesh has taken an ambitious plan to create a water grid to supply 45 litres of clean drinking water to each household. I hope this will be taken care of. Another assurance in the Andhra Pradesh Re-organisation Act was establishing integrated steel plant in YSR district. We have been promised four smart cities at Visakhapatnam, Tirupati, Amaravati and Kakinada with a budget of Rs. 9,000 crore. I hope the fund will be released soon. I also hope that the Central Government will push for the growth of Visakhapatnam-Chennai corridor and also release funds for the crucial Amaravati-Anantapur Expressway.

I would like to reiterate that the Government of India in its wisdom bifurcated Andhra Pradesh and the former Prime Minister had assured us that the special category status would be given to the residual State. The overall financial position of Andhra Pradesh is very precarious and the only way to bring the State out of financial crisis and attract investment and provide a level-playing field is by granting the special category status to it. Therefore, I would request the hon. Prime Minister to grant Andhra Pradesh special category status and I request the hon. finance Minister to provide adequate funding to Andhra Pradesh. I hope these concerns will be addressed. With this, I wish the Government all the best for its endeavour and I hope it will take into consideration these concerns. Thank you.

(ends)

1652 hours

SHRI NAMA NAGESWARA RAO (KHAMMAM): Hon. Chairperson, thank you for giving me the opportunity to speak on the Union Budget 2020-21. The Budget was presented in the backdrop of the overall slowdown in the Indian economy. The GDP growth in 2019-20 was expected to be below five per cent. It is lowest in last 12 years. In such a backdrop, it was expected that the Union Budget 2020-21 would propose bold steps to address the decline in investment and announce a series of structural reforms to revive the growth of the country and address the problem of rising unemployment in the country. The Budget failed to provide any kind of stimulus required for reviving the economy. The target of disinvestment is Rs. 2.10 lakh crore. It is very ambitious. In the last year, the actual figure has been only Rs. 18,000 crore till today. So, I would advise the Government to keep the targets realistic and achievable. A lot has been talked about agriculture and allied sector but the allocation is only Rs. 1.55 lakh crore. Doubling the farmers' income by 2020 is one of the key targets for this Government. But it requires a minimum growth rate of 15 per cent per annum for the farmers' real income for next three years; then only we will be able to achieve this target. अभी हमारे तेलंगाना में केसीआर साहब फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए प्रति एकड़ 10,000 रुपये रायतु बन्धु योजना में दे रहे हैं। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट भी 6,000 रुपये दे रही है। हम डिमाण्ड कर रहे हैं कि जिस तरह से तेलंगाना में किसी के पास पांच एकड़ जमीन आने से उसके पास 50,000 रुपये आ जाते हैं, इधर पांच एकड़ के लिए 1000 या 1100 रुपये आते हैं, इसलिए किसानों की डबल इनकम एचीव करने के लिए हमें प्रति किसान को प्रति एकड़ 10,000 रुपये देने चाहिए। इसके साथ सरकार का टारगेट है कि 2024 तक इकोनोमी को पांच ट्रिलियन यूएस डॉलर तक ले जाना है। For achieving this, continuously you need a growth rate of 16 per cent. But the present growth rate is below 5 per cent. How will it be achieved? There is no proper roadmap in the Budget. In the Budget paper, it was mentioned that ours is the 5th largest economy. पूरे हाउस को यह बात सुननी चाहिए, यह बात मैं इस लिए बोल रहा हूं, क्योंकि यूएसए की इकोनोमी 21.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, लेकिन उनकी पॉपुलेशन केवल 30 करोड़ है। China's economy is worth USD 14.1 trillion and their population is 130 crore. जापान का 5.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर, जर्मनी का 3.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर and the present Indian economy is only worth USD 2.9 trillion whereas our population is 130 crore. Even Japan and Germany are almost the size of the State of Maharashtra.

(1655/IND/RK)

Coming to the realistic figure, India's GDP per capita हमारी रैंकिंग वर्ल्ड में 145 नम्बर पर है। हम यहां अपने को पांचवें नम्बर पर बता रहे हैं। हमारी रैंकिंग 185 देशों में से 145 नम्बर पर है। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हम कितना पीछे हैं। मैं यह डेटा आईएमएफ के बता रहा हूं।

Coming to the recommendations of the 15th Finance Commission, the tax devolution to States has been reduced from the existing 42 per cent of the divisible tax pool to 41 per cent. Never before in the history of the Finance Commission the tax share to the States has been reduced. For the first time it has been done on the plea of giving this one per cent share to Jammu and Kashmir. The Central Government should give

money from its own pocket. Why do you want to give the other State Governments' share to Jammu and Kashmir? We do not mind giving one per cent share to Jammu and Kashmir but that should be given from the Central Government pool and not from the State Government pool.

With regard to the 15th Finance Commission, from the beginning we have been demanding not to take 2011 census as the base year of computation. We had been requesting to take into consideration 1971 census as the developing States are being affected because of this formulation. डेवलपिंग राज्यों पर इस कारण प्रभाव पड़ रहा है। इसके बारे में दोबारा सोचें। इसकी वजह से तेलंगाना को 2383 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है, इसको जरूर कम्पनसेट करें। We would once again request the hon. Prime Minister, as also the hon. Finance Minister, to intervene and do justice to the State of Telangana and other Southern States. All Southern States have been affected due to the 15th Finance Commission.

The GST Act clearly says that the States which register less than 14 per cent growth rate due to GST implementation, would be compensated for five years. उसके लिए कम्पनसेट नहीं कर रहे हैं और तेलंगाना 5 हजार करोड़ रुपये की पेमेंट बाकी है। प्रश्न काल में मंत्री जी ने कहा था कि दो साल में दे देंगे।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI ANURAG SINGH THAKUR): Not two years, two instalments.

SHRI NAMA NAGESWARA RAO (KHAMMAM): Thank you, Mr. Minister.

In this Budget the Government of India has announced Jal Jeevan Mission to provide piped water to the entire country, mainly to the rural India. The Government of Telangana took up this Mission as Mission Bhagiratha, which has almost been completed. NITI Aayog's representatives have seen it. नीति आयोग ने वित्त मंत्री को 31 मई, 2016 को पत्र लिखा कि भगीरथ मिशन को 19205 करोड़ रुपये दिए जाएं। They have recommended Rs.19,205 crore for this Mission Bhagiratha in 2016. In the last four years, we have approached all the levels. We would again request for it because ours is a progressive State. पहली बार गरीब लोगों को पानी देने जा रहे हैं, इसलिए नीति आयोग की अनुशंसा पर पैसा दिया जाना चाहिए। इसी तरह से मिशन 'काकतीय' है। हमने विलेज टैंक्स को डेवलप किया है। उसके लिए भी नीति आयोग ने 5 हजार करोड़ रुपये रिकमेंड किए थे। दोनों स्कीम्स के लिए 24205 करोड़ रुपये नीति आयोग ने तेलंगाना के लिए रिकमेंड किए हैं। इसके लिए यह पैसा हमें जरूर मिलना चाहिए।

महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण बात सदन में कहना चाहता हूं। आंध्र प्रदेश रीआर्गेनाइज एक्ट के बारे में इश्यू पेंडिंग है।

(1700/PS/ASA)

For the past fifty-years, the people of Telangana have fought for a separate State of Telangana.

1700 hours (Shri N. K. Premachandran *in the Chair*)

मेरे नेता के.सी.आर. साहब, जब 15वीं लोक सभा चल रही थी, वह हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे, उनको दस दिन हो गए थे, उनकी लाइफ क्रिटिकल सिचुएशन में थी। उस लाइफ एंड डैथ की पोजीशन में इसी सदन की बीएसी मीटिंग जब चल रही थी तो मैं अकेला तेलंगाना से बीएसी मीटिंग में था। हमने यह डिमांड की थी कि हमारा नेता हंगर स्ट्राइक पर बैठा है और अब दस दिन हो गये हैं। हमको हाउस में इस पर डिसकस करना है। उधर से लाल कृष्ण आडवाणी साहब ने उस प्रपोजल पर अपनी सहमति दी और तत्कालीन अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार जी और स्वर्गीय सुषमा स्वराज मैडम ने भी कह दिया था कि आज हाउस में इस बारे में डिसकस करना चाहिए। मैं हाउस का रिकॉर्ड बता रहा हूं कि उस मामले पर हुई चर्चा में 24 लोगों ने डिसकशन में भाग लिया था। दिनांक 9 दिसम्बर 2009 से हम लोग तेलंगाना के लिए फाइट कर रहे थे। फाइट करने के बाद फाइनली 18-02-2014 में हम लोगों को तेलंगाना राज्य मिला है। सब लोगों ने यह भी कहा था कि तेलंगाना के लिए अपोजीशन नहीं है जबकि स्वर्गीय सुषमा स्वराज मैडम बोल रही थीं कि आप अगर मैडम सोनिया जी...(व्यवधान) हम सब लोग हाउस में सपोर्ट करेंगे। ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON (SHRI N. K. PREMACHANDRAN): Please conclude.

... (*Interruptions*)

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): चेयरमैन साहब, फाइनली हम लोगों के बिल लाने के बाद सर्वसम्मति से पूरे हाउस ने बिल को पास कर दिया। हरेक बिल पास करने के समय लॉबीज क्लिअर की जाती हैं, डोर्स क्लोज हो जाते हैं और डोर्स क्लोज हो जाने के बाद बिल पास होते हैं। मगर आजकल बहुत लोग बोल रहे हैं कि उस बिल को पास करने के लिए डोर्स क्लोज किए गए।...(व्यवधान) सर, अभी तो मैं पहली बार बोल रहा हूं।

सर, 6 साल से हम लोगों ने तेलंगाना में काफी कुछ विकास के काम किए हैं। अभी सेन्ट्रल गवर्नमेंट को भी 6 साल हो गये हैं और हमारी सरकार को भी 6 साल हो गये हैं। हमने काफी कुछ विकास के काम पिछले 6 साल में किए हैं लेकिन अभी काफी मुद्दे पेंडिंग हैं। लिस्ट पढ़ने में बहुत समय लगेगा। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि जितने भी पेंडिंग इश्यूज हैं, उनको सरकार देखे और हमारी सरकार को आगे बढ़ने के अवसर दे।

HON. CHAIRPERSON: Thank you. Additional papers need not be given. Are your demands over?

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): सर, तेलंगाना स्टेट के काफी पेंडिंग इश्यूज हैं। इसके साथ-साथ सिंगल विंडो क्लिअरेंस के लिए जिस तरह से एक्ट लेकर आए हैं, उसकी वजह से हमारे पास काफी इंवेस्टमेंट आ रहा है।...(व्यवधान) अगर हमारे यहां इंडस्ट्री आएगी, हम भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसका जो इंडस्ट्रियल कॉरीडोर है, वारंगल- हैदराबाद, बैंगलूर का जो है, इस तरह से बहुत सारे इश्यूज पेंडिंग हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि रेलवेज और रोड्स के जो पेंडिंग इश्यूज हैं, उनको भी सरकार देखे। अभी माननीय प्रधान मंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही है।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude with the demands.

SHRI NAMA NAGESWARA RAO (KHAMMAM): I am concluding.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude with the demands.

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): सर, जो कंट्री नीड्स हैं, वॉटर की जरूरत सबको है, उसकी रिवर लिंकिंग करनी चाहिए और सेंटर और राज्य साथ-साथ आगे बढ़ें तभी देश का विकास होगा। धन्यवाद।

(इति)

(1705/RC/RAJ)

1705 hours

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Sir, I thank you very much for giving me this opportunity to react on this Budget …(*Interruptions*).

HON. CHAIRPERSON (SHRI N. K. PREMACHANDRAN): Nothing would go on record except the speech of Shri Mohammed Basheer.

…(Interruptions) …(Not recorded)

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Sir, in this Budget discussion, I wish to confine myself only to two subjects. First is the implication of the Budget with regard to Kerala and second is the impact of the Budget on the minorities of India.

Sir, as far as Kerala is concerned, we always have a bitter experience. In the past also it was like that and this year also it is like that with regard to Kerala's share of taxes. In the last year's Budget, it was Rs.16400 crore and this year, it is Rs. 15236.34 crore which means there is a reduction of Rs. 1164.4 crore. That is the position for Kerala. I do not want to say much on this.

The figures relating to the BJP-ruled States are with me. If you critically analyse them for all the places whether it is Uttar Pradesh, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Haryana, Bihar, etc., it is just double. When you are distributing the wealth of the nation, it should be done in a judicious manner. That is what I wish to say in brief. With regard to the Railways also, the same thing is happening.

As regards the Ministry of Minority Affairs, I would like to ask whether it is dead or you are thwarting that. What is happening? The allocation for minorities has been slashed like anything. The allocation for UPSC, SSC and State Public Service Commission coaching has been reduced from Rs.20 crore to Rs.10 crore and the allocation for Free Coaching and Allied Scheme for minorities is reduced from Rs.75 crore to Rs.50 crore. Similarly, the allocation for education and livelihood for minorities has decreased from Rs. 140 crore to Rs.120 crore. The allocation for minority women schemes has also been decreased from Rs.150 crore to Rs.110 crore. This is injustice. Why should you do this kind of injustice to a backward community?

The Sachar Committee said that representation of Muslims in the jobs, especially in the Civil Services is only three per cent. When this naked truth prevails, why should we go with this kind of injustice?

Now let us see the expenditure. I am not giving my own opinion. The Standing Committee on Social Justice presented a report in this regard. The Committee observed that out of the total budgetary allocation of Rs.4700 crore during the year 2018-19, the actual expenditure incurred by the Ministry was only Rs.3085 crore which means there is a decrease there also. The Committee also said that ultimately the money was surrendered. The Committee also said that there has been under-utilisation of funds in most of the important schemes regarding education and skill development. The Committee further said that they are not convinced by routine reasons cited by the Ministry.

What about the current year? The Committee observed that in 2019-20, the expenditure incurred by the Ministry for different schemes has only been 27 per cent till 31.10.2019 and the remaining amount of 73 per cent is to be utilised in the remaining four months. How will it happen? You are reducing allocation everywhere and you are taking the money back also which is surrendered to the Ministry of Finance.

In her Budget Speech, the Minister said that for every scheme, strict guidelines are given to States to follow the same. It will result in strict procedures and things like that. I do not want to go into the details of that.

(1710/SNB/VB)

Sir, I have two pages of that Committee Report in my hand. What happened to the twenty-seven schemes? A sum of Rs. 851 crore has been surrendered. What is this Ministry doing? The hon. Prime Minister and the hon. Finance Minister keep on saying a lot of things about the minorities, but what is happening in reality? The allocations have either been reduced or surrendered.

Sir, as far as the Budget speech of the hon. Finance Minister is concerned, she said that at the turn of the century every member of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes community who seeks a better life and for every women wishing to stand up and get counted and for every individual from the minority community, the Budget aims to have their hopes and aspirations addressed. Is it a fact? The Government is digging a graveyard for the minorities in this country. The Government has to realise this fact. The Government is spinning

some colourful stories. But what is happening in this country? A sense of insecurity is developing amongst the minorities. Freedom is being curtailed. The hon. Finance Minister towards the end of her speech was quoting a few poems. These kinds of poems are all good for beautification of a speech but as far as India is concerned, the most relevant poem for this country at this juncture is Rabindranath Tagore's freedom song and I would like to quote a few lines of that. I quote:

"Where the mind is without fear
and the head is held high,
where knowledge is free.
Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls.
Where words come out from the depth of truth,
where tireless striving stretches its arms toward perfection.
Where the clear stream of reason has not lost its way
into the dreary desert sand of dead habit.
Where the mind is led forward by thee
into ever widening thought and action.
In to that heaven of freedom, my father,
LET MY COUNTRY AWAKE!"

These were the words of Rabindranath Tagore. We are for freedom. But for this Government what is it? Let this country work hard to make the dreams of Rabindranath Tagore a reality. We have to work towards that.

Sir, with these few words, I conclude.

Thank you.

(ends)

1713 बजे

श्री नन्दकुमार सिंह चौहान (खण्डवा): माननीय सभापति जी, मैं आज वर्ष 2020-21 के बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री जी ने जो बजट देश के सामने प्रस्तुत किया है, यह बजट पुकार-पुकारकर देश को आश्वस्त कर रहा है कि प्रधान मंत्री जी का जो लक्ष्य है, भारत की अर्थव्यवस्था को पाँच ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचाने का, यह बजट उसका फाउंडेशन है।

इस बजट ने देश की जनता पर कराधान का कोई बोझ न डालते हुए, देश के विकास के लिए नये आयाम को छूने का प्रयत्न किया है। आलोचना तो कोई भी कर सकता है, लेकिन पूरा देश जानता है कि मोदी जी के नेतृत्व में सभी सेक्टर्स के लिए, गरीबों, किसानों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए, एससी और एसटी के लिए, उनके आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए जिस प्रकार ईमानदारी से प्रयत्न किए गए हैं, वे जमीन पर दिखाई देने लगे हैं।

(1715/PC/RU)

माननीय सभापति महोदय, प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत, इस सदन में बैठे हुए लोगों में से कौन इन्कार कर सकता है कि वे करोड़ों गरीब, जो कच्ची झोपड़ियों में रहते थे, बारिश का पानी उनके सिर पर टपकता था, रात बैठे-बैठे बीतती थी। आज ग्रामीण सैक्टर हो या शहरी सैक्टर हो, प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत करोड़ों गरीबों को घर बनाकर इस सरकार ने दिए और उनके घर के सपने को पूरा किया।

सभापति महोदय, मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं। मैं जिस गांव में रहता हूं, वहां मोदी जी के प्रधान मंत्री बनने से पहले मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ी से खाना बनता था। जब सुबह होती थी तो पूरा गांव धुआंमय हो जाता था। आज उज्ज्वला योजना के तहत दस करोड़ गरीबों को गैस कनैक्शन देने के बाद गांव का वह परिदृश्य बदला है। खाना पकता है, लेकिन गांव में धुंआ दिखाई नहीं देता। …(व्यवधान) आपको तो कभी प्रेशर नहीं दिखेगा। …(व्यवधान) जो आलोचना के लिए ही बैठे हैं, मैं उनसे क्या कहूं? …(व्यवधान) देखिए, देश सुधारने के लिए कुछ कड़े फैसले भी करने पड़ते हैं। देशहित में ऐसे फैसले हमारे प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हुए।

सभापति महोदय, देश का कराधान, जीएसटी जैसी टैक्स-क्रांति हमारे देश में हुई। शुरूआत में व्यापारी लोग इसका विरोध करते थे, लेकिन अब सब जगह से जीएसटी का वैलकम होने लगा है, यह कराधान की वह पद्धति है। आज यहां बैठे हुए लोग हर अच्छे काम का भी विरोध करते हैं। इससे बड़ा दिल दुखता है। मैं यह कहना चाहूंगा कि अच्छे काम करने में कभी-कभी कड़े निर्णय भी करने पड़ते हैं। वह कर के, देशहित में, देश को आगे बढ़ाने के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए, सामाजिक जीवन में बदलाव लाने के लिए जो-जो देश के लिए जरूरी है, वह मोदी सरकार ने किया है और भविष्य में भी हम करेंगे।

सभापति महोदय, अच्छे को अच्छा कहना भी हमें सीखना पड़ेगा। मैं कहना चाहूंगा कि अच्छे काम करने में कभी-कभी कुछ कठिनाइयां आती हैं, लेकिन ये लोग हमेशा हर बात की आलोचना करते हैं। ये लोग अपने गिरेबां में तो झांककर देखें। मैं इनके लिए दो पंक्तियां कहना चाहूंगा –

चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी
हम पर इल्ज़ाम है चमन से बेवफाई का।
रौंद डाला जिन्होंने चमन को पैरों तले
वो दावा कर रहे हैं चमन की रहनुमाई का?

माननीय सभापति महोदय, देश बदल रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के बाद अब देश में बाहर से आने वाले लोग, चाहे वह एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, वहां की सफाई को देखकर देश की प्रशंसा करते हैं कि वास्तव में देश बदलाव की ओर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ये अच्छे काम हैं। स्वच्छ भारत मिशन दिखने में छोटा मिशन दिखता है, लेकिन सामाजिक जीवन में इससे कितना बड़ा बदलाव आया है। सफाई की तरफ देश बढ़ने के कारण लाखों लोग, जो बीमारियों से मर जाते थे, उनका जीवन नरेन्द्र मोदी की सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के लिए बजट में प्रावधान कर के, उसको मिशन मोड में लाकर देश के सामने एक परिवर्तन लाया है।

माननीय सभापति महोदय, महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, उनके उत्थान के लिए इस बजट में पोषण आहार पर 35 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। महिलाओं के लिए जो विशिष्ट कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उनके लिए 28,600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस देश में बहुत बड़ी संख्या में हमारे एससी, एसटी वर्ग के लोग रहते हैं। वे गरीबी में जीते आ रहे हैं।
(1720/SPS/NKL)

उनका वास्तविक आर्थिक उद्धार हो, इसके लिए प्रयत्न उतने नहीं हुए हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि प्रयत्न नहीं किए गए हैं, लेकिन जिस मात्रा में प्रयत्न होने चाहिए थे, नहीं हुए हैं। मोदी जी के प्रधान मंत्री बनने के बाद हर बजट में एस.सी./एस.टी. वर्ग के उत्थान के लिए पर्याप्त मात्रा में राशि रखी जा रही है। मैं सदन के माध्यम से देश को बताना चाहूंगा कि एस.सी. और ओ.बी.सी. के कल्याण के लिए इसी वर्ष के बजट में 85 हजार करोड़ रुपये का प्रोविजन हुआ है। वहीं पर दूर-दराज के जंगलों में जो हमारे एस.टी. वर्ग के आदिवासी भाई रहते हैं, उनकी भी चिंता मोदी सरकार ने इस बजट में की है। उन ट्राइब्स के लिए 55 हजार करोड़ रुपये का प्रोविजन किया गया है।

महोदय, आज यह सब किया जा रहा है। नॉर्थ-ईस्ट में जो बदलाव आया है, नॉर्थ-ईस्ट में जो शांति का माहौल बना है, उससे देश के प्रति एक विश्वास जागा है। देश की सरकार के प्रति जो एक आशा और विश्वास नॉर्थ-ईस्ट में पैदा हुआ है, वह पिछले 70 सालों में नहीं हुआ, लेकिन मोदी जी के कार्यकाल में नॉर्थ-ईस्ट हमारी मुख्य धारा में जुड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए 34 हजार करोड़ रुपये का प्रोविजन किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, हमारा देश कृषि प्रधान देश होने के नाते इस बजट में किसानों के लिए 1 लाख 42 हजार करोड़ रुपये का प्रोविजन किया गया है तथा सिंचाई के लिए अलग से प्रोविजन किया गया है। इरीगेशन बढ़ेगा तो कृषि का उत्पादन बढ़ेगा। हर स्तर पर देश को ऊंचा उठाने के लिए, किसान और गांव के मजदूरों के उत्थान के लिए 20 लाख सोलर पम्प इसी वर्ष देने का टारगेट इस बजट में हुआ है। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला है। विश्व में सोलर के लिए जो काम हमारे भारत में होने लगा है, उसकी प्रशंसा पूरी दुनिया कर रही है।

मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि आज प्रधान मंत्री कृषि सम्मान निधि दी जा रही है। मैं वित्त मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उसके कारण गरीब और छोटे किसान देश भर में प्रसन्न हैं, लेकिन अभी भी वह राशि प्रॉपर तरीके से हमारे मध्य प्रदेश में नहीं पहुंच रही है। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो किसानों की सूचियां भारत सरकार को आनी चाहिए, उनके प्रॉपर तरीके से न आने के कारण उससे किसान वंचित रह रहे हैं। मैं भारत सरकार से एक आग्रह और करूंगा। मैं कृषि मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि कृषि सम्मान निधि की राशि हमारे मध्य प्रदेश में वन पट्टाधारक आदिवासियों में एक को भी नहीं मिल रही है। कृषि सम्मान निधि भारत सरकार द्वारा पूरे देश के किसानों के लिए लागू की गई योजना है। मध्य प्रदेश के ट्राइबल्स हैं, वनवासी हैं, उनको जो वन के पट्टे खेती करने के लिए दिए गए हैं, जो सरकार के द्वारा दिए गए पट्टे हैं, उन्हीं पर वे खेती कर रहे हैं, तो उनको भी कृषि सम्मान निधि के अंतर्गत जो 6-6 हजार रुपये एक-एक किसान को मिलते हैं, वह वनाधिकार के पट्टेधारक किसानों को भी मिलने चाहिए। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

(इति)

1724 hours

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Thank you, hon. Chairperson Sir, for giving me the opportunity to speak on the General Budget, 2020-21.

Let me begin by making a statement. After the creation of the new State of Andhra Pradesh in 2014, eight Budgets have been put in by the Central Government. But even today, Sir, the people of Andhra Pradesh are very much disappointed, even after the presentation of eight Budgets, because they have been constantly looking with a lot of hope, after every Budget, that the implementation of the AP Reorganisation Act will be done in a proper way but no sufficient allocation has been done, not even in this Budget or the previous seven Budgets that have been put in by the Central Government.

(1725/KSP/MM)

Most importantly, let me remind the House about the Andhra Pradesh Re-Organisation Act and how it came into effect in 2014. Some of the Members, who were present during that time, are still here and they would remember that at that point of time, when the new State of Telangana was created, there were certain issues which cropped up between both the States. So, all the Members of Parliament thought about as to what would be the best way to go forward and they created the State of Telangana. Whatever issues were there between Telangana and Andhra Pradesh, they were all listed and proper assurances and provisions were made so that they would come out of all the problems that arose due to bifurcation and that is how the Andhra Pradesh Re-Organisation Act came into effect.

Let that not deceive anyone here right now, because every time we talk about the Andhra Pradesh Re-Organisation Act or the implementation of these provisions, many of them say that it is a State Subject and why we should raise it here in Parliament. But they should all remember that the whole Andhra Pradesh Re-Organisation Act is an Act of Parliament. The responsibility of implementation of the Act lies with the Central Government. If not the Central Government, whose responsibility is it to implement this Act? That is why, we constantly keep talking about the Andhra Pradesh Re-Organisation Act and we

are bound to do that. The previous two speakers from Telangana and Andhra Pradesh also mentioned this Act, because this is very important.

So, I would like to reiterate all the problems that are pending even today in terms of the implementation of the Andhra Pradesh Re-Organisation Act. One of the important issues is giving of Special Category Status to the State of Andhra Pradesh. Before the 2019 Election, during the last five years, we have been relentlessly fighting for the same. You have also seen that we have been fighting inside and outside the House, we have done a lot of protests, we have come out of the NDA, we have demanded strongly for the Special Category Status, we could not achieve it, and the YSRCP has made an election promise to the people of Andhra Pradesh about it, they believed in it, they gave them the mandate, they have got 22 MPs in this House, but they have still not achieved it. The demand is still there for the Special Category Status and now I would like to remind the hon. Members of Parliament from YSCRP also that the people of Andhra Pradesh are very much disappointed with the way they are fighting for the Special Category Status to Andhra Pradesh. So, definitely, the way forward should be decided by the MPs of YSCRP because they made an election promise that they are going to get it.

The other important aspect is the creation of a new railway zone. It is a very important matter which has been constantly demanded by us. Before the 2019 Lok Sabha Election, the hon. Railway Minister Piyush Goyalji came to Visakhapatnam and announced the creation of the new railway zone. He has named it as the South Coast Railway Zone. But how many days have passed since that announcement? Not a single rupee has been allocated for this purpose. So, what will the people think? It is just to make a fool of them that they have made this announcement as an election promise. If there is any integrity in announcing the creation of a new railway zone, definitely there should have been a proper budget allocation for setting up of this railway zone with its headquarters at Visakhapatnam. We strongly demand now also that proper allocation of fund should be made whenever a Minister or the Prime Minister or any representative of the Central Government makes a promise.

Sir, another important demand is regarding the Backward Regions Grant Fund. This was also mentioned in the Andhra Pradesh Re-Organisation Act. Seven districts from Andhra Pradesh namely, Srikakulam, Vizianagaram,

Visakhapatnam, Chittoor, Kurnool, Kadapa and Anantapur were all recognised as backward districts and we have demanded for the rightful funds for the development of these districts. The Central Government has agreed on giving Rs. 50 crore per district for six years. This was the commitment they made. All other districts which are under the Backward Region category across the country are all getting that money. For three years, the Central Government released Rs. 1,050 crore which is Rs. 350 crore per year for the State of Andhra Pradesh and for the next three years, not a single rupee has been given to the State of Andhra Pradesh. I come from one of those backward districts namely Srikakulam. So, I strongly demand on behalf of my people and on the basis of the AP Re-Organisation Act that this Backward Region Grant Fund should be released immediately by the Central Government.

Then, there is a commitment for establishment of many educational institutions like IIM, IIT etc., because all such institutes were left with Hyderabad. We are a separate State right now and not a single institution of national importance is there in the State of Andhra Pradesh. So, a commitment was made for setting up of these institutes. The former Chief Minister of Andhra Pradesh, Chandrababu Naidu Garu distributed these institutions across the State of Andhra Pradesh with the concept of decentralised development.

(1730/KKD/SJN)

He has distributed these institutions across the State of Andhra Pradesh; he has provided all support from the State Government, giving the land, which is to the tune of Rs. 11,600 crore. Now, what is the assurance that the Central Government is giving? In every Budget, you would find only Rs. 5 crore or Rs. 10 crore for these important institutions, which need hundreds of crores for fulfilment. Now, six years have gone by. For four years, students have been studying in some rented campuses without proper facilities. The Central Government should take proper and necessary steps, and allocate sufficient budget for these institutions. Completion of these institutions is also a very important aspect.

Sir, Polavaram Project is a national project. It is the responsibility of the Central Government. They have to finish this project. The State Government is executing it. Funds are also pending. Rs. 11,000 odd crore has been earmarked. Rs. 6,000 odd crore has been released and Rs. 5,000 odd crore has

yet to come. Moreover, the Central Government is not saying about the R&R Package, which is the most important thing. Unless that is cleared, the whole Polavaram cannot happen. So, some statement has to be given regarding the R&R Package also.

Similarly, Sir, about the Vizag-Chennai Industrial Corridor, an announcement was made during the Budget Speech of then then hon. Finance Minister, late Arun Jaitley-ji. But what is the statement now? The Asian Development Bank, which was supposed to implement this, has observed four different nodes, Visakhapatnam, Machilipatnam, Donakonda and Chittoor. The NICDIT, National Industrial Corridor Development and Implementation Trust has approved the nodes also.

HON. CHAIRPERSON (SHRI N. K. PREMACHANDRAN): Please conclude now.

SHRI KINJARAPU RAM MOHAN NAIDU (SRIKAKULAM): Sir, within two minutes, I am concluding my speech.

Shri Piyush Goyal-ji, to one of the questions, had replied that since the Budget is presently…

HON. CHAIARPERSON: Please do not go for any explanation. Kindly conclude by making bullet points.

SHRI KINJARAPU RAM MOHAN NAIDU (SRIKAKULAM): Okay, Sir. I will just conclude.

So, this project is also pending. No proper budget allocation has been made regarding this project.

There are a couple of other things. One is about the NREGA funds. It is a scheme of the Central Government. NREGA funds have been given by the Central Government to the State Government to be given to the contractors, who have done the work under them. It is still pending with the State Government only. After constant persuasion with the Central Government, the Central Government has said that it has to be released, but the State Government has not yet released it. So, as it is a Central scheme, and I would request the Central Government to take up its responsibility.

There is one more point, which, Mr. Chairperson, you would also agree.

The other important point is about the 15th Finance Commission, which definitely, the Central Government has to take into account. The 15th Finance

Commission is doing a lot of injustice to the Southern States including Kerala. If you see the difference between the 14th and 15th Finance Commissions, in terms of devolution of funds, Andhra Pradesh is losing 6.63 per cent. Similarly, Telangana is losing 14.71 per cent. Karnataka is losing 24.7 per cent. Kerala is losing 23.81 per cent. As we are the performing States, we should be incentivised. If we are performing well, if we are doing good on the SDGs, we have to be incentivised and given more funds.

HON. CHAIRPERSON: Now, please conclude.

SHRI KINJARAPU RAM MOHAN NAIDU (SRIKAKULAM): Sir, please give me one minute to conclude.

Sir, if this continues in future also, when there is delimitation of seats and if the Census 2011 is taken into account, we will lose on the Parliamentary seats also. More seats will come from the North of India and less seats will come from the South of India. So, financially, we are losing; and politically also, we are losing the representation. If the Central Government does not take this into account seriously, there would definitely be a rebellion in the Southern States of this country. So, the Central Government has to treat us properly especially in regard to devolution of funds by the 15th Finance Commission. All the Chief Ministers from the Southern States have submitted that these are not the right recommendations. But still the Centre has not yet taken this into account. It may have serious complications in future if it is not addressed now. So, problems concerning the 15th Finance Commission should be addressed.

Lastly, AP Reorganisation Act is the most important issue not just for Andhra but for Telangana also. A lot of commitments were made and assurances given, but they have not moved by even a single inch. No budgetary allocation has been made. For the last five years, we have been asking but the Central Government would say that 10 years time is there to fulfil the commitments. Now, six years have already gone by. If you look at the implementation, 60 per cent should have been done by now, but zero to 10 per cent has been done till now. So, I would request the Central Government to take the issue of implementation of AP Reorganisation Act seriously and give proper attention.

With these words, I conclude. Thank you.

(ends)

1735 hours

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Mr. Chairman, Sir, firstly, I want to know from the Government: Is the Budget exercise meant to mislead the Parliament, and why should we trust this Government?

For example, the Budget Estimates for Gross Tax Revenue, 2019 was Rs. 24.6 lakh crore.

(1735/RP/GG)

In the second Budget presented by the hon. Finance Minister on 1st February, the Revised Estimate for gross tax revenue for the year 2019-20 is Rs. 21.6 lakh crore. There is a huge difference of Rs. 3 lakh crore. I want to know from the Government as to why was this over-estimation done. Who did this? The Parliament is sacrosanct. You cannot mislead the Parliament. It was done to peg the Budget Estimate for the fiscal deficit lower than what a more accurate revenue estimate would have allowed.

HON. CHAIRPERSON (SHRI N. K. PREMACHANDRAN): Anticipation is not misleading the Parliament.

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): No, Sir, it is misleading the Parliament. I will tell you why. Let me corroborate, Sir. You have asked a right question. Mr. Rathin Roy was a Member of the Prime Minister's Economic Advisory Council. He wrote an article. He warned this Government. What we saw was that within a few weeks, he was dropped from the Prime Minister's Economic Advisory Council.

I will give you the second example. Again, in this year's Budget, the Government is trying to hide the fiscal deficit by over-estimating the gross tax revenue for the year 2020-21. It is Rs. 24.2 lakh crore. That is the gross tax revenue. The Budget will see a growth of 12 per cent from 2019-20 to 2020-21. When the Budget estimate for nominal GDP growth for the year 2020-21 is only 10 per cent, how can we have 12 per cent growth?

My third point is that the Government has refused to say about fiscal crisis. I will tell you why. The Budget is seeking Parliament's permission for invoking the escape clause provided under the FRBM Act because right now the fiscal deficit is 3.8 per cent of GDP. For an escape clause to be invoked, an independent council has to be formed. Where is that independent council? Has

the independent council given the advice? No, it has not. What is the roadmap? We do not know that.

My fourth point is that this Government, the Modi Government, is so broke that it is even borrowing money to pay for salaries and pensions for its employees. The Budget speech gives a lot of absolute figures of different sectors but there is no absolute growth. The Finance Minister assumes that we do not know. Take for example the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA). In 2020-21, the allocation dipped to Rs. 61,500 crore against the revised estimate for spending in 2019-20, which was Rs. 71,000 crore. It has a decrease of 13.8 per cent. …(*Interruptions*)

SHRI S.C. UDASI (HAVERI): It is demand-driven.

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, he is taking my time.

HON. CHAIRPERSON: If you are yielding then you are losing your time.

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): No, Sir. He is taking my time. I am not yielding. You can add his time to my time, Sir.

Sir, the allocation for the National Health Mission has been decreased to 5.1 per cent. In the present debate, the Prime Minister spoke so eloquently about infrastructure. Sir, do you know how much has been given to infrastructure? It is Rs. 12,500 crore. The Prime Minister is against the VIP culture but for SPG, the Budget is Rs. 600 crore. For infrastructure, it is Rs. 12500 crore. Moreover, Sir, SPG budget is not audited or covered by C&AG. There is no audit done. What infrastructure will be created by Rs. 12,500 crore? Only the Government can answer this.

As far as the GST is concerned, the Prime Minister has taken the credit for it. If you read paragraph 106, the Finance Minister is saying: “Hereinafter, transfers to the fund would be limited only to collection by way of GST compensation cess." This is the dishonest way of completely ignoring the GST Act. You have to give 14 per cent compensation. An amount of Rs. 1.5 lakh crore have not been given to the States. How will the States be compensated now? They have made budget on that basis. Mr. N.K. Singh, Chairman of the Fifteenth Finance Commission said: “Frequent changes have resulted in a clutter that has made compliance difficult for businesses.” His own Fifteenth Finance Commission said this.

The hon. Minister is sitting here. Look at the way the Budget is created. Sir, Rs. 4000 crore is given to the Ministry of Communications. For what purpose the amount has been given? The Ministry of Communications will give that Rs. 4,000 crore to the Government for GST. It is fantastic. There is a great wisdom in this.

Now, I am coming to the budget for minorities. It is not the question of increasing the budget. What is the Muslim literacy rate? It is the lowest. It is 68.5 per cent. The national literacy rate is 74 per cent. As far as pre-matric and post-matric scholarships are concerned, the Government is giving only Rs. 35 lakh to 60,000 minority students. What is the number of applicants for pre-matric? It is 75 lakh. In the case of post-matric scholarship, it is 18 lakh. Day-in, day-out, I have been demanding that it should be made demand-driven. You gave a commitment that one crore scholarships would be given but you do not do it. You owe only words for minorities but when it comes to actual implementation, it is zero.

(1740/RCP/KN)

That is the example I would like to give. The unit costs of scholarship for minorities have not been increased from 2007-08. The Prime Minister has given pre-matric scholarship. According to inflation, increase the scholarship for admission and tuition fees, for post-matric, to at least Rs.10,000. Do away with the criteria of 50 per cent for scholarship. We do not want that. You want more students because all-India survey says 17.3 lakh Muslims are in higher education. How do you give them? You want to increase their participation.

In Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram, the cumulative unspent balance in 2018-19 is Rs.3092 crore; in 2019-20 it is Rs.4,850 crore. What is this? The National Education Policy says that Muslims are under-represented in education, in higher education and school education.

In August 2019 the Government reduced corporate tax and it is 15 per cent for foreign companies and 22 per cent for Indian companies. So, Indian companies will pay 50 per cent more than the foreigners. These companies have already invested lakhs of crores of rupees in India for several decades. I would also like to know from the hon. Finance Minister whether she is the Finance Minister of India or of foreigners.

I would give another example. Why is there 22 per cent tax only for companies and not for partnerships and small businesses? It is because your hierarchy of cronyism is like this: foreigners first, rich Indian companies second, and small Indian companies last. In Dividend Distribution Tax of 10 per cent, the companies are making the shareholders to pay. What is this?

The hon. Finance Minister in her speech was very vocal in criticising the global trade agreements. Does that mean that the Government of India will refuse a deal with the USA? When Trump comes, will the Finance Minister say that we do not want a trade deal with the US? Will the Minister of External Affairs who is going to Europe on 17th February say that we do not want it?

Sir, an important issue is about the household survey that has been done. It clearly says that 31 per cent of our youth is unemployed. Within that, graduates are 43 per cent. We do not know what is the roadmap for employment. The condition of unemployment is so bad. The NCRB tells us that in 2018, when Modi was the Prime Minister, every day, 36 youths were committing suicide. Why? It is because of lack of employment. What is your roadmap? You do not have a roadmap. That is why I have started by saying that this Budget exercise is meant to mislead the Parliament. Why should we trust all these data? It is because this Government can go back tomorrow. I am pretty much sure that the GDP will not even touch 4.5 per cent this time because there is nothing in this Budget to revive the economy. People are being taken for a ride. That is why I oppose this Budget.

I am reminded – I am concluding – that the way the Finance Minister spoke for two hours and so many minutes, someone cut a joke and said that it reminded about seeing an old movie called 'Sangam'. There are two intervals in that. Maybe the Finance Minister could have given another interval and said it afterwards. There is nothing in the Budget for common man. That is why, I oppose it.

Thank you, Sir.

(ends)

1743 hours

DR. K. JAYAKUMAR (TIRUVALLUR): Hon. Chairman, Sir, at the outset, I appreciate the Finance Minister for liberally quoting the poets from South and North. She started her speech with a quote from Aauvaiyar, the great Saint poet of South. She also quoted the poetry of Pandit Dinanath Koul without any language bias or regional bias. I appreciate her.

I wish to start my presentation here with a couplet from Thiruvalluvar which, I think, will be more apt for this Government considering its past performance:

"Idipparai illa emara mannan
Keduvar ilanum kedum."

The meaning of it is this. A king does not need enemies to destroy him. He himself gets destroyed by his wrong deeds if he has no fearless advisors and ministers to advise him not to do wrong when he engages in such acts.

Keeping myself in such a position, I would like to comment on this Budget. (1745/SMN/CS)

To begin with, the Finance Minister claimed that the economy is strong and inflation is contained. I totally disagree with it. I am thankful to the hon. Minister of State for Finance who is present here. The consumer price index in November, 2019 which was 5.4 shot up to 7.35 per cent just in one month, that is, in December, 2019. About the fiscal deficit, you are supposed to maintain at 3.3 per cent but it has increased to 3.8 per cent. The GDP during the last 11 years is lowest at five per cent. Even now, it is 4.5 per cent and not even five per cent. It started from eight per cent, decreased to seven per cent and further went down to 6.5 per cent and today, in 2019, it is ending up at 4.5 per cent and, therefore, the investment is only one per cent. Only one per cent has increased which is lowest in the last 17 years. Manufacturing is a paltry at two per cent and, therefore, the statement made by the Minister is absolutely false and the figures do not support it.

Coming to the tall claims of the Budget that the economy would be taken to five trillion dollars and the size of the Budget is the fifth largest in the world today, here again, I beg to differ with the Minister that he is not in a position to

reach five trillion dollars. Many economists and many people have spoken earlier than me over here. This is due to largely currency fluctuations and the faulty policies of the Government. I read the World Bank Report on the financial position of this country compared to the other countries. The World Bank, for that matter, any other agency, even IMF has stated that it is the demonetization. The effect and the strong beating given to the economy has not recovered and its effect would still last for few more years and in this situation, the Finance Minister saying that the country would reach five trillion dollars economy is only a mirage and I do not think it is possible to do that.

Another important thing that Dr. Manmohan Singh has mentioned in one of his articles and even came out to give voluntary suggestion to this Government is that this Government lacks social harmony. Social harmony plays a very important and effective role in the economic development of this country. Unless the people are in a harmonious state, cooperate with each other and live without differences, the growth of economy is impossible. As the days pass, the disharmony in the country under this Government is more than what it was when it started and we are witnessing it. Today, the country is divided in two parts and the two forces are fighting against each other. I will come to that later.

Another mention made by the Finance Minister is that the former Finance Minister Mr. Arun Jaitley is the architect of the GST. Here again, I beg to differ. Who has invented the GST system? Who started it? Who designed it? Who wanted to implement it? Who came to this House and asked for an approval? It is the UPA Government, the financial expert Mr. Chidambaram has designed the GST under the able guidance of Dr. Manmohan Singh and the present Government which was in Opposition on that day vehemently opposed it and did not allow it.

When you got the opportunity to implement it, you have implemented it in the most shabby manner. The implementation part of the GST has led down and it has broken the economic growth of this country and there is no second opinion to it and the real architects are Dr. Manmohan Singh and Mr. Chidambaram. At a later part, I pay my best regards and respects to Mr. Arun Jaitley who had piloted this and my best homages to him.

Another point I would like to add here is about the unemployment position. You are supposed to develop employment. I am not going back to your first term where you promised that you would give ten crore jobs or two crore jobs in a year. We pardoned you that you did not achieve it. What has happened to that? (1750/MMN/RV)

Now you are doing things in such a way that it will increase unemployment further. Today, the unemployment position is the highest in the last 45 years. Kindly, gracefully accept that your Government is not in a position to provide employment. I will come to that later. You have no plans to provide employment to solve the unemployment problem.

Another thing is that on the income tax part of it, the hon. Finance Minister has made a statement. The MoS for Finance may also know that the Finance Minister has mentioned faceless appeals. That means, the entire income tax system would go online. Everything would be done online. Aadhaar would be linked. From Aadhaar, you can get PAN card. From PAN card, you can get Aadhaar. Online system has been done for everything. There is no need for interaction with the human beings in running the country. Please put your hands on your heart and tell us who had devised this system. What were all the oppositions raised about when Aadhaar scheme was taken up. Hon. Chairman, Sir, I will just quote only two points.

On 12th March, 2004, it was mentioned by the then Opposition that Aadhaar programme was a fraud perpetrated on the people. So, you are using that fraudulent system today. You only said that. We did not say that. I do not want to name which spokesperson had mentioned. You said this Aadhaar programme, which was brought by the UPA, is a fraud and it is a useless system; and Aadhaar cards are given to illegal residents over here. At least, we are giving it to illegal residents but now you are taking away the citizenship of the legal residents in this country, and that is what your CAA is doing.

You talked about the Direct Benefit Transfer scheme. Who has done this? …(*Interruptions*) I will finish it. You can interfere later.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI ANURAG SINGH THAKUR): He has made a wrong statement. The CAA does not take away anyone's citizenship. So, I think that should be taken away because that

is not related to the Budget, and CAA does not take away anyone's citizenship. Sir, so, I want you to correct him.

DR. K. JAYAKUMAR (TIRUVALLUR): I did not say that.

HON. CHAIRPERSON (SHRI N. K. PREMACHANDRAN): Please wait. That is only his personal observation which he feels and apprehends so.

DR. K. JAYAKUMAR (TIRUVALLUR): So, the BJP has said-- and again the hon. Finance Minister may note--that Direct Benefit Transfer is not a gamechanger. But now you will say it is a gamechanger.

HON. CHAIRPERSON: Jayakumar Ji, now you please conclude.

DR. K. JAYAKUMAR (TIRUVALLUR): Please give me two minutes' time.

HON. CHAIRPERSON: Your time is already over.

DR. K. JAYAKUMAR (TIRUVALLUR): Sir, what I am trying to say is that the Finance Minister was kind enough to mention that a Prime Minister was there and that Prime Minister said only 15 per cent of the benefits reach the people and 85 per cent goes in the drain, and therefore, that Prime Minister started this system to see that the benefits reach the people. The Finance Minister was feeling shy on that day to mention the name of that Prime Minister and that Prime Minister is Rajiv Gandhi Ji who has given his life for this country's sake. It is bad that his name was not mentioned in this Budget. When you talk about any online system in the country, he is the person who has connected India online with the world and brought a scientific temper to this country. None other than that is responsible for it.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

DR. K. JAYAKUMAR (TIRUVALLUR): Sir, I have only one point to make. You will agree with me. I want to mention about disinvestment. What is this Government going up with? Why are you going in for disinvestment? You do not have money. You are bankrupt. You do not have money to spend.

HON. CHAIRPERSON: Now, Shri Anubhav Mohanty.

DR. K. JAYAKUMAR (TIRUVALLUR): You are disinvesting to spend money. Otherwise, you will not go for the LIC. The Congress Government also did it but we were selling sick industries. We were selling breadmaking companies. The Government's duty was not to make bread. But here you are going to sell LIC, a company which is making crores and crores of rupees. Rs.14,000 crore is the

profit of that company today, and you are selling that company. What is the reason to sell this company? I will tell you the reason.

HON. CHAIRPERSON: Please do not explain all this.

DR. K. JAYAKUMAR (TIRUVALLUR): It is because the private parties are going to take part in it and in the later phase, it will slip into the hands of the private parties, and that is an illegal means that you are trying to do.

HON. CHAIRPERSON: Jayakumar Ji, if you can conclude, conclude it now.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: No, you are going further. Now, Shri Anubhav Mohanty.

… (*Interruptions*)

(1755/VR/MY)

HON. CHAIRPERSON: Anubhav, please hold for a second.

....(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: You please finish your speech with concluding remarks. You are going to talk about the new subject.

DR. K. JAYAKUMAR (TIRUVALLUR): It is going to give a spiralling effect to the economy. Your disinvestment will not help in the development of the economy. On the contrary, the disinvestment of Railways and other Public Sector Undertakings will affect about 1.3 million employees, who are there. *....(Interruptions)* What solution are you giving to the employees? *....(Interruptions)*

(ends)

1756 बजे

श्री अनुभव मोहंती (केन्द्रपाड़ा): सर, लोक सभा में आने के बाद बजट में यह मेरा पहला पार्टिसपेशन है। मैं बीजू जनता दल से हूं और जो भी बोलूंगा, वह बीजू जनता दल की तरफ से बोलूंगा। Till today, the Biju Janta Dal (BJD) has been an example for all. जब भी कोई सरकार केन्द्र में रही है, अगर कोई अच्छी चीज आई हो, अच्छा बिल आया हो, अच्छा बजट प्रस्तुत पेश किया गया हो तो हमने उनकी सराहना की है। लेकिन जब कभी भी कोई लूपहोल्स रहा हैं या किसी सेक्टर को गवर्नमेंट ने इग्नोर किया है तो हमने उनको वह चीज भी बतायी है।

सर, जब राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को ऐड्रेस किया गया था और आज भी जब बजट पर डिस्कशन हो रहा था तो हमारे सीनियर श्री महताब जी ने बजट के ऊपर कुछ अच्छा भी कहा था। मैं उनकी तरह अच्छा बोल नहीं पाऊंगा, but whatever I speak will be from my heart and will be genuine, and I hope these are the points which hardly any Member would have touched upon in this Session. Sir, I will request you to give me a little more time.

Sir, the current limit for loans by banks for studying abroad is Rs.7.5 lakh which is nowhere close to the cost of the education. The high education costs are making it hard for students to pursue higher studies in good colleges both in India and in foreign Universities.

सर, हम एक ऐसे देश में रहते हैं, जहां पर एजुकेशन लोन पर इंट्रेस्ट बहुत ही ज्यादा होता है। अगर हम इसको कार लोन से कम्पेयर करें तो कार लोन का इंट्रेस्ट उससे कम है। उसके साथ ही लाखों डिस्काउन्ट्स भी मिलते हैं। When education is considered to be the backbone, if you want to be a developed country and the intention is genuine, I would request the Government that the interest on education loan should be the lowest in comparison to any other loans in India. अगर उसे जीरो करें तो और भी अच्छी बात है। अगर एजुकेशन लोन को इंट्रेस्ट फ्री किया जाए तो अच्छी बात है।

My next point is related to farmers. The farmers, who have been identified by Pradhan Mantri Kisan Scheme or any other scheme by different States, I would request that the Government should exempt them from road toll tax. मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि किसानों को पूरे भारत में रोड टोल टैक्स से फ्री किया जाए because they feed our nation. They themselves are unable to meet basic necessities of life. Taxing them is against the ethics and moral principles of our country's rich culture and conscience.

HON. CHAIRPERSON: Anubhav ji, please be seated. The hon. Minister wants to make an intervention.

सदन का समय बढ़ाए जाने के संबंध में

1758 बजे

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): चेयरमैन सर, अभी कई स्पीकर्स बोलने वाले हैं, इसलिए मेरा अनुरोध है और अगर हाउस एग्री करें तो 9 बजे तक हाउस का समय बढ़ा दिया जाए।

HON. CHAIRPERSON: I want to say that we have to conclude the discussion on the Union Budget by today because the hon. Minister has to reply on it tomorrow. If the House agrees, we will extend the time up to 9 o'clock. After that, we will see whether it needs to be extended further. Suppose, there is no speaker left to speak on the Union Budget, then we need not have to extend the time further. For the time being, it will be extended up to 9 pm.

GENERAL BUDGET – GENERAL DISCUSSION – Contd.

SHRI ANUBHAV MOHANTY (KENDRAPARA): Thank you very much, Sir. As time of the House is extended, I feel I will get some more benefit out of it. *....(Interruptions)*

Sir, a study has revealed that more than 71 per cent of senior citizens in our country face harassment and humiliation by their own family members, relatives or children. गवर्नमेंट ने सीनियर सिटीजन्स को प्रोटेक्शन देने के लिए तथा उनके सेफगार्ड के लिए बहुत सारे लॉज लाए हैं। But I want to propose that senior citizens clubs should be there in every single district of India where we can provide them lifetime membership for indoor and outdoor games, auditorium for their events, entertainment zone, lawns, fitness zone, old age friendly restaurants and doctors available for 24 hours a day.

(1800/SAN/CP)

Sir, they must also be provided the facility of *tirth yatras* at State expenses, like our Government at State level in Odisha does. I will speak in Oriya a few lines in-between my entire speech.

*[Sir, Odisha Government has a scheme for pilgrimage of senior citizens. The Government of Odisha provides the facility for senior citizens in the age group 60-75 years.]

This facility can be availed of by senior citizens in the age group 60-75 years. While the pilgrims from Below Poverty Line, BPL, categories can avail of one hundred per cent concessions under the scheme, the non-BPL pilgrims, except income tax payees, in the age group 60-70 years, can avail of 50 per cent concessions and those above 70 and up to 75 years can get 70 per cent concession.

In this year's Budget, there is no provision or no special allocation for animals, apart from cattle, specifically provided. There must be separate Budget allocated for the upgradation of veterinary hospitals all over India. There must also be provided encouragement to veterinary doctors by enhancing their pay-scales and other benefits so that they are encouraged to pursue this noble profession with zeal.

---

* Original in Odiya

Sir, inclusion of OBCs in Census 2021 must be done on priority by the Government as my Party, BJD, and my leader, Shri Naveen Patnaik, have always been saying that the census should reflect a definite population in India and the Government should allocate Budget for their development and bring them into the mainstream of the country. This has been a long-standing demand of the State Government of Odisha and I would request the Government to consider this.

Sir, I am from film fraternity. यह एक बहुत जरूरी मुद्दा है, जो मैं केंद्र सरकार को यहां बताना चाहूंगा कि फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ बॉलीवुड, टॉलीवुड या मॉलीवुड को नहीं बोला जाता है। There are so many regional film industries जिन फिल्म इंडस्ट्रीज़ में एक फिल्म को बनाने के लिए 1 करोड़ रुपये भी बहुत ज्यादा होते हैं। So, GST and other taxes have become a burden on these industries. यह इंडस्ट्री शट-डाउन होने की कगार पर है। So, I request the hon. Finance Minister to completely remove the GST on regional film industries. At the same time, India is rich in art and culture, and is having technicians and artistes, जो अपनी पूरी जिंदगी को डेडीकेट करते हैं, सैक्रीफाइस करते हैं, दूसरों के एंटरटेनमेंट के लिए, दूसरों को हंसाने के लिए, दूसरों के माइंडसेट को थोड़ा सा रिलैक्सेशन देने के लिए। मैं चाहूंगा, यह सरकार भी जानती होगी और वे मानेंगे कि ऐसे बहुत कलाकार हैं, बहुत से टेक्नीशियंस पूरे भारत में हैं, जो भुखमरी से मरते हैं। They die out of hunger. उनके पास कुछ खाने के लिए पैसा नहीं होता है। इंडिया में ऐसा भी इन्स्टैंस है कि बहुत मुश्किल से अगर उनका परिवार कुछ पैसा इकट्ठा करके उनको अस्पताल में भर्ती कराते हैं, ट्रीटमेंट कराने की कोशिश करते हैं और अगर वे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के दौरान गुजर जाते हैं, तो उनकी डेडबॉडी को भी फ्री करके वहां से लाने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं। So, the Government must have a special Budget for payment of pension to these artistes and these technicians who have sacrificed their entire lives to entertain us and to give a smile on our faces.

Sir, Odisha is known for its susceptibility to recurring cyclones and natural calamities almost every single year. मैंने कुछ दिन पहले भी इसके बारे में बोला था that building resilient electricity transmission and distribution network in the coastal belts of Odisha will help in avoiding the recurring cost of re-building such damaged infrastructure due to such calamities.

*[Sir, our Party BJD under the able leadership of Shri Naveen Patnaik has been demanding a special category status. We were not given any such status by the NITI Aayog. Later on also, we kept on demanding and we have been

* Original in Odiya

requesting the Central Government to accord to such status to the State of Odisha.]

Now, our demand is for a special focus State status and we are not begging for this status life-long. ओडिशा को सिर्फ तीन साल स्पेशल फोकस स्टेट स्टेटस दिया जाए और हम पूरे देश को दिखा देंगे कि ओडिशा पूरे भारत में एक नंबर राज्य है। हमारी क्षमता उतनी है। पिछले सालों में हमने दिखाया है कि किस तरह से, किस ढंग से हमने हॉकी वर्ल्ड कप को होस्ट किया, किस तरह से एशियन गेम्स को होस्ट किया। आज इंडियन हॉकी टीम के सीने पर ओडिशा लिखा हुआ है, तो ओडिशा का एक सिटिजन होने के नाते मुझे इस चीज को लेकर गर्व होता है। मेरी इतनी ही रिक्वैस्ट है कि गवर्नमेंट इसको कंसिडर करे, हर बार की तरह इस बार इग्नोर न करे।

(1805/NK/RBN)

It is because our demands are very genuine. We are not begging before anyone. Railway projects meant for Odisha are pending for a very long time. There are no new railway projects for railway connectivity in Odisha apart from the Gopalpur-Sambalpur project. This Budget has disappointed us a lot. इस बार कोई नया रेलवे प्रोजेक्ट सैंक्शन नहीं हुआ है, जबकि हमारी डिमांड थी पुरी-कोर्नाक, बरगढ़-नुआपाड़ा, जाजपुर-अरडी धामरा, चकुलिया-बुरामारा, गुनपुर-थरुबली *[Sir, not a single railway line has been announced for Odisha this year. In my own constituency Kendrapara also, people are yet to get the services of the Railways even after so many years of Independence. Hon. Minister of Railways had promised us that by February 2020 railway line will be commissioned for my area and trains will run. Through you, I would like to request the hon. Finance Minister to kindly complete the work of long-pending railway lines. The State Government is providing free land and is prepared to bear fifty per cent of the expenditure. Despite all these, if the requisite work does not get completed, it is a matter of great regret.]

I would request you to please do it. Mobile network connectivity and bank services are some of the things on which I would like to speak. …(*Interruptions*) Two more points and I will conclude.

HON. CHAIRPERSON (SHRI N.K. PREMACHANDRAN): You please put your demands and conclude.

SHRI ANUBHAV MOHANTY (KENDRAPARA): I will make just two demands.

---

* Original in Odiya

I would also like to propose setting up of universities for the paramedics. There must be proper training of all paramedics for the use of equipment for MRI, CT scan, x-ray, blood test, and many such examinations that are done before, in-between the doctor's treatment or even after the treatment. This shall ease the work of doctors. हमारे देश में डॉक्टर के नम्बर की समस्या है, उसको यह बहुत मायने में कम करेगा।

HON. CHAIRPERSON: No explanation please.

SHRI ANUBHAV MOHANTY (KENDRAPARA): So, I request you to kindly consider this request and let Odisha be the first place to have such university or training centre at the national level.

My last point is this. मुझसे सारे एमपी एकमत होंगे, जब हम एमपीलैड की बात करते हैं, When it comes to MPLADS funds, since 2011 It has been stalled at Rs. 5 crore per year. On top of it, there are many other things in that, like the GST.If I cite my own example, I represent seven Assembly constituencies. पांच करोड़ रुपये अगर मैं हर असेम्बली में इक्विली बांटू तो भी एक करोड़ रुपये नहीं होता है। That MPLADS funds cannot be spent properly. There is no infrastructural development which can really serve the people. So, I would request and urge upon the Government to kindly consider this long-term demand. I believe all MPs will agree with me on this.

I will conclude by making a mention about the MSMEs. एमएसएमई के अंदर जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं, उसमें लैंड इडको की तरफ से देते हैं या कोई गवर्नमेंट आर्गेनाइजेशन की तरफ लीज पर लोन देते हैं। अगर लीज से आगे बढ़कर गवर्नमेंट उसको फ्री-होल्ड दे तो उनके लिए बहुत ही अच्छी सुविधा हो जाएगी। यह ज्यादा लोन लाने और उसको एक्सपैंड करने के लिए होगा, इस फ्यूचर जेनरेशन की फैमिली इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करती है। इसके ऊपर इम्पलायमेंट डिपेंड करता है, एक राज्य या एक देश डिपेंड करता है, उसके लिए सुविधा हो जाएगी।

I request the Government to kindly think of it. एक क्राइटेरिया को रखिए, कुछ पाइंट्स रखिए, दस सालों से जो इंडस्ट्री अच्छा रेवेन्यू जेनरेट कर रही है, अच्छा इम्पायमेंट दे रही है, उसको फ्री-होल्ड लैंड दी जाए। This would be a great help. Thank you for giving me this opportunity to speak on the Budget.

(ends)

1809 बजे

श्री अर्जुन सिंह (बैरकपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। मैं सबसे पहले माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। माननीय प्रधान मंत्री जी के मार्गदर्शन मे वित्त मंत्री जी ने जिस तरह से देश के गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, पिछड़ा वर्ग, छोटे और मंझोले व्यापारी को ध्यान में रखकर बजट बनाया है। दुध, मत्स्यपालन और पशुपालन के क्षेत्र में एक संतुलित बजट लाने की कोशिश की गई है जोकि वर्ष 2020-21 में भारतवर्ष के लोगों के लिए सुविधा लाएगी।

मैं एक बात कहना चाहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। एक अजीब माहौल देश के अंदर बनाने की कोशिश की जा रही है। हर दूसरे व्यक्ति के सामने यह बात लायी जाती है कि भारतवर्ष में मार्केट की अवस्था बहुत खराब है, बिजनेस चौपट हो गया है, धंधा खराब हो गया है। पिछली सरकार के पाप को इस सरकार को धोना पड़ रहा है।

(1810/SK/SM)

पिछली सरकार ने पाप किए, जिनकी औकात नहीं है दस रुपए लोन लेने की, उनको सौ-सौ करोड़ रुपये का लोन मिल गया, दो-दो सौ करोड़ रुपये का लोन मिल गया। सौ करोड़ की फैक्ट्री लगाने की जगह 400 करोड़ रुपये का लोन लिया और आज स्थिति यह है कि वह लोन चुकाने की स्थिति में नहीं हैं। कारखाने बंद हो गए और कारखानों में लोगों को काम नहीं मिल रहा है। उनका जो पाप 32 साल का है, मिली जुली सरकार का पाप हम लोगों को देखना पड़ा रहा है कि जहां भी जाइए, हर समय इस तरह का वातावरण दिखाई देता है।

सुबह चर्चा हो रही थी कि इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्रों की संख्या कम हो रही है, छात्र नहीं जा रहे हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है, मैं बंगाल से आता हूं। बंगाल की स्थिति यह है कि पिछले नौ-दस साल से घर में ही इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया है। दस कम्प्यूटर लगा दिए और उसे इंजीनियरिंग कॉलेज की मान्यता मिल गई, कोटा मिल गया, सर्टिफिकेट मिल गया। इस तरह की व्यवस्था पिछली सरकारों ने की है कि जिस कॉलेज का दिल्ली में नाम भी नहीं है, एक वहां के सांसद हैं, उन्होंने वहां से सर्टिफिकेट लेकर इलैक्शन के लिए एफिडेविट दिया है कि उन्होंने एमबीए किया है। इस तरह का एक चक्र चल रहा है। इसके अगेंस्ट मामला भी हुआ है, वर्तमान में यहां सांसद भी हैं। उनके अगेंस्ट दिल्ली में कोर्ट में मामला चल रहा है।

मैं पश्चिम बंगाल से आया हूं। इसे किसी जमाने में जूट उद्योग का मेनचेस्टर कहा जाता था। माननीय प्रधान मंत्री जी ने यूएन के पटल पर विश्व को संबोधित करते हुए भारत को प्लास्टिक मुक्त बनाने में अग्रणी भूमिका निभाने की बात कही थी। पहले मार्क्सवादियों की सरकार थी, अब यहां तृणमूल सरकार है। पश्चिम बंगाल में जूट मिलों की स्थिति यह है कि जूट के लिए एक शब्द सोचना भी इनके लिए गुनाह है। भारत सरकार सारे जूट प्रोडक्ट खरीद रही है। राज्य सरकार की तरफ से कोई सहयोग न मिलने की वजह से पीएफ, ग्रेच्युटी, ईएसआई इतना डिफॉल्टर है कि कर्मचारियों की सिर्फ ग्रेच्युटी का ही 200 करोड़ रुपया बाकी है। पीएफ में वर्कर का पैसा काट लिया जाता है लेकिन जमा नहीं होता है। ईएसआई का पैसा जमा नहीं होता है। ईएसआई में करोड़ों अरबों रुपया है लेकिन

राज्य में मालिक बनकर राज्य सरकार बैठी है। अस्पताल में चले जाइए, अगर आज पैर टूट गया है तो दस दिन बाद एक्स-रे होगा क्योंकि डॉक्टर नहीं हैं। इसकी देखरेख राज्य सरकार का लेबर डिपार्टमेंट करता है। जूट उद्योग से लोग पलायन कर रहे हैं, जबकि यहां जूट उद्योग अच्छा चल सकता है।

कुछ वर्ष पहले भारत का जूट उद्योग विश्व रैंकिंग में अव्वल था, जबकि आज बांग्ला देश है। छोटा सा देश हमें टक्कर दे रहा है। सारा एक्सपोर्ट का काम बांग्लादेश कर रहा है क्योंकि वहां लेबर कम्पोनेंट सस्ता है, पीएफ, ईएसआई का कोई झमेला नहीं है। मैं माननीय वित्त मंत्री से कहूंगा कि जो जूट उद्योग को आर्डर देता है, वहां से जिस पैसे की पेमेंट होती है, पीएफ और ग्रेच्युटी डायरेक्ट वर्करों को दी जाए, जिनकी बकाया है। माननीय प्रधान मंत्री जी कपड़ा ट्रस्ट में गए थे, इसका नामकरण भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर किया था। उन्होंने 500 करोड़ रुपये पेंशन के खाते में दिये ताकि जो पुराने लोग हैं उनको पेंशन दी जाए। बंगाल के जूट उद्योग में अगर डायरेक्ट पैसा काटकर श्रमिकों को दिया जाए तो वहां के श्रमिक बच जाएंगे, इंडस्ट्री बच जाएगी। जूट उद्योग ऐसा उद्योग है जिसमें 40 परसेंट श्रमिकों की कमी है, क्योंकि जूट मिल में लोग काम करने नहीं जाते हैं।

(1815/MK/SPR)

पश्चिम बंगाल की सरकार के बारे में मैं क्या बताऊं, यहां पर हमारे प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने इस बार मत्स्य उत्पादन में बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। बंगाल में सबसे ज्यादा लोग मछली खाते हैं, बंगाल में सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन होना चाहिए, लेकिन सारा तालाब इन लोगों ने भर कर बेच दिया।

मैं रेलवे की बात करना चाहता हूं। मेरा एक प्वाइंट है। मैं बैरकपुर से आता हूं। हमारे बगल में माननीय सांसद सौगत राय जी हैं, इनके तीन विधान सभा क्षेत्र पड़ते हैं। जब केंद्र में टीएमसी के रेल मंत्री थे, उसी समय से दक्षिणेश्वर-बैरकपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए दो हजार साठ करोड़ रुपये पड़े हुए हैं, लेकिन आज तक राज्य की सरकार ने जमीन नहीं दी, जिसके कारण वह मेट्रो रेल प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पा रहा है। …(व्यवधान) वहां पर जिस तरह से ये लोग रेलवे की जमीनों को पब्लिसिटी करके ऐड दे रहे हैं और बोल रहे हैं इसमें पट्टा देंगे, लेकिन रोहिंग्या को लाकर बसाया जा रहा है। वहां रेलवे की जमीनों को, केंद्र सरकार की जमीनों को, राज्य सरकार एडवर्टाइजमेंट देकर बेच रही है।

माननीय सभापति (श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन): अब समाप्त कीजिए।

श्री अर्जुन सिंह (बैरकपुर): बजट में जिस प्रकार से एक भावना बनाकर लोगों को बरगलाया जा रहा है, पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है, मैं मोदी जी को धन्यवाद दूंगा और एक बात कह कर अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं –

“हयात ले के चलो, कायनात ले के चलो,
चलो तो सारे जमाने को साथ ले के चलो।”

(इति)

1817 बजे

SHRI M. SELVARAJ (NAGAPATTINAM):

{For English translation of the speech
made by the hon. Member,
Shri M. Selvaraj in Tamil,
please see the Supplement. (PP 458A to 458D)}

1826 बजे

श्री प्रिंस राज (समस्तीपुर): सभापति जी, आज आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सबसे पहले मैं आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा बजट प्रस्तुत किया है। मैं इस बजट का स्वागत करता हूं और इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस बजट में किसान, शिक्षा प्रणाली, नए टैक्स स्लैब, ओबीसी, एससी और एसटी लोगों के लिए जो बजट एलोकेट किया गया है, वह बहुत ही सराहनीय है। नए भारत और मजबूत इकोनोमी के लिए जो फाउंडेशन तैयार की गई है, मुझे पूरा विश्वास है कि इससे बहुत मदद मिलेगी।

सर, हर साल जब बजट आता है, आम आदमी होने के नाते जब कोई टी.वी. खोलकर देखता है, तब उसकी नजर ज्यादातर एक चीज पर होती है कि जितनी हमारी आमदनी है, उस पर कितना टैक्स देना होगा। यह हमारे लिए एक एस्पिरेशन है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने इतनी देर खड़े होकर पूरा बजट पढ़ा, लेकिन आम पब्लिक यह देखती है कि हम जितना कमा रहे हैं, हमसे कितना टैक्स लिया जाएगा।

इस बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, जो नया टैक्स रिजीम लाया गया है, वह बहुत ही स्वागत योग्य है। इसमें पहले पांच लाख रुपये के ऊपर व्यक्ति की इनकम पर 20 प्रतिशत टैक्स देना पड़ता था, उसे अब पांच लाख रुपये से साढ़े सात लाख रुपये की स्लैब में घटाकर दस प्रतिशत किया गया है। इसी प्रकार से साढ़े सात लाख रुपये से दस लाख रुपये की स्लैब में 15 प्रतिशत टैक्स किया गया है। इस सरकार की जो नीयत है, जो सोच है, वह यह है कि जितने भी टैक्सपेयर्स हैं, उनकी जेब में ज्यादा से ज्यादा पैसा जाए, वे ज्यादा से ज्यादा खर्च कर सकें। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं।

साथ ही, जिस तरीके से किसानों के बारे में इस बजट में बातें की गई हैं, सोलर पावर का जो नया युग आया है, इसमें 20 लाख किसानों को डायरेक्ट सोलर पैनल के थ्रू बिजली मुहैया कराने से, उनको सिंचाई में जो मदद मिलेगी, वह सराहनीय है। सरकार ऐसे 15 लाख किसानों को पावर ग्रिड एस्टैबलिश करने के लिए जो मदद करेगी, वह सराहनीय है, ताकि वे अपनी खेती करें। साथ ही जो बिजली उत्पादित होगी, उसे आस-पास के जिलों में भेज सकें और उससे भी उनकी कमाई हो सके। सरकार हमेशा यह बात करती है कि जितनी भी आमदनी एक किसान की होती है, उसे डबल किया जा सके।

(1830/IND/SNT)

हमारे विपक्ष के साथी इस बारे में काफी सवाल उठाते हैं, लेकिन यह सोचने की बात है कि कम से कम यह सरकार ऐसा सोचने का साहस रखती है कि हमारे किसान भाइयों की आमदनी डबल हो। जब किसान ऐसी चीजों का उत्पादन करता है, जैसे दूध या कुछ भी हो, उससे किसान को बचाने के लिए सरकार ने 'किसान रेल' और 'कृषि उड़ान' जैसे प्रावधान किए हैं, जिससे जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं को जल्द से जल्द मार्केट में पहुंचाया जा सके।

इस सरकार ने बजट में शिक्षा प्रणाली पर बहुत जोर दिया है। जिस तरह से एजुकेशन रिफार्म की बात हुई है, वह बहुत ही सराहनीय है। बजट में कहा गया कि 150 के करीब हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स खोले जाएंगे, जो कि एपरेंटिस एम्बेडेड होंगे, ताकि कोई पढ़ाई खत्म करने के बाद नौकरी के लिए जाए या अपना बिजनेस करे, तो वह ऑलरेडी उस व्यवस्था के लिए तैयार होगा। जब हम एजुकेशन रिफार्म की बात करते हैं तो यह केवल हायर एजुकेशन तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह प्राइमरी लेवल से होना चाहिए। जिस तरह से हम एक बच्चे को शिक्षा देते आए हैं कि बच्चा पढ़ रहा है, वह उसे रट्टा लगा लेता है और एग्जाम देता है। हमें इस व्यवस्था को बदलना है ताकि बच्चे इंडिपेंडेंट हो सकें और उनका अच्छे से अच्छे व्यवसाय में चयन हो सके। आप कई उदाहरण देख सकते हैं कि जो बच्चे पढ़ाई के क्षेत्र में अव्वल नहीं होते हैं, लेकिन वे अन्य क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम कर जाते हैं। ऐसे बच्चों को चिह्नित किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि अच्छे ट्रेंड टीचर्स की नियुक्ति हो, ताकि ऐसे बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके।

महोदय, सदन में युवा राज्य वित्त मंत्री जी मौजूद हैं। हम इनसे आग्रह करेंगे कि इनके पास भी युवाओं की कई समस्याएं आती होंगी। इन्होंने युवाओं के लिए बजट भी रखा है। हम इनसे आग्रह करेंगे कि एक युवा आयोग का गठन हो, ताकि वह सुनिश्चित कर सके कि जब पढ़ लिखकर नौजवान अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं, तब उन्हें इस तरह की काउंसलिंग मिल सके कि उन्हें रोजगार मिल सके, उनको बिजनेस सेट करने में सहायता मिले या किसी अन्य फील्ड में जाना है, तो वह आयोग उनकी मदद करे।

महोदय, आयुष्मान योजना के तहत सरकार पांच लाख रुपये का फ्री इलाज देती है। साथ ही इस बजट में हर डिस्ट्रिक्ट में नए अस्पताल का प्रावधान रखा गया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह बात अच्छी है कि हर जिले में अस्पताल होना चाहिए, लेकिन अभी जितनी भी डिस्पेंसरीज या अस्पताल हैं, उनमें डाक्टर्स का अभाव है। हम आग्रह करेंगे कि डाक्टर्स की पर्याप्त संख्या हो। पांच ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा गया है और यह बहुत सराहनीय है। हम सभी साथियों से आग्रह करेंगे कि इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जैसा अभी हमारे विपक्ष के साथी बोल रहे थे कि देश पांच ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनेगा। हमारी सरकार इस काम को करने में सक्षम है, इसलिए कहती है कि हम पांच ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकते हैं। यदि किसी के मन में यह बात आ जाए कि हम पांच ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव नहीं कर सकते, तो उन्होंने तो पहले ही माइंड बना लिया है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपने जिस तरह से देश चलाया है, वैसे अब देश नहीं चल रहा है। आज आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है और हमें पूरा विश्वास है कि हम पांच ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव कर सकेंगे।

(1835/ASA/GM)

सर, मैं एक छोटी सी कहानी कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। यह कहानी एक बाप-बेटे की है। एक बाप-बेटा बहुत समय से पैदल चल रहे थे। एक गांव आया। गांव के लोगों ने कहा कि ये धूप में पैदल चल रहे हैं। कैसा बाप है, यह कोई घोड़ा क्यों नहीं ले लेता जिससे बेटे को बिठा दे? बाप ने घोड़ा लिया और बच्चे को उस पर बिठा दिया। फिर वे आगे बढ़े। लेकिन आगे जाकर एक गांव

आया। उस गांव के लोगों ने कहा कि यह कैसा बेटा है, बाप को पैदल चला रहा है और खुद घोड़े पर बैठा है। फिर बाप घोड़े पर बैठ गया। आगे एक और गांव आया। गांव वालों ने फिर कहा कि ये कैसे बाप बेटे हैं कि ये दोनों एक जानवर पर अत्याचार कर रहे हैं। दोनों उस जानवर पर चढ़कर बैठे हैं। फिर वे दोनों घोड़े से उतर गये। फिर आगे एक गांव आया। वहां के लोगों ने कहा कि ये कैसे बेवकूफ हैं कि घोड़ा साथ में है, लेकिन फिर भी दोनों पैदल चल रहे हैं। सर, कहने का मतलब यही है कि सरकार जो काम कर रही है, जो काम करना चाहती है, अच्छा कर रही है। अपोजीशन का काम कहना है, वे ये कहेंगे ही। उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। धन्यवाद।

(इति)

1836 बजे

डॉ. संघमित्रा मौर्या (बदायूं): माननीय सभापति जी, मैं वर्ष 2020-21 के बजट के संबंध में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत है। दिनांक 01 फरवरी 2020 को वित्तीय वर्ष 2020-21 का केन्द्रीय बजट देश के सामने पेश किया गया। 21वीं सदी के तीसरे दशक में इस बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने दीर्घकालीन प्रभाव वाले कई सुधारों की घोषणा की है जो प्रशंसनीय है। मैं हृदय की अनंत गहराइयों से इसकी प्रशंसा करती हूं। मैं माननीय प्रधान मंत्री और माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देती हूं।

जिस ग्रामीण परिवेश से मैं आती हूं, जहां पर मेरा बचपन बीता, निश्चित तौर से तमाम तरह की मूलभूत आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूं। लेकिन जो यह बजट आया है, यह बजट साबित करता है कि जिन सुविधाओं से मैं वंचित रही हूं, आने वाला युवा, आने वाला बच्चा, इन सुविधाओं से वंचित नहीं रहेगा, बल्कि उन्हें सही प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। इस बजट से देश के आम अल्प आय वाले परिवार, खास तौर से मध्यम वर्गीय परिवार और आम सभी जनमानस को समान रूप से सुविधाएं मिलेंगी। मैं एक बार दोबारा माननीय प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं जिन्होंने निचले तबके के लोगों को ऊपर के पायदान पर बैठे लोगों के समकक्ष लाने का अथक प्रयास किया है। इस बजट के मुख्य उद्देश्य- लघु अवधि, मध्यम अवधि और दीर्घ अवधि के उपयोगों के जरिये भारतीय अर्थव्यवस्था को ऊर्जावान बनाना है। केन्द्रीय बजट 2020-21 के बजट को मैं अगर एक लाइन में कहूं तो यह महत्वाकांक्षी भारत का बजट है। वह भारत जिसमें समाज के सभी वर्गों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा की पहुंच और रोजगार के बेहतर अवसर हैं ताकि उनके जीवन का स्तर ऊंचा और मजबूत हो सके।

वर्ष 2020 के इस केन्द्रीय बजट में सरकार द्वारा जिन नये प्रयोगों को किया जाना है, वह अर्थव्यवस्था के लिहाज से नि:संदेह सकारात्मक साबित होंगे। सभी के लिए आर्थिक विकास- यानी 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' हमारा परम ध्येय रहा है।

तमाम तरह के लोग टिप्पणियां करते हैं कि यह बजट जनता के हित में नहीं है और वे लोग टिप्पणी करते हैं जिन्होंने लम्बे समय तक इस देश पर राज किया, इस प्रधान मंत्री की कुर्सी को वे सुशोभित करते रहे लेकिन गरीबों, पिछड़ों का वोट लेने के अलावा उन्होंने उनके हित का कभी कोई कार्य नहीं किया। वे तो हम सब धन्य हैं जो वर्ष 2014 में आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी प्रधान मंत्री बनते हैं तो गरीबों, शोषितों, पिछड़ों और किसानों की चिंता करते हैं और उसी चिंता के कारण ही आज गरीबों, किसानों और जरूरतमंदों का हक उनको मिल रहा है।

यदि हम सिंचाई और ग्रामीण विकास को ध्यान में रखकर देखें तो हम देखते हैं कि हमारी सरकार ने गांवों और गरीबों पर विशेष ध्यान देने का काम किया है।

(1840/RAJ/RK)

निश्चित ही वह हमारे कृषक भाइयों को अनेक लाभ पहुंचाएगा। प्रधान मंत्री कुसुम योजना के तहत 20 लाख किसानों को सोलर पंप्स की सुविधा तथा साथ ही 15 लाख ग्रिड कनेक्शन पंप्स की सुविधा दिया जाना, डीजल और कैरोसिन से मुक्त, उसको समाप्त कर पंप सेट्स को सौर ऊर्जा से जोड़ कर

के किसानों के भार को कम करने का भी एक सराहनीय कार्य किया जा रहा है। कृषि सिंचाई और ग्रामीण विकास के लिए सोलह सूत्री कार्य योजना को लागू किया जाना, उसमें उक्त सोलह सूत्री कार्य योजना के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपये का आबंटन, कृषि सिंचाई और उससे संबंधित गतिविधियों के लिए 1.60 लाख करोड़ रुपये और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के लिए 1.23 लाख करोड़ रुपये की कार्य योजना का विस्तार दिया जाना, इसके साथ ही पीएम किसान लाभार्थियों के लिए केसीसी योजना के तहत लाने का प्रस्ताव नाबार्ड के पुनर्वित्त योजना को और अधिक विस्तार देना है।

जल संकट से जूझ रहे 100 जिलों के लिए वृहद् उपायों के प्रस्ताव पर ध्यान दिया जाना, सिंचाई के लिए वर्षा जल आधारित क्षेत्रों को एकीकृत खेती का विस्तार और गैर फसल मौसम में बहुस्तरीय फसल, मधुमक्खी पालन, सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना, आदि को स्थान दिया जाना शामिल है।

माननीय सभापति महोदय, पूर्व में जो प्रधान मंत्री रहे हैं, उन्होंने खुद स्वीकारा था कि वह एक रुपये देते हैं और जनता के खाते में 10 पैसे, 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन धन्य हैं, इस देश के यशस्वी प्रधान मंत्री, आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी, जो किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2000 रुपये देते हैं तो किसानों के खाते में 2000 रुपये, पूरे पैसे पहुंचते हैं। हमारा कोई किसान भाई यह नहीं कह सकता है कि उसे 1,999 रुपये मिले हैं, उसमें से एक रुपये की भी कटौती नहीं होती है, क्योंकि आदरणीय मोदी जी ने आदरणीय मोदी जी ने बीच से दलालों को हटा दिया है। वह सीधे-सीधे योजना का लाभ गरीबों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जो जरूरतमंद हैं, उन तक उनकी योजनाएं पहुंच रही हैं।

मत्स्य व्यवसाय हेतु समुद्री मत्स्य संसाधनों के विकास प्रबंध और संरक्षण के लिए फ्रेम वर्क, जिससे वर्ष 2022-23 तक देश में 200 लाख टन मत्स्य उत्पादन का लक्ष्य और 3,477 मित्रों और 500 मत्स्य पालन कृषक संगठनों द्वारा युवाओं को लाभकारी मत्स्य पालन के क्षेत्र में जोड़े जाने की योजना है।

स्वच्छता को लेकर प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 20 हजार अस्पतालों का जोड़ा जाना, 'टी.बी. हारेगा और देश जितेगा', कैम्पेन के तहत वर्ष 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य, हर जिले में जन औषधि केन्द्र खोला जाना, हमारी सरकार का 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' जैसे नारे को चरितार्थ करता है। आज तक किसानों और गरीबों की चिंता किसी ने नहीं की है, स्वास्थ्य की चिंता किसी ने नहीं की है। यदि गरीब मर रहे हैं तो मरते रहें, लेकिन आज हम सब धन्य हैं, जो इस देश के यशस्वी प्रधान मंत्री, आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी गरीबों की चिंता करके, उनके स्वास्थ्य की चिंता करके, आयुष्मान भारत योजना के तहत पांच लाख रुपये की सुविधा देने का काम कर रहे हैं।

आज विपक्ष शिक्षा और रोजगार की भी चर्चा करता है कि हमारी सरकार रोजगार नहीं दे रही है, शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रही है, बजट नहीं बना रही है। मैं कहना चाहूंगी कि आज जो सरकार शिक्षा और रोजगार की बात करती है, जो कहते हैं कि रोजगार और शिक्षा नहीं मिल रही है, जब हम दिल्ली

के चुनाव के दौरान गए तो देखा कि जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताब और पैन होना चाहिए, उस उम्र के बच्चों को सीएए के विरोध में सड़क पर तख्ती और मोमबत्ती पकड़ा कर खड़ा किया गया है, लेकिन उन बच्चों को यह भी नहीं पता है कि सीएए क्या होता है। पांच-छ: साल के बच्चे जिनके हाथ में हमें किताब और कलम पकड़ानी चाहिए, उनके हाथ में तख्ती और मोमबत्ती पकड़ा कर सड़क के किनारे खड़े करते हैं और हम यहां पर रोजगार और शिक्षा की बात करते हैं।

आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय वित्त मंत्री जी के नेतृत्व में, निश्चित तौर पर यह देश बदल रहा है, उन्होंने देश के लिए बहुत अच्छा बजट लाया है। मैं चार लाइनें कह कर अपनी बात को विराम दूंगी और साथ ही साथ सरकार से यह अनुरोध करूंगी, क्योंकि मैं एक ऐसे लोक सभा क्षेत्र से आती हूं जो आजादी के इतने लंबे समय के बाद भी आज भी बहुत पिछड़ा है। चाहे वह ट्रेन हो, बस हो या रोजगार हो, हमारा क्षेत्र हर चीज से दूर है और हम चाहेंगे कि सरकार उन क्षेत्रों पर नजर रखे। मैं चार पंक्तियों के साथ अपनी बात को विराम दूंगी।

(1845/VB/PS)

गरीबों की आन-बान-शान और सम्मान हैं हमारे मोदी जी,
देश को जिसने दिया शानदार बजट, वो हैं हमारे मोदी जी,
जाति-धर्म से मुक्त होकर सबको एक जैसा लाभ दिया,
भारतवर्षी होने का गौरव हैं और स्वाभिमान हैं हमारे मोदी जी।

(इति)

1845 बजे

श्री राम शिरोमणि (श्रावस्ती): माननीय सभापति जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान बेरोजगारी और बढ़ती हुई आर्थिक मंदी की तरफ दिलाना चाहता हूँ, जिसका माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा बजट में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है तथा विश्व के सबसे अधिक युवा भारत में हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने दो करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वायदा किया था, लेकिन आज युवा लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। इसके बावजूद, बजट में बेरोजगारी दूर करने का कोई प्रावधान नहीं है। आज पूरा विश्व आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, जिसका प्रभाव भारत पर भी पड़ रहा है। इससे निपटने के लिए सरकार द्वारा कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया है।

बजट भाषण में उच्च शिक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु कोई चर्चा नहीं की गई है। विश्व के कई देश अपनी जीडीपी का छ:-सात प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करते हैं, लेकिन विश्व में सबसे अधिक युवाओं की जनसंख्या वाले भारत में जीडीपी का मात्र एक प्रतिशत ही शिक्षा पर खर्च करने का अवलोकन हो रहा है। सरकार से मेरी माँग है कि अन्य देशों की तरह शिक्षा की गुणवत्ता व सुगमता तथा सभी लोगों तक शिक्षा की पहुँच बनाने के लिए इसमें जीडीपी का खर्च और बढ़ाना चाहिए।

बजट भाषण में महिलाओं, दलितों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। बजट से आमजन, खास तौर पर मध्यम वर्ग एवं निम्न वर्ग, जिनको सबसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं, नौकरीपेशा तबके की निगाहें करों में रियायत पर होती हैं, लेकिन वर्ष 2020-21 के बजट में नई कर व्यवस्था का समावेश करते हुए, जिस तरह से दो नई कर व्यवस्थाएँ बना दी गई हैं, वे राहत देने की बजाय संकट ही खड़े करेंगी। लोगों को एक कर व्यवस्था को चुनकर उसी के हिसाब से कर का भुगतान करना पड़ेगा। करदाता वैसे ही परेशान होंगे जैसे जीएसटी से व्यापारी परेशान हो रहे हैं।

सरकार पैसे जुटाने के लिए एलआईसी व आईडीबीआई में हिस्सेदारी बेचेगी। यह सरकार की खराब आर्थिक स्थिति की ओर संकेत करता है।

खनन, ऊर्जा और रीअल एस्टेट जैसे प्रमुख क्षेत्रों को रफ्तार देने के लिए जिस तरह की उम्मीद बजट से थी, इससे कारोबारियों को निराशा ही हाथ लगी है। किसानों की आय बढ़ाने और खेती के संसाधनों में बढ़ोतरी का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

आजादी के 73 वर्ष बाद भी 58 से 60 प्रतिशत खेती में सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं हो पाई है, जो आज भी वर्षा पर निर्भर है। जो क्षेत्र सिंचित नहीं हैं, वहाँ पर प्रति हेक्टेयर औसतन 1.2 टन उत्पादन होता है, जबकि सिंचित क्षेत्र में लगभग चार टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है। आँकड़े बताते हैं कि 42 प्रतिशत गरीब ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहते हैं। इनको न तो उपयुक्त पोषण मिलता है, न ही तमाम वंचित किसानों तक पहुँचने के लिए किसी महत्वाकांक्षी योजना का जिक्र है और न ही इसके लिए सरकार द्वारा कोई विशेष आवंटन किया गया है।

वर्ष 2001 से अब तक हमारा व्यापार घाटा छ: अरब डॉलर से बढ़कर लगभग 176 अरब डॉलर हो गया है अर्थात यह 30 गुना हो चुका है। इससे निपटने के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यह बजट हवा-हवाई है, जैसे ऊँट के मुँह में जीरा।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

(1850/RC/PC)

1850 hours

SHRI MARGANI BHARAT (RAJAHMUNDRY): Sir, I thank you for giving me the opportunity to speak on the national Budget.

On behalf of my leader and hon. Chief Minister, Shri Y.S. Jaganmohan Reddy Garu, I congratulate the Central Government led by Shri Narendra Modi Ji. In the difficult times when the economy is sluggish and sentiment is weak, the hon. Finance Minister announced the first Budget of this decade and build confidence amongst the citizens of the country. But a lot of aspirations, expectations, thoughts, and hopes went in vain for the people of Andhra Pradesh.

I have no hesitation in saying that it is a double whammy for the State of Andhra Pradesh since there is no mention of Special Category Status, revenue deficit and industrial corridor which were promised and which were there in the AP Re-organisation Act. Neither in the President's Address nor in the Budget, it is there. It has disappointed the aspirations of five crore people.

I am deeply perplexed as to where I should start from. Should I start from the national Budget or should I start from the promises made in this noble House regarding the Andhra Pradesh Re-organisation Act? Our hon. Chief Minister, Shri Y.S. Jaganmohan Reddy Garu met the hon. Prime Minister and the hon. Home Minister many times for granting the Special Category Status, but the Central Government put forth the argument that in accordance with the recommendations of the 14th Finance Commission, the Special Category Status ceased to exist. The Ministry of Finance contended that at page no.17, para 2.29 and 2.30, the 14th Finance Commission stated that they had not taken into account any distinction between the special and general category States. Then why can the Special Category Status which was promised in this noble House not be given? At the time of bifurcation, it was promised.

A step further our State Government has requested the 15th Finance Commission to review the plea for granting of status. The Chairman and the members of the Commission were the most sympathetic towards the State of Andhra Pradesh. In a reply to a question asked by the media, the hon. Chairman, Shri N.K. Singh, stated that it was beyond the purview of the Finance Commission to consider recommending the grant of Special Category Status to

any State. But I would like to reiterate in this House that the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi Ji, mentioned that the Congress has killed the mother, *i.e.,* Andhra Pradesh and saved the baby, *i.e.,* Telangana. He further said that had he been there, he would have saved the mother also. Therefore, I would request the hon. Prime Minister to keep up his promises.

The hon. President has rightly said in his Address at para 78:

> "The fundamental mantra of Independence was a Self-reliant India. A self-reliant India is possible only when every Indian takes pride in every product made in India. My Government believes in the mantra of 'Buy local for a better tomorrow'. I urge every representative of the people, from Panchayat level to the Parliament, and every Government in the country, to transform the philosophy of 'Buy local for a better tomorrow' into a movement. I also urge every Indian to give priority to local products. By using locally manufactured products, you will be able to help the small entrepreneurs in your area to a great extent."

We appreciate the hon. Prime Minister and the Government for promoting 'Make-in-India' but in reality we have to deliver more efficiently.

Sir, give me two more minutes, I will conclude. There are a couple of points regarding tourism and about crude oil.

HON. CHAIRPERSON (SHRI N. K. PREMACHANDRAN): If you want to put more demands, kindly conclude with demands.

SHRI MARGANI BHARAT (RAJAHMUNDRY): Sir, instead of focussing and pushing the locally produced/manufactured goods we are screaming towards FDI. Sir, what do foreign direct investors do? They do not come to our country to do charity.

(1855/SNB/SPS)

They come here to earn profit and take them back in dollars. By converting one single dollar into rupee we are losing 70 times of our currency. The hon. Finance Minister mentioned in her Budget speech that FDI investments today got enhanced to 284 billion dollars from 190 billion dollars. Now, if the FDI goes up, how can rupee get stronger? How can we transform the philosophy of the Government `buy local for better tomorrow'? The hon. Finance Minister, in para

135 of her Budget speech, agreed that undue benefits given under the FDI is posing a threat to our domestic industry.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now. If you have any demands, you put them before the Government and conclude your speech. You are the third speaker from your party.

SHRI MARGANI BHARAT (RAJAHMUNDRY): Sir, please give me two minutes.

Sir, this august House is aware that this country has a foreign exchange reserve of 450 billion dollars. Instead of keeping that foreign exchange as a reserve can be used for productive purposes. We have a lot of scope and potential in the tourism sector.

HON. CHAIRPERSON: You are explaining things. Please conclude now.

SHRI MARGANI BHARAT (RAJAHMUNDRY): But unfortunately, the tourism sector has been given very less priority in this Budget. Smaller countries like Malaysia, Singapore, Mauritius, Maldives etc. are spending a lot on promotion of tourism. In fact, our country should pursue tourism aggressively for earning more foreign exchange through this sector.

The other point is this. Why is our GDP low? We all know that our country is a major importer of crude oil and the bullion. Why can we not implement the use of vehicles driven by natural gas? That has to be promoted. In fact, my constituency is located in the KG basin. Ten million cubic meters of gas is produced per day in the KG basin. …(*Interruptions*)

I want to conclude by making the demand that the special category status should be accorded to the State of Andhra Pradesh and whatever other promises were made in the Andhra Pradesh Reorganisation Act should be fulfilled. Also, I would like to mention that our hon. Chief Minister asked for a R&R package for the Polavaram project. Unless we get that R&R package, how can we construct the dam and store water? The R&R package for the Polavaram project has to be released at the earliest so that we have a means of survival for the people of Andhra Pradesh.

Thank you.

(ends)